हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 9 सितम्बर, 2024 को माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैंबर, शिमला-171004 में 02.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

09.09.2024/1400/डी0टी0/वाई0के0-1

अध्यक्ष : प्रश्न काल आरंभ।

प्रश्न संख्या : 2138

श्री रणधीर शर्मा (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नाबार्ड से संबंधित है। लोक निर्माण, जल शक्ति या अन्य विभागों द्वारा जो योजनाएं वित्त पोषण के लिए नाबार्ड को भेजी जाती है। इस प्रश्न में पिछले दो सालों में कितनी योजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत हुईं और कितनी विचाराधीन हैं, की विस्तृत जानकारी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। जो योजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत होती हैं उसमें यह व्यवस्था है कि जो डी.पी.आर. पहले भेजी जाती है उसे पहले स्वीकृत किया जाता है। विभागों द्वारा प्लानिंग डिपार्टमेंट को डी.पी.आर. भेजी जाती है और फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा उस डी.पी.आर. को नाबार्ड की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। जिस सिन्योरिटी में डी.पी.आर. भेजी जाती है उसी सिन्योरिटी में नाबार्ड द्वारा डी.पी.आर अप्रूव की जाती है। लेकिन इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद एक नई व्यवस्था शुरू की है। व्यवस्था परिवर्तन अच्छे के लिए है हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन यह व्यवस्था परिवर्तन इतनी (***) के साथ किया जा रहा है जिसका प्रदेश के आधे हिस्से को नुकसान हुआ है। पिछले साल सरकार ने नाबार्ड को नई लिस्ट भेजी Reprioritise of DPRs और उस लिस्ट में कांग्रेस विधायकों के विधान सभा क्षेत्र की ही योजनाओं के नाम हैं। जब हमने इस विषय में नाबार्ड में बात की तो वे कहते हैं जो हमें सरकार कहेगी हम वही करेंगे। नाबार्ड में पिछली बैठक में जितनी सड़कें स्वीकृति हुई हैं वह कहीं भी सिन्योरिटी के हिसाब से स्वीकृत नहीं हुई हैं। वे सारी सड़कें जिन विधान सभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक हैं वहां के लिए स्वीकृत हुईं। मैं इस विषय पर इसलिए गम्भीरता से बात कर रहा हूं कि नाबार्ड से कर्ज मिलता है और वह कर्जा प्रदेश सरकार वापिस करती है। इसलिए इसका व्यय भी प्रदेशव्यापी होना चाहिए। इसे आप मात्र 40 विधान सभा क्षेत्रों में खर्च करेंगे और 28 विधान सभा क्षेत्रों को बाहर रखेंगे, ये कहां का न्याय है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमें भी प्रदेश की जनता ने ही चुन कर भेजा है। आप बहुत-सी बातों में अन्याय करते हैं, भेदभाव करते हैं। जबसे नाबार्ड का गठन हुआ और नाबार्ड से पैसे लेने की प्रथा शुरू हुई है, जब से आर0आई0डी0एफ0 शुरू हुआ है, तभी से ये प्रथा चली आ रही है। इस सरकार ने इस प्रथा में बदलाव करके एक तरह से

अपनी (***) का परिचय दिया है और हमारे 28 विधान सभा क्षेत्रों के साथ अन्याय और भेदभाव किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री

(***) अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

09.09.2024/1400/डी0टी0/वाई0के0-2

जी से पूछना चाहूंगा कि ये जो प्रथा आपने शुरू की है जिसके कारण हमारे विधान सभा क्षेत्रों से संबंधित पांच-पांच साल पहले जो डी0पी0आर्ज0 नाबार्ड में गई थीं वे डीपी0आर्ज0 आज स्वीकृत नहीं हो रही और आपने जो सूची भेजी है उसमें तुरन्त, जिसकी डी0पी0आर0 नहीं भी थी, उसकी भी डी0पी0आर0 स्वीकृत हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो भेदभाव हुआ है, इस भेदभाव को दूर करेंगे; और दूसरा ये जो नई प्रथा शुरू की है इसको बंद करके जो पहले डी0पी0आर0 जाए वह पहले स्वीकृत हो। First come first get की प्रथा को लागू रखेंगे?

श्री एन0जी0द्वारा जारी

09-09-2024/1405/वाई.के.-एन.जी/1

प्रश्न संख्या - 2138.....जारी

श्री रणधीर शर्मा के पश्चात.....जारी

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसमें यह देखाना चाहिए कि सबसे ज्यादा 14 सड़कें सरकाघाट विधान सभा में स्वीकृत हुई हैं। झण्डुता, बिलासपुर व श्री नैना देवीजी विधान सभा में भी सड़कें स्वीकृत हुई हैं। श्री नैना देवीजी विधान सभा में 11 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों का समान विकास करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसमें कोई भी संकीर्ण मानसिकता की बात ही नहीं है। जिस भी क्षेत्र की डी.पी.आर. प्राप्त होती है हम उसे नाबार्ड में भेज देते हैं। माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि हर विधान सभा क्षेत्र के लिए 175 करोड़ रुपये फिक्स किए हुए हैं। उस 175 करोड़ रुपये के दायरे में जिनकी भी योजनाएं आएंगी उन्हें

हम प्राथमिकता के आधार पर भेजते हैं। जिन विधान क्षेत्रों का 175 करोड़ रुपये से ऊपर अमाऊंट चला जाता है तो उसमें भी हम कंसीडर करते हैं कि क्या उस क्षेत्र में सड़कों आदि को पैसा देना जरूरी है और वहां पर कितने लोग रहते हैं तथा इस दृष्टि से भी हम कार्य करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस बार हमने इसकी सीमा को 20 करोड़ रुपये बढ़ाया है। इन 20 करोड़ रुपये में हमने रख-रखाव व इलैक्ट्रिकल वाहनों का पैसा रखा है। क्योंकि 31-03-2026 तक हम प्रदेश को ग्रीन हिमाचल प्रदेश के रूप में विकसित करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि इलैक्ट्रिकल वाहनों के लिए जहां पर चार्जिंग स्टेशन लगने है या सड़कों के रख-रखाव करने के लिए माननीय विधायक अपनी-अपनी प्राथमिकता दें। इसके लिए हमने 20 करोड़ रुपये अतिरिक्त स्वीकृत किया है। यह अमाऊंट हर विधान सभा क्षेत्र के लिए फिक्स है। इस बारे में तो प्लानिंग की बैठक में भी बात हो चुकी है। हमने सभी विधान सभा क्षेत्रों में योजनाओं को स्वीकृत किया है।

09-09-2024/1405/वाई.के.-एन.जी/2

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि केवल दो विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर योजनाओं की स्वीकृति कम मिली है। उनमें से एक शिमला शहरी विधान सभा क्षेत्र है क्योंकि शिमला शहरी विधान क्षेत्र में नाबार्ड के माध्यम से स्वीकृत नहीं होती। दूसरा विधान सभा क्षेत्र डलहौजी है, जहां पर नाबार्ड की लिमिट पेंडिंग पड़ी है। **यदि वहां के विभाग भी हमें अपने कायों की डी.पी.आर. सरकार तक पहुंचाएंगे तो उनको स्वीकृति मिल जाएगी।** जिन विधान सभा क्षेत्रों की लिमिट पूरी हो जाती है तो उसके लिए हम देखते हैं कि वहां की योजनाओं को स्वीकृत करना है या नहीं। क्योंकि नाबार्ड से भी लिमिटिड लोन मिलता है। ऐसा नहीं है कि अनकंडिशनल लोन मिल जाता हो। हमने उस लोन को सभी विधान सभा क्षेत्रों में बराबर बांटा है।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय सदन व प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। श्री नैना देवीजी विधान सभा क्षेत्र में 11 सड़कें तो तब से स्वीकृत हुई हैं जब से नाबार्ड के माध्यम से सड़कों का निर्माण होना शुरू हुआ है। पिछले 3-4 साल से कोई भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई है। पिछले 5 साल से कटीरड़-पंगवाणा सड़क की डी.पी.आर. नाबार्ड में लम्बित पड़ी हुई है। मैंने पिछले सत्र में भी प्रश्न लगाया था तो उत्तर आया कि वह गायब हो गई और हमने दोबारा डी.पी.आर. भिजवाई हुई है तथा वह भी अभी तक स्वीकृत नहीं हुई। मुख्य मंत्री जी तो जबसे नाबार्ड चला है तब से लेकर अब तक की सड़कें बता रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 175 करोड़ रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 195 करोड़ रुपये किया गया है या नहीं? श्री नैना देवीजी विधान सभा क्षेत्र में तो 175 करोड़ रुपये की लिमिट भी पूरी नहीं हुई है। हमारी चार सड़कें पिछले साल से प्लानिंग विभाग में गई हुई हैं और उनमें से कोई भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई। यह जो अभी लेटेस्ट स्वीकृत हुई हैं इसमें एक भी विधान सभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें बीजेपी का विधायक हो। मैं इस लिस्ट को पढ़ कर भी सुना सकता हूं। इन्होंने जो reprioritize के लिए लिस्ट भेजी थी और जो स्वीकृत होने वाली लिस्ट है, दोनों में ही कोई भी विधान सभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें बीजेपी का विधायक हो।

09-09-2024/1405/वाई.के.-एन.जी/3

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी पुराना उत्तर देकर गुमराह करेंगे तो यह ठीक नहीं है। हमने मुख्य मंत्री जी से स्पेसिफिक पूछा है कि क्या आपने पत्र के माध्यम से प्लानिंग से नाबार्ड को लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत priorities को चेंज करने के लिए लिस्ट दी है? यदि दी है तो बताएं उसमें कौन-कौन से विधान सभा क्षेत्र शामिल हैं? इसके अलावा नाबार्ड की बैठक में जो लेटेस्ट सड़कें स्वीकृत हुई हैं, उनकी सूची भी दे दीजिए कि किस-किस विधान सभा क्षेत्र की सड़कें शामिल हैं? लिस्ट सामने आने के बाद सभी को सारी बात समझ में आ जाएगी और पिछला रिकॉर्ड छोड़ दें। यदि किसी विधान सभा क्षेत्र का नाम नहीं है और उसकी लिमिट 175 करोड़ रुपये से ऊपर हो गई है तब हम भी समझ जाएंगे।

मुख्य मंत्री जी, विस्तृत रिप्लाई दीजिए। इस प्रकार गुमराह करने से बात नहीं बनेगी। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार सरासर हमारे साथ अन्याय व भेदभाव कर रही है जिसको हम सहन नहीं करेंगे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो यही है कि क्या सरकार ने पिछले साल डी.पी.आर्ज़ को reprioritize करने की लिस्ट भेजी थी? यदि हां तो उसमें कौन-कौन से विधान सभा क्षेत्र शामिल थे? इसके अलावा नाबार्ड की बैठक में जो लेटेस्ट सड़कें स्वीकृत हुई हैं वे किस-किस विधान सभा क्षेत्र की हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अब माननीय सदस्य कुछ चीज़ पढ़े न तो मेरा क्या कसूर है? इसमें लिखा हुआ है और दिनांक 01-04-2022 से 31-07-2024 तक सारी सड़कों की लिस्ट दी हुई है।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

09.09.2024/1410/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्या : 2138 जारी---

मुख्य मंत्री जारी---

माननीय सदस्य जो नैना देवी के बारे में पूछ रहे हैं, (***) 175 करोड़ रुपये का कंटिन्यूटी प्रोसैस होता है। प्रत्येक साल बढ़ता है और ऐसी बातें कहना कि (***) है। इनको बोलने का ज्यादा शौक है, ये काफी अच्छा बोलते हैं लेकिन मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि हमने सारी सड़कों की 04.01.2023 से 31.07.2024 तक लिस्ट दी है। दो साल अभी हमारी सरकार को होने जा रहे हैं और अभी पीछे ही सातवां महीना खत्म हुआ है। जहां तक ये इनकी नाबार्ड की सड़क की बात कर रहे हैं, अगर आपका उस अमाउंट में पैसा रहता होगा तो उसको कर देंगे। अगर उसमें कोई प्रायोरिटीज़ भी हैं और किसी की प्रायोरिटी नहीं है, जिनकी भी डी.पी.आर्ज़ आ रही हैं, सरकाघाट के माननीय सदस्य ने तो कभी

बोला नहीं है क्योंकि उनकी सड़कें आ रही हैं, उनकी डी.पी.आर. बन कर आ रही है और हम उसको स्वीकृत करवा रहे हैं। किसी के साथ भेदभाव का मतलब ही नहीं है। हमारी सरकार किसी से भदभाव नहीं करती। अगर आपका अमाउंट बचता होगा,175 करोड़ रुपये में कुछ बचता होगा तो आपकी सड़क को भी उसमें डाल दिया जाएगा।

दूसरे, हमने आपको 20 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा दिए। 10 करोड़ रुपये मेंटिनेंस के और इलैक्ट्रिकल व्हीकल्ज़ के भी दिए। उन दोनों प्रोयोरिटीज़ में आप एक प्रायोरिटी और भी दे सकते हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने बोल तो दिया कि हम हिमाचल प्रदेश का समान विकास चाहते हैं। ...(व्यवधान) इन्होंने बोल तो दिया कि मेरी सरकार हिमाचल प्रदेश का समान विकास करवाना चाहती है। चलिए, लास्ट सप्लीमेंट्री श्री रणधीर शर्मा जी।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि , **(***)**

अध्यक्ष : ऐसा मत बोलो। सरकास्टिक वे में मत बोलो। इन्होंने कहा कि डिटेल्ड रिप्लाई दिया है।

(***) अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

09.09.2024/1410/केएस/एजी/2

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारी भी कोई इज्जत है। यह नहीं है कि हम पढ़कर नहीं आते लेकिन हम अनपढ़ भी हो सकते हैं। तब भी इनको हमारी बात का जवाब देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा है कि क्या सरकार के प्लानिंग विभाग ने नाबार्ड को एक सूची डी.पी.आर्ज़ को रीप्रायोरीटाइज़ करने के लिए भेजी है? अगर भेजी है तो वह यहां रखें। उसमें किस-किस विधान सभा क्षेत्र के नाम हैं, वह रखें। दूसरा, जो लेटेस्ट नाबार्ड की मीटिंग में इस चिट्ठी के जाने के बाद सड़कें स्वीकृत हुईं, वे किस-किस विधान सभा क्षेत्र की हुईं, वह सूची रखे दें। इतनी ही बात हम पूछ रहे हैं और ये उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं कि जहां अन्याय हुआ वहां न्याय करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं न मानूं वाली बात है इसमें मैं क्या कर सकता हूं। सूचना में हमने पूरा डिटेल दी है। अब ये बोल रहे हैं कि आपने चिट्ठी लिखी है या किस-किस विधान सभा के बारे में लिखी है? नाबार्ड से सरकार का पत्राचार चलता रहता है। सरकार के पत्राचार में कब कौन सी चिट्ठी लिखी है, एक साल पहले हमने क्या लिखा और एक साल बाद हमने क्या लिखा, उस पत्राचार के बारे में अगर आप किसी नियम के तहत, नियम-62 के तहत पूछेंगे तो हम पूरा बताएंगे। अभी तो जो प्रश्न किया है, उसके संदर्भ में जवाब दे रहे हैं और मैं बार-बार कह रहा हूं कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की 175 प्लस 20 करोड़ रुपये यानी 195 करोड़ रुपये की लिमिट है। उसमें जो भी सड़क आएगी, आपकी भी आएगी तो आपकी भी करेंगे। जब लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी तो नहीं होगी। यह तो स्पष्ट है और नाबार्ड से पत्राचार कोई एक बार नहीं होता। कई बार होता है। तीन महीने में, छः महीने में, कई बार होता है। कौन से पत्राचार में क्या लिखा है, वह हमारी आपस की बात है। अभी हम इलैक्ट्रिकल बसिज़ के लिए पत्राचार कर रहे हैं। अब नाबार्ड में जो एक लिमिट फिक्स की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके अंदर अगर इनकी सड़क एग्जॉस्ट होगी तो हम देखेंगे कि उसको देना है या नहीं देना है। अगर नहीं होगी तो उसको हम डालेंगे।

09.09.2024/1410/केएस/एजी/3

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, एक तो मुख्य मंत्री जी जिस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, (***) रणधीर जी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, उसके बावजूद ऐसी टिप्पणी करना किसी सदस्य के प्रति उचित नहीं है। यह टिप्पणी करने का क्रम अभी ही नहीं, हम भी उठते हैं तो हमें भी ये यही कहते हैं। आप मिडिया को एड्रेस करते हैं, तब भी आप यही कहते हैं।

(***) अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

09.09.2024/1415/ag/1

प्रश्न संख्या : 2138-------- क्रमागत

श्री जय राम ठाकुर---- जारी

इस विधान सभा में जो भी चुनकर आता है वह जन-प्रतिनिधि होता है। अगर कोई पढ़ा-लिखा नहीं है, तब भी वह जन-प्रतिनिधि ही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की टिप्पणी को कार्यवाही से निकालना चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणी को नहीं करना चाहिए। आप इस बात को बार-बार बोलते हैं। आपने मुझे भी बोला है और विपक्ष के कई सदस्यों को इस प्रकार से बोला है। ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को सारी जानकारी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सभी सदस्यों के प्रति सम्मान का भाव रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न पूछा गया है, इसको तो इन्होंने गोल-गोल घुमाकर जलेबी बना दिया है। यह एक स्पैसिफिक प्रश्न है कि क्या सरकार की ओर से कोई ऐसी रिकमैंडेशन गई है जिसके अंतर्गत इन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा? नाबार्ड का एक सैट प्रोसिजर है कि जो भी प्राथमिकताओं का क्रम आता है उसी में से पिकअप की जाती हैं। जिनकी डी0पी0आर्ज0 बनी होती हैं उन्हीं में से होना है। आपने जो 1.95 करोड़ रुपये की लिमिट वाली बात कही है तो मुझे लगता है कि अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में अभी भी थोड़ी-बहुत लिमिट्स बची हुई हैं। परंतु हो यह रहा है कि जहां पर विपक्ष के विधायक हैं वहां पर डी0पी0आर्ज0 बनाई ही नहीं जा रही, उनको लंबित रखा जा रहा है। हम विधायक प्राथमिकता की बैठक में अपनी प्राथमिकताएं देते हैं मगर उन प्राथमिकताओं पर अधिकारी काम ही नहीं करते। वे इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको मालूम है कि हम विपक्ष में हैं। मेरा यह मानना है कि अधिकारियों का भी इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है। मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि आपने जो रिकमैंडेशन्ज भेजी थीं, मैं यहां पर अपराध शब्द का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि किसी विधान सभा क्षेत्र में जहां पर जरूरत है वहां आपने रोका है। वह आपने इसलिए रोका है क्योंकि सरकार आपकी है। आपके विधायकों ने कहा कि इसको डालिए तो इसलिए आपने उसको डाल दिया। विधान

सभा क्षेत्र से डी0पी0आर्ज0 बनकर तैयार हैं मगर उसके बावजूद वे आपकी प्राथमिकता में शामिल नहीं हुईं और इसीलिए उनकी स्वीकृति नहीं मिल पा रही है।

09.09.2024/1415/ag/2

मुख्य मंत्री जी, क्या आपने इस संदर्भ में पत्र डाला है? ...(व्यवधान) यह हक़ीक़त है, आपकी सरकार को दो साल का समय होने वाला है। हमारी सरकार के कार्यकाल में जिन कार्यों के टैण्डर होकर के काम भी अवार्ड हो चुके थे अभी भी उनकी पेमैंट नहीं की जा रही है। वर्तमान में उन लोगों की पेमैंट हो रही है जिनके लिए फोन जाते हैं और वे फोन कहां से जाते हैं, मैं उनके बारे में ज़िक्र नहीं करना चाहता। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है।

सभी विधान सभा क्षेत्रों में जो विधायक प्राथमिकता की स्कीम्ज हैं, उनकी डी0पी0आर्ज0 बनाने के लिए भी और उसके बाद हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि आपने जो प्रायोरिटी लिस्ट भेजी है, उसमें क्या विपक्ष के विधायकों का भी कहीं ज़िक्र है?

Speaker: Before that you reply, all those words which are indecent, sarcastic and undesirable will be removed from the record.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी को (***) नहीं कहा। यहां पर बैठे सभी माननीय सदस्य शिक्षित वर्ग में आते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी बात के माध्यम से सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं। मैंने यह कहा कि पढ़ लो, क्या पढ़ने के लिए मना किया है जब प्रश्न में उत्तर लिखा है तो कम-से-कम पढ़ कर तो बोलो। यहां पर बार-बार एक ही सवाल पूछेंगे तो कंफ्यूज़्ड ही नज़र आएंगे। अब मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल न करूं, तो क्या करूं?

(***) अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

टी सी द्वारा जारी

09.09.2024/1420/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

प्रश्न संख्या : 2138. क्रमागत्

मुख्य मंत्री ..... जारी

जब एक विधान सभा क्षेत्र की एक लिमिट हैं और यदि उसमें किसी की कम है तो हम लिखते हैं कि इसकी लिमिट कम है और इन सड़कों को प्रायोरिटी दी जाए। इसमें हम गलत क्या बोल रहे हैं? अगर पत्राचार कर रहे हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं? तभी तो मैं बोल रहा हूं कि पढ़कर सुनाउंगा क्योंकि ये पढ़ते नहीं है? मुझे कहते हैं कि आप ही बड़े ज्ञानी है लेकिन मुझे ज्ञानी तो यह किताब बना रही है जिस किताब में यह सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सवाल करने से पहले सनसनी और कहानी न बनाएं। आप विषय से संबंधित प्रश्न पूछें। माननीय सदस्यों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की डी0पी0आर्ज0 नहीं बनाई गई। इस प्रश्न में दिनांक 04.01.2023 से 31.07.2024 तक के बारे में पूछा गया है और जिनका मैं जबाव दे रहा हूं। सरकाघाट में 10 और पावंटा साहिब में 14 सड़कों को नाबार्ड के तहत बनाया गया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि किसी विधान सभा क्षेत्र के लिए लिमिट से कम अमाउंट रहा होगा तो उस सड़क को भी हम प्रायोरिटी में डालेंगे। जो बात पूर्व मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं, हमने किसी को भी नहीं कहा कि डी0पी0आर्ज0 मत बनाइये। सभी क्षेत्रों में अधिकारियों को डी0पी0आर्ज0 बनाने के लिए कहा गया है। माननीय सदस्यों ने विधायक प्राथमिकता में जिन सड़कों की डी0पी0आर्ज0 बनाने के लिए लिखकर दिया होता है उन सबकी डी0पी0आर्ज0 बनाने का दायित्व उस विधान सभा क्षेत्र के एक्सीयन से संबंधित होता है और उनको कहकर आप डी0पी0आर्ज0 बनाएं। अगर आपके अमाउंट के बीच में डी0पी0आर्ज0 रहेगी यानी 195 की लिमिट में रहेगी तो हम उनको कंसीडर कर लेंगे।

प्रश्न समाप्त

09.09.2024/1420/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

प्रश्न संख्या : 2139

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे विश्वविद्यालय में एक्सपर्ट लोग नहीं हैं,सीनियर लोग नहीं हैं जो बाहर के

लोगों को प्रतिनियुक्ति पर लाया जा रहा है? अगर आप इस तरह से लोगों को बाहर से ही लाते जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को कब अपने प्रदेश में काम करने का मौका मिलेगा? दूसरा, जब सरकार ने प्रतिनियुक्तियां कैंसल कर दी है तो इनको रिलीव कर दें। इनको रिलीव क्यों नहीं किया जा रहा है?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह जो दो प्रतिनियुक्तियां बाहर से हुई हैं ये वर्ष 2022 में हुईं हैं। हमारी सरकार के समय में किसी को भी बाहर से नहीं लाया गया है और इनकी प्रतिनियुक्ति रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है क्योंकि इनके ऊपर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च आ रहा है जिसको बचाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में क्वालिफाइड लोग हैं और उनको नियुक्ति दी जा सकती है।

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया जारी है और इसका जो लिखित में उत्तर दिया गया है उसमें कहा गया है कि इनकी प्रतिनियुक्तियां रद्द कर दी गईं हैं। यदि रद्द कर दी गईं हैं तो उनको रिलीव कर दो।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है लेकिन इनकी प्रतिनियुक्तियां रद्द कर दी गईं हैं।

09.09.2024/1420/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यहां पर जो विश्वविद्यालय में भर्ती की बात की जा रही है, क्या यह भर्ती सिलेक्शन के माध्यम से हुई है और क्या इसकी अनुमति सरकार ने दी है? यदि इसकी अनुमति सरकार ने दी है और इनकी सिलेक्शन भर्ती के माध्यम से हुईं हैं तो क्या सरकार या विश्वविद्यालय प्रशासन उनको हटा सकता है?

दूसरा क्या इनके खिलाफ कोई चार्जिज हैं? क्योंकि ऐसे अनेकों विभागों में दूसरे राज्यों के लोग यहां सर्विस कर रहे हैं। यह जो डेपुटेशन शब्द लिखा गया है, सरकार इसको भी क्लीयर करें कि डेपुटेशन शब्द क्यों लिखा गया है?

राजस्व मंत्री एन0एस0 द्वारा शुरू ।

09-09-2024/1425/एन0एस0-ए0एस0/1

प्रश्न संख्या : 2139 ---क्रमागत

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले कहा कि ये दो साइंटिस्ट बाहरी राज्यों से लाए गए जबकि इनकी आवश्यकता नहीं थी। जब विपक्ष की सरकार थी तो उस समय ये लाए गए हैं। ये इनके बारे में प्रश्न भी स्वयं ही कर रहे हैं और जवाब भी खुद ही दे रहे हैं। यह यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश सरकार की ग्रांट पर चलती है। इसमें सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। हम 1.67 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा इन दो अधिकारियों के ऊपर खर्च कर रहे हैं जबकि हमारे पास इसी क्वालिफिकेशन के लोग ऑलरेडी हैं। इसमें लिखा हुआ है कि दो साल के डेपुटेशन के लिए ये जिस स्टेट से आए हैं तो उन्होंने भी लिखा है कि दो साल के डेपुटेशन पर हैं। पर ये चाह रहे हैं कि इनको कंटीन्यू किया जाए। आज यूनिवर्सिटी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह संभव नहीं है।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने पूरा जवाब दे दिया। श्री राकेश जम्वाल जी अब आप क्या पूछना चाहते हैं?

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछ रहा हूं कि सरकार ने अगर कोई पोस्टें सैंक्शन कीं तो उनका विज्ञापन ऑल इंडिया लैवल पर दिया गया और जो दो लोग सलैक्ट होकर आए वे किसी भी प्रदेश से आए। हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोग दूसरे प्रांतों के विश्वविद्यालयों में काम करते हैं। ये बातें बड़ी दूर तक जाएंगी। डेपुटेशन शब्द क्यों लिखा गया है? ये लोग अपने 5 सालों की सर्विस और ड्यूज यहां पर क्लेम न करें, इसलिए डेपुटेशन शब्द लिखा गया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर ये सरकार की अनुमति या सलैक्शन से आए हैं तो क्या सरकार इनको हटा सकती है? ये पांच साल के लिए सलैक्शन से आए हैं। साथ में यह भी पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि कार्रवाई की जाएगी। क्या इनके खिलाफ कोई चार्जिज हैं जिसके लिए आप कार्रवाई करेंगे?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिस जगह से ये आए हैं उन्होंने भी कंडीशन डेपुटेशन की लिखी है और इनको डेपुटेशन ही माना गया है। हमें अब इनकी आवश्यकता नहीं है और

हम अपना निर्णय बदल देंगे। जो पिछली सरकार ने फैसला लिया है तो मैं समझता हूं कि वह भी गलत था।

अध्यक्ष : आप इसे नियम-61 के तहत लाएं, आप इसको कल भी ला सकते हैं। He has specifically said that.

09-09-2024/1425/एन0एस0-ए0एस0/2

प्रश्न संख्या : 2140

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हिमकेयर के लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया में क्या नियमों में कोई बदलाव हुआ है? दूसरा, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, इसमें बताया गया है कि प्रदेश में हिमकेयर योजना के अंदर निजी अस्पतालों की भी सूची आई है। क्या इन अस्पतालों के बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर्ज की सूची भी सभा पटल पर रखेंगे? 'घ' भाग में जो उत्तर आया है उसमें बताया गया है कि किसी भी निजी अस्पताल में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। क्या निजी अस्पतालों के लिए कोई जांच कमेटी बनी थी या इनकी जांच के कोई आदेश मंत्री जी ने दिए थे? यह मैं जानना चाहता हूं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं तो 5 प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि इसके अंतर्गत 32,507 लाभार्थी पंजीकृत हैं। योजना अनुसार सभी लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। 6 महीने में 4 प्रमाण पत्र चाहिए होते हैं। The first is Life Certificate, the second is Income Certificate, the third is BPL Certificate and the final is Medical Certificate.

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

09.09.2024/1430/rks/dc-1

प्रश्न संख्याः 2140... जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री....जारी

ये प्रमाण-पत्र अपलोड कर दिए जाते हैं। इसकी यह प्रकिया है और किसी वजह से इसमें डीले हो जाए तो जो स्वास्थ्य लाभ मिलना है उसमें देरी हो जाती है। आजकल ये प्रमाण-पत्र अलग-अलग चैनल से अपलोड किए जा सकते हैं। अगर माननीय सदस्य इस संदर्भ में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। Third Party audit is being done regularly in all the private hospitals just like the government hospitals.

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का एक भाग यह था कि क्या माननीय मंत्री जी निजी अस्पतालों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्ज की सूची सभा पटल पर रखेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने सूचना मांगी है वह सभा पटल पर रख दी जाएगी। In the august House I can say that there have been a Sub Committee formed and that Sub Committee has to see कि इसमें जो सुधार की संभावना है वह सही हो। **यह सब-कमेटी हाल ही में गठित की गई है और इसकी सूचना भी सदन में दे दी जाएगी।**

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो सहारा योजना के लंबित आवेदन हैं उन्हें कब तक स्वीकार किया जाएगा? सहारा योजना में 6 महीनों के भीतर प्रमाण-पत्र देना जरूरी है। सहारा योजना उन मरीजों के लिए हैं जो बैड रिडन हैं। इसलिए हर 6 महीने बाद जीवित प्रमाण-पत्र देना संभव नहीं है। मेरा आग्रह है कि अगर सरकार इस 6 महीने की शर्त को बढ़ाकर एक वर्ष कर दें तो मराजों को काफी लाभ होगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि हिमकेयर योजना के तहत जो निजी अस्पतालों की धनराशि लंबित पड़ी है क्या आप उस धनराशि को जारी करेंगे या नहीं? यदि हां, तो यह राशि कब तक जारी कर दी जाएगी?

09.09.2024/1430/rks/dc-2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रमाण-पत्र की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया है, वह एक अच्छा सुझाव है। हम इस अवधि को बढ़ाने का विचार करेंगे। दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैं आपको क्लेम वाली राशि बढ़ने के बारे में बताउंगा। पहले जो एक साल की अवधि रखी गई थी उसे अब तीन साल कर दिया है। इस तरह क्लेम बढ़ते गए और निजी अस्पतालों की देनदारियां भी बढ़ती गई। हमें निजी अस्पतालों को राशि जारी बंद करनी पड़ी।

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सहारा योजन में बहुत ज्यादा पेंडेंसी है। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में लगभग 150 ऐसे मरीज हैं जो बैड रिडन हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप इस पेंडेंसी को कब तक जारी करेंगे? जब से आपकी सरकार बनी है हिमकेयर योजना में मेरे चुनाव क्षेत्र के 29 ऐसे केस हैं जिनको अभी तक पेंडिंग राशि नहीं मिली है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस राशि को कब तक जारी करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज का प्रश्न मूलतः हिमकेयर और सहारा योजना पर आधारित है।

श्री बी.एस. द्वारा ... जारी

09.09.2024/1435 /बी.एस./डी.सी-1

Question No 2140 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी...

पहला हिमकेयर योजना और दूसरा प्रधान मंत्री आदर्श स्वास्थ्य योजना। जहां तक सहारा योजना का तालुक है as brought out earlier also ये उन बीमारियों के लिए है जितमें मरीज कफी गंभीर हालत में पड़े होते हैं। Those ones who require long treatment और वे लोग अपनी जेब से कुछ भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए इस योजना का नाम सहारा रखा गया है। हम उन लोगों को सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों की 4 लाख रुपये से ज्यादा आमदनी नहीं है उनको तीन हजार रुपये प्रति माह दे दिया जाता है। ताकि वे अपना इलाज करवा सकें और बीमारी से बाहर आ सकें। जहां तक आपका तालुक पेमेंट

के बारे में है it is continuous process. The Government is always in continuity और जिस प्रकार मैं देख भी रहा था कि बहुत सी देनदारियां हैं, जो पहले की सरकार के समय की रह गई हैं और हमें उनको देना पड़ा। जो 90/10 का अनुपात है 90 percent from the Centre Government and 10 per cent from the State Government, 10 प्रतिशत देने के बाद भी हम लोगों को बहुत सी देनदारियां देनी पड़ी। यह पूरे-का-पूरा प्रोसेस देखा जा रहा है and I am sure that soon we shall be able to give an answer कृपया आप धैर्य रखिए। 2-3 या 4 महीनों में जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं उन्हें आप लोगों को मुहैया करवा दिया जाएगा। इस प्रकार का आपका कोई भी प्रश्न नहीं रह जाएगा।

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी हिमकेयर योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुछ निजी अस्पताल भी इसमें empanel किए गए थे क्या उन अस्पतालों में इस योजना के माध्यम से अब इलाज बंद कर दिया गया है? यदि बंद कर दिया गया है तो उसका क्या कारण है? दूसरा, जिन लोगों ने निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवाया है, उनके ड्यूज अभी पेडिंग पड़े हैं। तो उस पैसे को उन लोगों को देने का क्या प्रावधान है? मंत्री जी बतलाने की कृपा करें।

09.09.2024/1435 /बी.एस./डी.सी-2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दोराय नहीं कि हमें 01 सितम्बर से पाइवेट अस्पतालों में दी जानी वाली सुविधाओं को बंद करना पड़ा। However dialysis is continuing, for that matter any other critical care needed for chronical diseases उसे निजी अस्पतलों में बंद नहीं किया गया है। आपने जो प्रश्न पूछा है। मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि 172.66 इसमें 82.66 देनदारियां देनी पड़ी despite the fact कि 90/10 की यह योजना है। उसके बाद 10 प्रतिशत देने के बाद भी हमारी सरकार को बहुत सी देनदारियां देनी पड़ रही हैं और हम दे रहे हैं। आपकी किसी प्रकार की योजना को बंद नहीं किया गया है। केवल निजी अस्पतालों को इसलिए बंद किया गया as there have been some irregularities. जहां तक पब्लिक अस्पतालों का प्रश्न है, पब्लिक अस्पतालों में as I told you earlier we are continuing for the dialysis

and any other critical care required. There should be no doubt in it. हिमकेयर का जैसा मैंने कहा कि हर छह महीने में अपलोड होते रहते हैं। अगर ये प्रमाण पत्र जैसे कि auto system हैं नहीं हो तो somehow it gets stuck. जब वे पूरा कर देते हैं तो इसमें देनदारियां automatically ही दे दी जाती हैं। There is no such difficult situation in which patients are put क्योंकि इसमें बिमार लोगों का जो इलाज है वह बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। इसलिए जब से हमारी सरकार बनी मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए बीड़ा उठाया है। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य सुविधाओं में हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा नाम हुए हैं। इसके लिए पूरे देश में हमारे प्रदेश की पशंसा की जाती है। इस क्षेत्र में हमारा प्रदेश काफी आगे हैं। I think you should appreciate that.

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी, ...(Interruption). Hon'ble Chief Minister wants to reply to the supplementary.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्य मंत्री जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं चाहूंगा कि पहले ठाकुर साबह अपना प्रश्न पूछ लें।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

09.09.2024/1440/डी0टी0/एच0के0-1

प्रश्न संख्या 2140 जारी...

अध्यक्षः माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि उनकी नज़र भी मेरी ओर पड़ी।
अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के गरीब लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सुविधाएं पूर्व सरकार के समय उपलब्ध करवाई गई थी उन सुविधाओं को एक तरह से वर्तमान सरकार ने रोक दिया है। जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है उस उत्तर में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार हक़ीकत को छुपा कर कहां जाना चाहती है? जो हक़ीकत है उसे स्वीकार करना चाहिए। सहारा योजना हमनें ऐसे लोगों के लिए शुरू की थी जो बेबस हैं, लाचार हैं, असहाय हैं और बिस्तर पर पड़ें हैं। वो जिंदा तो है लेकिन अपना काम खुद नहीं कर

सकते, ऐसी बिमारी उनको लग गई है। सहारा योजना के द्वारा 3000 रुपये ऐसे ही व्यक्ति के खातें में डाला जाता था। आजकल ऐसे दर्जनों लोगों के प्रार्थना पत्र, संदेश व फोन हमें आ रहे हैं। क्योंकि सहारा योजना के तहत जो पैसा उनके खातों में जाता था वह पैसा अब नहीं जा रहा। इस संबंध में मैंने अधिकारियों से भी पूछा था, मुझे ये जानकारी दी गई थी कि ट्रेजरी में कोई इश्यू आ गया था जिस कारण से ये पैसा ऐसे असहाय लोगों को नहीं मिल पाया। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप विभिन्न उपेक्षित वर्गों के प्रति संवदेना रखते हैं इसी प्रकार की योजना सुखाश्रय के नाम से आपने अनाथ बच्चों के लिए भी चलाई है। आपने नाम जिस तरह का भी रखा हो लेकिन उस योजना की भावना अच्छी है। उसी तरह से जो ये साहारा योजना है वह भी इसी तरह की योजना है। और अभी इस योजना में लंबित मामलों की संख्या 5379 है। मैं ये चाहता हूं कि जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिलता था क्या आप सुनिश्चत करेंगे कि हर महीने इन गरीबों लोगों के उपचार के लिए व इनके परिवार की जो छोटी-मोटी जो जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए पैसा हर महीने इनके खाते में डाला जायेगा? मेरे प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसमें जो हिमकेयर योजना है, जिसका उत्तर आपने 'ख' भाग में दिया है कि 355 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है उसके बाद 127.93 करोड़ रुपये प्राइवेट हस्पतालों का भी है। ये क्या 127.93 करोड़ रुपये इस 355 करोड़ में शामिल है या इसके अतिरिक्त है, इसको स्पष्ट करें? तीसरी बात जो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं वह यह है कि इनके द्वारा आदेश जारी

09.09.2024/1440/डी0टी0/एच0के0-2

किये गये कि नीजि चिकित्सालयों में हिमकेयर योजना अब नहीं चलाई जायेगी यानी उसका पैसा नहीं दिया जायेगा। हमनें इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की है क्या इसमें कोई अनियमतताएं पाईं गई हैं, जिसके कारण इसे बंद किया गया हो। लेकिन हमें पता चला कि इसमें कोई अनियमतताएं भी नहीं पाई गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट चिकित्सालयों में हिमकेयार योजना को बंद कर दिया गया है। क्या मुख्य मंत्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जब सरकारी चिकित्सालयों में कोई कोई आदमी उपचार करवाने के लिए जाता है, उसे अल्ट्रा साउंड की डेट एक-एक महीने के बाद

मिलती है, इसमें डाक्टरज का कसूर नहीं है, उनपर पर वर्कलोड बहुत है। एम0आर0आई0 करवानी हो तो उसके लिए तीन-तीन महीने के बाद की डेट लोगों को दी जाती है। सीटी स्कैन करवाना हो तो दो-दो महीने के बाद की डेट रोगियों को दी जाती है। इतने समय के बाद जो डेटज मिलती है अगर किसी रोगी को गम्भीर रूप की बिमारी है और उसे एम0आर0आई0 या सीटी स्कैन की डेटस नहीं मिलती तो उसका उपचार समय पर नहीं हो पायेगा, और उसे कुछ भी हो सकता। हमनें इसी भाव के साथ प्राइवेट सेक्टर के चिकित्सालयों को इम्पैनल्ड किया था। तो क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो प्राइवेट चिकित्सालयों में, पूर्व सरकार के समय हिमकेयर की एक व्यवस्था दी थी वो इसलिए

श्री एन0जी0द्वारा जारी

09-09-2024/1445/एच.के.-एन.जी/1

प्रश्न संख्या - 2140.....जारी

श्री जय राम ठाकुर.....जारी

क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि निजी अस्पतालों में हमने हिम केयर की व्यवस्था दी थी, उसे पुनः आरम्भ करेंगे? हमने यह व्यवस्था इसलिए की थी क्योंकि स्वास्थ्य से ऊपर यानि के आदमी की जिंदगी से महत्वपूर्ण कोई भी चीज़ नहीं है। यदि आपको लगता है कि कुछ गलत किया है तो आप निजी अस्पतालों की जांच कीजिए और उन पर कार्रवाई भी कीजिए। निजी अस्पतालों की इम्पैनलमेंट लोगों की सुविधा की दृष्टि से की गई थी और क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि उस सुविधा को जारी रखा जाएगा?

अध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने पहले बोल दिया है कि निजी

09-09-2024/1445/एच.के.-एन.जी/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री व नेता विपक्ष, श्री जय राम ठाकुर जी ने प्रश्न उठाया है और इस महत्वपूर्ण विषय पर मैंने पहले भी कहा है कि Cabinet has formed a sub-Committee to go into this entire gamut of SAHARA YOJANA as well as HIMCARE. आपने ठीक कहा कि उन लोगों के लिए यह सहारा है जो लोग Parkinson's, Malignant Cancer Disease, Paralysis Disease having permanent disability taking treatment for long basis or bed ridden, Muscular Dystrophy, Haemophilia, Thalassemia, Acute or chronic Renal failure or any other disease which renders a person permanently incapacitated से ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए यह योजना बनाई गई थी और सचमुच में कोई भी योजना रोकी नहीं जा रही है। यह ठीक है कि हमारी देनदारियां 418 करोड़ रुपये की हैं It is being attended and you will be seen that it will be definitely attended soon. जहां तक निजी अस्पतालों का ताल्लुक है तो बहुत सारे कारणों से इस योजना को निजी अस्पतालों में बंद करना पड़ा। लेकिन इसका किसी भी प्रकार का प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। आज मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है और लगातार we are in the process of getting all the modern machineries e.g. the Ultrasound, the MRI and we are trying our best. हमारे जिला व ब्लॉक लेवल तक के अस्पतालों में जितनी भी सुविधाएं हैं they should be upgraded to the most modern health facilities और हम इस ओर बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमें निजी अस्पतालों में जाने की जरूरत ही न पड़े। हम इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से करने की ओर बढ़ रहे हैं। We are trying to do it. That is why I feel the question which has raised by the Hon'ble Member, I have adequately answer to it.

09-09-2024/1445/एच.के.-एन.जी/3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने 6 मिनट में पूरे अतीत व वर्तमान को इस माननीय सदन में रखा है और हमने इनके बीच में कुछ भी नहीं बोला था। अध्यक्ष महोदय, हम व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। इस व्यवस्था परिवर्तन में हिमकेयर की ओर देखा गया कि सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को डी.ए. की किश्त नहीं दी गई लेकिन हिम केयर योजना को निजी अस्पतालों को ज्यादा पैसा देने के लिए बना दिया गया। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं और पूर्व मुख्य मंत्री भी इस बात को स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि सिटी स्कैन, पैट स्कैन आदि टैस्ट्स को तीन-तीन माह का समय लग जाता है और इस व्यवस्था को देखते हुए हमने हिम केयर योजना लाई है। इनका कहने का तात्पर्य यही था। इसमें कोई दोराय नहीं है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इसकी हर चीज़ पर विचार-विमर्श किया है। मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि हमने पाया कि प्रदेश में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वे सभी रैफरल अस्पताल बन गए हैं।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

09.09.2024/1450/केएस/वाईके/1

प्रश्न संख्या : 2140 जारी--

मुख्य मंत्री जारी---

मरीज नूरपुर,कांगड़ा, मण्डी या कुल्लू से चलेगा, उसके बाद वह पी.जी.आई. को ट्रांसफर हो जाता है। कइयों के पास तो पैसे भी नहीं होते लोन उठाकर वे अपना इलाज करवाते हैं। हिमकेयर योजना से फायदा किसको हुआ? पहली बार हिमाचल प्रदेश में 137 निजी हॉस्पिटल खुल गए। क्या हमारे सरकारी हॉस्पिटल्ज़ इतने मज़बूत नहीं हो सकते थे? हमने 1150 करोड़ रुपया हिमकेयर के नाम पर निजी अस्पतालों को दे दिया। मैं यह बात

इसलिए कहना चाहता हूं कि सहारा योजना पर भी हमने गौर किया। हिमकेयर योजना में हमने पाया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्ज़ वाले रोज़ फोन कर रहे हैं कि हमारे बिल दे दीजिए। हर्निया का ऑप्रेशन होता है तो कहते हैं कि पैकेज ही लेना पड़ेगा। खर्चा 25 हजार रुपया है और बिल बन रहा है एक लाख रुपये का। हमने फैसला किया कि हमारे जो डॉक्टर्ज़ जो वर्ल्ड रिनाउंड हैं, चाहे आई.जी.एम.सी. में है, टांडा में हैं या प्रदेश में किसी अन्य जगह पर लगे हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। पहले चरण में इस वर्ष आई.जी.एम.सी. मैडिकल कॉलेज और टांडा मैडिकल कॉलेज को मज़बूत करने की दिशा में हम आगे बढ़े। वर्ल्ड प्रैक्टिस क्या है, हम नर्सिज़ से मिले, उन्होंने कहा कि एक नर्स 12 मरीजों को देखती है। 12 मरीजों को जो नर्स देखेगी, एक डॉक्टर जो एस.आर.शिप करता है 72 घंटे, 48 घंटे की डियूटी देता है। आप बताएं कि 8 घंटे बाद तो वैसे ही माइंड थक जाता है। हमने उस व्यवस्था में परिवर्तन किया और आज आई.जी.एम.सी. में लगभग चार सौ कुछ पोस्टें और टांडा में 450 पोस्टें हमने स्वीकृत कर दी हैं। हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं और इन पदों को हम रैगुलर बेस पर भरेंगे। 200 डॉक्टर हमने पब्लिक सर्विस कमिशन के थ्रू भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता को अच्छी क्वालिटी का इलाज मिले। इसलिए हमने जब निजी हॉस्पिटल्ज़ का पता किया, उनके पैकेज की छानबीन चल रही है। यह ठीक है कि इसमें लिखा गया है कि अनियमितताएं नहीं हैं, माननीय सदस्य सुधीर शर्मा जी ने पूछा है, लेकिन हमें ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि अनियमितताएं भी पाई गई हैं। हमारी कैबिनेट सब कमेटी देख रही है और किसी हॉस्पिटल का तो इतना बिल है, आप इसी में देख लीजिए कि कई हॉस्पिटल्ज़ के पास इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्केन की सुविधा नहीं है, कितनी सिटी स्केन की मशीन्ज़

09.09.2024/1450/केएस/वाईके/2

हैं? हम इन सारी चीजों को देख रहे हैं। हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। जहां निजी अस्पतालों के हैं, उसमें कैबिनेट सब कमेटी सारे डॉकुमैंट्स चैक करेगी और उसके बाद अगर आगे बढ़ना होगा तो हमारी सरकार आगे भी बढ़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, आयुषमान भारत जो कि केंद्र सरकार की योजना है। उसमें भी धांधलियां हुई हैं। जब उसमें धांधलियां हो सकती हैं तो इनमें भी हो सकती हैं परंतु जब तक

हम जानेंगे नहीं, तब तक कैसे करेंगे? अध्यक्ष महोदय, इस जवाब में ही लिखा है कि अभी भी टोटल पैंडिंग लायबिलिटीज़ 355 करोड़ रुपये की है और पिछले कल ही मैंने 60 करोड़ रुपये की रिलीज़ की हैं ताकि आई.जी.एम.सी., टांडा और पी.जी.आई. में किसी आम आदमी, गरीब आदमी को नुकसान न पहुंचे। इसलिए हमने एक वर्ष में, जैसा कि इस उत्तर में लिखा गया है, हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल्ज़ की अभी भी 127 करोड़ रुपये की पेंडिंग पेमेंट है। और सरकारी हॉस्पिटल्ज़ की 227 करोड़ रुपये है। जबकि सरकारी अस्पतालों में, मैं किसी निजी हॉस्पिटल पर कटाक्ष नहीं करना चाहता, गवर्नमैंट हॉस्पिटल्ज़ में लगने वाले डॉक्टर टैस्ट के थ्रू आते हैं और डेडिकेटिड होते हैं। निजी हॉस्पिटल्ज़ वाले भी होते हैं लेकिन जो हमारे गवर्नमैंट हॉस्पिटल्ज़ हैं, उनको स्ट्रेंथन करना हमारा दायित्व भी है।

अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्य मंत्री जी के समय में सहारा योजना एक बहुत ही अच्छी योजना शुरू की गई थी और इसमें कोई दो राय नहीं है। हिम केयर का बजट 20 करोड़ रुपये था। इसमें से 1150 करोड़ रुपये रिलीज़ कर चुके हैं और लगभग 300 के करीब हमारी सरकार बनने के बाद हमने रिलीज किया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्ज़ में अभी हमने डायलासिज़ की सुविधा दी है क्योंकि उसका रेट 1500 रुपया फिक्स है। सहारा योजना एक अच्छी योजना ले कर आए थे। हमारी सरकार बड़ी संवेदनशील है। हमने अनाथ बच्चों के लिए, जिनके माता-पिता नहीं हैं, हिमाचल हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जिसने उन अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

09.09.2024/1455/AV/YK/1

प्रश्न संख्या : 2140-------- क्रमागत

मुख्य मंत्री---- जारी

आज कोई अनाथ बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है तो उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। इसके अतिरिक्त जहां पर होस्टल की सुविधा नहीं होगी वहां पर 3000 रुपये की राशि का खर्चा भी हमारी सरकार ही वहन करेगी। सहारा

योजना माननीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी के कार्यकाल में शुरू की गई थी। यह एक अच्छी योजना है मगर इसमें भी यह देखने की जरूरत है कि जो चल नहीं सकता या व्हील चेयर पर चलने वाले को क्या सही मायने में सहारे की जरूरत है। हम इन सारी केटेगरीज का अध्ययन कर रहे हैं और **उनको हम सहारा योजना से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं करेंगे।** ...(व्यवधान) आपने एक अच्छी योजना चलाई है और हम उसका स्वागत करते हैं। ...(व्यवधान) हमारे नाम से कोई योजना नहीं है। नाम इंगित होता होगा परंतु मेरा नाम सुखविन्दर सिंह सुक्खू है। इसलिए अगर सुखविन्दर सिंह सुक्खू के नाम से किसी योजना का नाम होगा तो आप लोग ऑब्जैक्शन करना। सुख का मतलब 'happiness' है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इसके बारे में भी हमारे पास थोड़ी-बहुत शिकायतें आई हैं कि कई लोगों ने जिनकी अंगुली भी कटी है उसका भी सहारा योजना के तहत प्रमाणपत्र बनाया हुआ है। ...(व्यवधान) **मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई बैड पर लेटा होगा और चलने-फिरने के काबिल नहीं होगा तो आपकी इस योजना को और भी मज़बूत किया जाएगा।** इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार हिमकेयर योजना को बंद नहीं कर रही है। हमने उसमें कुछ सुधार करके यह सोचना है कि उसमें क्या हमें प्रीमियम फिक्स करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो उसमें हमें किन सुधारों के साथ आगे बढ़ना है, मैंने इसके बारे में माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी के साथ चर्चा की है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं और मैंने यह बार-बार कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश में बैस्ट हैल्थ सिस्टम को डवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एम्ज़ दिल्ली के साथ समझौता हुआ है और

09.09.2024/1455/AV/YK/2

हम आने वाले एक-दो वर्षों में प्रदेश में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हमारी रोबॉटिक सर्जरी भी शामिल होगी। हमने प्रदेश के सभी 68 विधान सभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना रहे हैं और **हमारे पास जैसे-जैसे डॉक्टर्ज की संख्या बढ़ती जाएगी, उनमें नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो पी0एच0सीज0 खाली हैं हम उनमें भी डॉक्टर भरने जा रहे हैं। हमने हिमकेयर और सहारा योजना में सुधार**

करना है और इन योजनाओं के अंतर्गत उस व्यक्ति का अधिकार नहीं छीना जाएगा जो गरीब और जरूरतमंद है। हमारी कैबिनेट की सब कमेटी उस बारे में विचार-विमर्श करेगी।

09.09.2024/1455/AV/YK/3

प्रश्न संख्या 2141

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां इससे पहले भी 'व्यवस्था का प्रश्न' के माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक शहीद मेजर का मामला उठाया था कि उनके परिवार को पूर्व सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन अभी तक अधूरे हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि शहीदों के परिवारों के साथ चाहे वह पूर्व में किसी भी सरकार द्वारा कोई भी आश्वासन दिए गए हैं, जो अभी तक अधूरे हैं, उनको रिव्यू करके शीघ्र पूरा किया जाए?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। वर्ष 1947 से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश के 1774 जवान या अधिकारी बैटल कैजुअल्टी के रूप में घोषित किए जा चुके हैं। हालांकि यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है। Hon'ble Speaker, Sir, I can give a detail reply of it.

टी सी द्वारा जारी

09.09.2024/1500/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री..... जारी

इनमें से 736 जवान जो जिला कांगड़ा से संबंध रखते हैं और उनमें से नौ जवान इंदौरा विधान सभा क्षेत्र से हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बैटल कैजुअल्टी के परिजनों को इस प्रकार की सुविधाएं दी जा रहीं हैं :

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सैनिकों के निकटतम परिजनों (Next of Kin) को एक्सग्रेशिया राशि प्रदान की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 सितम्बर, 2023 को

बैटल कैजुअल्टी सैनिकों के परिजनों को मिलने अनुग्रह राशि मु0 20 लाख से 30 लाख रुपये कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बैटल कैजुअल्टी सैनिकों के परिजनों (Next of Kin) को प्रदेश के भीतर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क बस यात्रा हेतु बस पास की सुविधा प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बैटल कैजुअल्टी सैनिकों के परिजनों में एक को उसके शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पूर्व/भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पदों में से प्राथमिकता के आधार पर नौकरी प्रदान की जाती है। The last question posed by the Hon'ble Member is regarding जितने भी इनको आश्वासन दिए हैं, चाहे पहले की सरकार थी या अब है, कभी भी सरकार ने कोई ऐसा आश्वासन दिया हो for a battle casualty and for those who sacrifice their life for the defense of this country has been fulfilled. अभी भी मैं इस माननीय सदन में आश्वासन देता हूं कि **that any promise made for a battle casualty will be honoured.**

प्रश्न काल समाप्त

09.09.2024/1500/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री,सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जोकि इस प्रकार है :-

सोमवार, 09 सितम्बर, 2024 शासकीय/विधायी कार्य

मंगलवार, 10 सितम्बर, 2024 शासकीय/विधायी कार्य

09.09.2024/1500/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब मुख्य मन्त्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सहबद्ध सेवा/पद, ग्रुप-सी, परीक्षा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः पीईआर(एपी)-सी-ए(3) -4/2019, दिनांक 09.04.2024 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.04.2024 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यावरण अधिकारी, ग्रुप-ए भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः एस0टी0ई0बी(3)-1/2022, दिनांक 12.04.2024 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.05.2024 को प्रकाशित; और

(iii) नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (डी पी सी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड का 39वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित)।

अध्यक्ष : अब स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी) के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब आयुष मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

09.09.2024/1500/टी0सी0वी0/ए0जी0-4

आयुष मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप- धारा (1) और (2) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप- धारा (1) और (2) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित)।

09.09.2024/1500/टी0सी0वी0/ए0जी0-5

<u>सदन की समिति का प्रतिवेदन</u>

अध्यक्ष : अब सदन की समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाएगा। श्री संजय रत्न सभापति, स्थानीय निधि लेखा समिति, स्थानीय निधि लेखा समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्थानीय निधि लेखा समिति, (वर्ष 2024-25), समिति के प्रथम मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत नाया पंजोड़, विकास खण्ड शिलाई, सिरमौर अवधि 04/2018 से 03/2023 के लेखाओं पर तैयार विशेष अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की संवीक्षा पर आधारित तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

09.09.2024/1500/टी0सी0वी0/ए0जी0-6

सांविधिक ईकाईयों हेतु मनोनयन

अध्यक्ष : अब माननीय शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश निम्न प्राइवेट विश्वविद्यालयों के शासकीय निकायों में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्य को मनोनीत करने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश निम्न प्राइवेट विश्वविद्यालयों के शासकीय निकायों में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्य को मनोनीत करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

Education Minister in English by AG . . ..

09092024/1505/AG-NS/1

Education Minister in English . . .

"That in pursuance of Section 18 (1) of the Private Universities Act and Section 17(1) of the First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of two years in the Governing Body of 16 Private Universities, for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the First Statutes of the Private Universities.छ

S.N.	Name of the University
1.	Arni University, Kathgarh, Indora (Kangra).
2.	Shoolini University of Biotechnology & Management Science, Bajhol, District Solan.
3.	IEC University Kallujhanda, Barotiwala, District Solan.
4.	Baddi University of Emerging Science & Technologies, Baddi (Solan).
5.	Chitkara University, Kallujhanda, Barotiwala, District Solan.
6.	Bahara University, Waknaghat, District Solan.
7.	Manav Bharti University, Village Sultanpur, District Solan.
8.	Career Point University, Tikker Kharwarian (Bhoranj), District Hamirpur, H.P.
9.	Sri Sai University Palampur (Kangra)
10.	APG Shimla University, Panthaghati, Shimla.
11.	Indus International University, VPO Bathu, District Solan.
12.	Eternal University, Baru Sahib, District Sirmour
13.	Maharishi Markandeshwar, University, Kumarhatti, Solan
14.	Abhilashi University, Chailchowk, Tehsil Chachiot, District Mandi
15.	Maharaja Agarsen University, Baddi
16.	Institute of Chartered Financial Analysis (ICFAI) University, Baddi

09092024/1505/AG-NS/2

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि ःThat in pursuance of Section 18 (1) of the Private Universities Act and Section 17(1) of the First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of two years in the Governing Body of 16 Private Universities, for a term of two years commencing from the date of publication of their

being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the First Statutes of the Private Universities.छ

S.N.	Name of the University
1.	Arni University, Kathgarh, Indora (Kangra).
2.	Shoolini University of Biotechnology & Management Science, Bajhol, District Solan.
3.	IEC University Kallujhanda, Barotiwala, District Solan.
4.	Baddi University of Emerging Science & Technologies, Baddi (Solan).
5.	Chitkara University, Kallujhanda, Barotiwala, District Solan.
6.	Bahara University, Waknaghat, District Solan.
7.	Manav Bharti University, Village Sultanpur, District Solan.
8.	Career Point University, Tikker Kharwarian (Bhoranj), District Hamirpur, H.P.
9.	Sri Sai University Palampur (Kangra)
10.	APG Shimla University, Panthaghati, Shimla.
11.	Indus International University, VPO Bathu, District Solan.
12.	Eternal University, Baru Sahib, District Sirmour
13.	Maharishi Markandeshwar, University, Kumarhatti, Solan
14.	Abhilashi University, Chailchowk, Tehsil Chachiot, District Mandi
15.	Maharaja Agarsen University, Baddi
16.	Institute of Chartered Financial Analysis (ICFAI) University, Baddi

09092024/1505/AG-NS/3

तो प्रश्न यह है कि च That in pursuance of Section 18 (1) of the Private Universities Act and Section 17(1) of the First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the

term of two years in the Governing Body of 16 Private Universities, for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the First Statutes of the Private Universities.छ

S.N.	Name of the University
1.	Arni University, Kathgarh, Indora (Kangra).
2.	Shoolini University of Biotechnology & Management Science, Bajhol, District Solan.
3.	IEC University Kallujhanda, Barotiwala, District Solan.
4.	Baddi University of Emerging Science & Technologies, Baddi (Solan).
5.	Chitkara University, Kallujhanda, Barotiwala, District Solan.
6.	Bahara University, Waknaghat, District Solan.
7.	Manav Bharti University, Village Sultanpur, District Solan.
8.	Career Point University, Tikker Kharwarian (Bhoranj), District Hamirpur, H.P.
9.	Sri Sai University Palampur (Kangra)
10.	APG Shimla University, Panthaghati, Shimla.
11.	Indus International University, VPO Bathu, District Solan.
12.	Eternal University, Baru Sahib, District Sirmour
13.	Maharishi Markandeshwar, University, Kumarhatti, Solan
14.	Abhilashi University, Chailchowk, Tehsil Chachiot, District Mandi
15.	Maharaja Agarsen University, Baddi
16.	Institute of Chartered Financial Analysis (ICFAI) University, Baddi

प्रस्ताव स्वीकार

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

09.09.2024/1510/rks/AS-1

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होंगे। अब श्री पवन कुमार काजल अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और फिर उप-मुख्य मंत्री जी उसका उत्तर देंगे। श्री पवन कुमार काजल जी चाहें तो आप चेयर की अनुमति से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। अब मैं श्री पवन कुमार काजल जी से आग्रह करूंगा कि आप अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस माननीय सदन में प्रस्तुत करें।

श्री पवन कुमार काजल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से "कांगड़ा निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के कारण हो रही असुविधा पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

अध्यक्ष : कृपया आप अपना विषय जारी रखिए।

श्री पवन कुमार काजल : अध्यक्ष महोदय, मैं जब वर्ष 2012 में इस विधान सभा में पहली बार चुनकर आया था तो मैंने कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र के लिए कई पानी की स्कीमों की डी.पी.आर्ज. बनवाई थी। वहां पर जो वर्ष 2012 से पहले सिंचाई एवं पेयजल योजनाएं की स्कीमें क्रियाशील थी वे डिफंक्ट थीं। इससे पहले जो टैंक बनते थे वे सीपेज हो जाते थे और राइजिंग मेन में पानी नहीं आता था। हमने उस समय के मुख्य मंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी से कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र के लिए पानी की स्कीमें अप्रूव करवाई थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए नाबार्ड के तहत एक 18 करोड़ रुपये की स्कीम अप्रूव हुई थी। जब यह स्कीम बनकर तैयारा होगी तो इससे लोगों के घरों में 24 घंटे शुद्ध पानी रहेगा। ये जो 18 करोड़ रुपये की योजना है इसमें सोहड़ा, तैयारा, वैदी, भड़याड़ा, समीरपुर, समीरपुर चकवन, अब्दुल्लापुर, नन्दरूल, मेहरला, त्रैम्बला, खडयाड़ा, ढुगयारी, तरखयानगढ़ व सलोल के गांवों को शुद्ध जल की व्यवस्था की जानी है। लेकिन जल शक्ति विभाग को भगवान बचाए। इस विभाग का काम पाइपें खरीदना व टैंक स्थापित करना ही है। इस पेयजल योजना का लगभग 99.99 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इसकी राइजिंग मेन बिछ चुकी है और टैंक भी बन गया है। लेकिन जिन 18-20 गांवों को जो इस योजना के तहत 24 घंटे पानी मिलना था वह अभी तक नहीं मिल पा रहा है। आपने उस योजना में करोड़ों रुपये की पाइपें बिछा दी हैं। पहले राइजिंग मेन को खुदाई करके बिछाया जाता था। जहां कहीं हार्ड रॉक हाती थी वहां राइजिंग मेन दबाई नहीं जाती थी। उस 18 करोड़ रुपये की योजना में भी राइजिंग मेन बिछ गई है। खड्डों व नालों में कुछ पाइपें ओपन डाली गई हैं। वहां

09.09.2024/1510/rks/AS-2

पर टैंक भी बन गए हैं लेकिन इस योजना से वहां की जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। उस स्कीम का सोर्स किसानों की कूहल से लिया गया है। जब आप इतनी बड़ी योजनाएं तैयार कर रहे हैं तो पहले आपको पानी का सोर्स देखना चाहिए तब जाकर आगे पैसा खर्च करना चाहिए। हमारी जनता को इस योजना से 24 घंटे पानी देने का प्रावधान था लेकिन अब उस योजना का हमारी जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं उप मुख्य-मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इसमें जो-जो कमियां हैं उन कमियों पर गौर किया जाए। दूसरी पेयजल योजना दौलतपुर-जुलाड़ी चंगर एरिया के लिए है। इससे पहले चंगर एरिया के लिए इतनी बड़ी योजना स्वीकृत नहीं हुई थी। हमने मेहनत करके दौलतपुर, तकीपुर, धबेड़, कुलथी, हारजलाड़ी, जनयान खड्ड, चौंधा, समेला, सकोट, तरसू,

श्री बी.एस. द्वारा ... जारी

09.09.2024/1515/बी.एस./ए.एस-1

श्री पवन कुमार काजल जारी...

इसी तरह की स्थिति जो मैं आपको दूसरे प्रोजैक्ट की बात बताना चाहता हूं कि समीरपुर-तियारा की है। पाइपें आई, पाइपें डल गई, टेंक बन गए लेकिन जब पानी का स्त्रोत देखा तो वहां पानी ही नहीं है। मैं आपके ध्यान में कांगड़ा विधान सभा के चंगर एरिया की बात करना चाहता हूं, जो गांव मैंने बताए वहां पर अढ़ाई-अढ़ाई महीनों तक पानी से वंचित रहना पड़ता है। आप करोड़ों रुपया खर्चेंगे फिर भी पानी से जनता को वंचित रखा जाएगा तो यह किस तरह की व्यवस्था है और किस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन है? मंत्री महोदय जी को पता है कि इसी पेयजल योजना में जो जे.ई. राजेश ऑन ड्यूटी बह गया था और उसकी दुःखद मृत्यु हो गई थी। मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहा रहा हूं कि आपने उनके घर में जा करके वायदा भी किया था कि इसे एज ए स्पेशल केस बना करके इनके बच्चों को नौकरी का प्रावधान करेंगे। ताकि ऑन ड्यूटी जो राजेश कुमार जी की मृत्यु हुई है उनके परिवार का जीवन-यापन हो सके। आपको इस बात का ध्यान होगा कि आपने कैबिनेट से स्पेशल इसके लिए बोला हुआ था। अध्यक्ष जी, मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहा रहा हूं कि यहां पर अधिकारी भी बैठे हैं, हम भुगतभोगी हैं। कांगड़ा विधान सभा का जो क्षेत्र पड़ता

है उसका डिवीजन शाहपुर में है और मुझे लगता है कि तीन-चार विधान सभाओं को छोड़ कर सभी जगह अपने-अपने डिवीजन हैं। पिछली सरकार में माननीय जय राम ठाकुर जी की सरकार में कांगड़ा को डिवीजन दिया गया था। परंतु आपकी सरकार में वह डी-नोटिफाई हो गया। मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि जिला कांगड़ा में 15 विधान सभा चुनाव क्षेत्र हैं और यहां पर कांगड़ा विधान सभा चुनाव क्षेत्र ही बचता है जिसे आपने डी-नोटिफाई किया है। कृपया, उसे नोटिफाई करने की कृपा करें। ताकि कांगड़ा की जनता और कांगड़ा के लोग इससे लाभान्वित हो सकें। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहा रहा हूं कि पेयजल योजना खोली है, यह भी 3.50 करोड़ रुपये की नाबार्ड से अप्रूव हुई है और इसका काम चला हुआ है। मैं विभाग से और मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसकी सही ढंग से देख-रेख की जाए, ऐसा न हो कि पाइपें डल गईं, क्रेट लग गए, प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग हो गई परंतु बाद में जनता को पानी न मिले। इसी तरह पेयजल योजना कोहाला की एस.सी. कंपोनेट में योजना है इसमें 2.50 करोड़ रुपये की जो भी जल शक्ति विभाग ने स्कीम बनानी है उसे सही ढंग से बनाए। अध्यक्ष

09.09.2024/1515/बी.एस./ए.एस-2

जी, मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि साथ लगती कांगड़ा टाउन की सीवरेज योजना है वह वर्ष 2001 से चली है। अब उसका 95-96 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। परंतु कांगड़ा की जनता उस सीवरेज सिस्टम से इतनी परेशान हुई कि जब से शुरू हुई इसमें अनेकों ठेकेदार आए और कई उलटी पाइपें डाल करके चले गए और कई सीधी पाइपे डाल गए। इसलिए उस योजना का सही ढंग से कार्य नहीं हो पाया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि साथ लगते 66 करोड़ रुपये सीवरेज योजना अप्रूव हुई है। आने वाले कल को जो यहां पर घटकरी है, बीरथा है, जागीपुर है और नटेहड़ के गांवों को इस सीवरेज योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए इसे सही ढंग से बनाया जाए, यही मैं कहना चाहता हूं। मंत्री जी के ध्यान में मैं एक और योजना लाना चाहता हूं कि पीने के शुद्ध पानी के लिए ठाकुर द्वारा, संघायिलां रजियाणा, मंड, रानीताल, भंगवार और सुकाबाग के लिए योजना है। इसका पिछले पांच-छह सालों से काम चला हुआ है। जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैं उप-मुख्य मंत्री जी से कहना चाह रहा हूं कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि कांगड़ा ही

डिवीजन के बिना रहता है। जो आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने हमारा डिवीजन खोला थी, उसे कृपया खोल दीजिए ताकि हमारी ये परियोजनाएं चली हुई हैं इनकी सही ढंग से देखरेख हो सके। मैं आपके ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूं कि यह

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

09.09.2024/1520/डी0टी0/डी0सी0-1

श्री पवन कुमार काजल जारी...

ठीक है हम विपक्ष में हैं। लेकिन हमारे पानी का डिवीजन शाहपुर में है। कांगड़ा में जो Providing and Fixing टूलकिट, जैसा पिछली सरकारों में भी होता रहा है, जो मैं नाम ले रहा हूं, वाई0एम0 सेल्स जिसके मालिक योगश महाजन है, ये टूलकिट देते हैं और Providing and Fixing करते हैं। इन लोगों ने पूरे प्रदेश में जल शक्ति विभाग को बदनाम कर दिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की Providing and Fixing हुई है। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से ये कहना चाहूंगा कि क्या सच में ही 1 करोड़ रुपये की Providing and Fixing हुई है?

(उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

इसकी आप जांच करवायें और इसके लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उनको सजा दिलवायें। आपने 18-18 करोड़, 25-25 करोड़ रुपये की पानी की पाइपें बिछा दीं पर उसके लिए सोर्स नहीं देखे गये, ये बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था, आप इसकी जांच करवायें। लोग पानी के संबंध में जब हमें कहते हैं तो उसके लिए कहीं सोर्स ही नहीं है। ये Buy and Sale का मामला है। ये वे लोग हैं जो दो दुनी चार करते हैं और इन्होंने पूरे प्रदेश में लूट मचा रखी है। पानी की स्कीमों में, यहां मैं खासकर दौलतपुर-जलाड़ी की स्कीम का उल्लेख करना चाहता हूं, इस स्कीम में ठेकेदार पाइपें बिछा कर चले गये। इसके लिए जब मैंने विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि हमनें ठेकेदार को कह दिया है। लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में ये भी लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी व सिवरेज के जो on going काम हैं, इसमें बहुत धांधलियां हुई हैं, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी धांधलियां आगे से न हो, कृप्या मंत्री जी इसका संज्ञान लें। मैं एक बात बार-बार कहता आ रहा हूं कि कांगड़ा में भी जल शक्ति डिवीजन की बड़ी आवश्यकता है। कांगड़ा के

जिले की 15 में से 14 विधान सभा क्षेत्रों में तो आपने डिवीजन खोल दिए हैं, इसलिए आप कांगड़ा में भी डिवीजन खोल दें।

उपाध्यक्षः अब माननीय उपमुख्य मंत्री जी इस प्रस्ताव का उत्तर देंगे।

09.09.2024/1520/डी0टी0/डी0सी0-2

उपमुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री पवन काजल जी ने नियम-62 के अंतर्गत कांगड़ा विधान सभा में पानी की योजनाओं के बारे में इस सदन का ध्यान आकृषित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य by choice विपक्ष में हैं। हम तो चाहते थे कि ये पॉवर में हों। आज ये इस साइड होते तो ये पॉवर में होते। अब पता नहीं कब इनको श्री जय राम जी मिल गये, कब इनको हमारे बीच में से ले गये? चलो हम इस बात से भी खुश हैं कि आप विपक्ष में बैठकर भी पॉवर में हैं। श्री पवन काजल जी पहले हमारे साथी थे, सहयोगी थी और दोस्त भी थे। हम राजनीति क्षेत्र के लोग हैं हम राननीति के क्षेत्र में एक दूसरे के विरोधी है लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है और हमारी विचारधारा अलग हो सकती है। लेकिन हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। जो मसले माननीय सदस्य श्री पवन काजल जी ने इस सदन में उठाएं हैं, मैं सबसे पहले इनकी सबसे बड़ी चिंता जो है, कांगड़ा के सभी विधान सभा क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग के डिवीजन हैं, लेकिन इनके विधान सभा क्षेत्र में जल शक्ति का डिवीजन नहीं है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलवाना चाहता हूं कि हम प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में डिवीजन खोलने के पक्षधर हैं।

श्री एन0जी0द्वारा जारी
09-09-2024/1525/डी.सी.-एन.जी/1

उप मुख्य मंत्री.....जारी

यह एक्सर्साइज हम बहुत जल्द पूरी कर लेंगे। **68 विधान सभा क्षेत्रों में से कोई भी विधान सभा क्षेत्र बिना डिविजन के नहीं रहेगा। माननीय सदस्य का मामला हमारे विचाराधीन है और जैसे ही उस पर फैसला होगा मैं इन्हें अवगत करवा दूंगा।** हम चाहते हैं कि हर माननीय विधायक के विधान सभा क्षेत्र में उसकी अपनी डिविजन हो ताकि किसी भी डिविजन में अन्य विधायक का दख़ल न हो सके। इसमें कांगड़ा, डलहौजी आदि को मिलाकर कुल चार विधान सभा क्षेत्र ही बचे हैं। हम इस प्रस्ताव पर गौर कर रहे हैं।...(व्यवधान) यह तो बड़े लोगों की बड़ी बाते हैं। ये सभी डिविजन हमारे विचाराधीन हैं और हम विधान सभा क्षेत्र अनुसार डिविजन खोलने के पक्षधर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जल शक्ति विभाग पर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी और मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि जल शक्ति विभाग लगभग 12 हज़ार योजनाएं चला रहा है। प्रदेश की पूरी जनसंख्या को हम पानी दे रहे हैं। पीने का पानी व खेत का पानी दे रहे हैं। सिवरेज़ व ड्रेनेज का बंदोबस्त कर रहे हैं। इसके अलावा हम खड्डों व नदियों की चैलेलाइजेशन भी कर रहे हैं। यह कहना कि किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है तो यह ठीक नहीं है। 70 लाख से ज्यादा की आबादि को पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है और जल शक्ति विभाग जब से अस्तित्व में आया है तब से इसने बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं। मैं इस वाद-विवाद में नहीं जाना चाहता क्योंकि जल जीवन मिशन पूर्व सरकार के समय में आया, पाइपें भी पूर्व सरकार के समय में खरीदी गई थीं और उन्हें बांटा भी पूर्व सरकार के समय में गया था। पाइपों को डिग भी पूर्व सरकार के समय में किया गया था। वे पाइपें अच्छी थी या बुरी थी और अब आप चाहते हैं कि मैं सभी के पीछे लठ लेकर जाऊं। यह मेरी फितरत में नहीं है और न ही मैं इसमें जाना चाहता हूं। आपने जो किया वह आपको मुबारिक हो और हमसे जो हो पाएगा वह हम करेंगे।

09-09-2024/1525/डी.सी.-एन.जी/2

पूर्व सरकार के समय में 5500 करोड़ रुपये से अधिक की पाइपें खरीदी गई थीं। अब आप कह रहे हैं कि पाइपें टूट रही है, पाइपें अच्छी नहीं हैं, नकली हैं या असली हैं, अब यदि इसी पोस्टमार्टम में फंसे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम आगे बढ़ें। हमने फिनां सिंह परियोजना के लिए धनराशि स्वीकृत करवाई। यह योजना पिछले 12 साल से लटकी पड़ी थी और उस पर 300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो चुका था। इसके लिए मैं स्वयं केन्द्र सरकार के पास गया और पूर्व जल शक्ति मंत्री व वर्तमान जल शक्ति मंत्री जी से मिला तथा अब फिनां सिंह परियोजना के लिए धनराशि स्वीकृत हो चुकी है ताकि हम उस परियोजना को पूर्ण कर सकें। सुखाहार परियोजना के लिए भी हम केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री जी से मिल कर आए हैं और इसके लिए उनसे लगातार बात कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के पैसे के लिए भी हम केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री व केन्द्रीय सचिवों से मिले हैं, हमने उनके साथ बैठकें भी की हैं और हम इसका पैसा लाने की कोशिश कर रहे हैं। पी.एम.के.एस.वाई. की हमारी योजनाएं रुकी पड़ी हैं और इसके लिए भी धनराशि जारी करवाने हेतु हम केन्द्र सरकार से बात करके आए हैं। इन तीनों योजनाओं को लेकर केन्द्र सरकार हमारी ओर सकारात्मक रवैया अपना रहा है और मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्दी यह पैसा मिल जाएगा। माननीय सदस्य सुबह नाबार्ड की योजनाओं का मसला उठा रहे थे। जल शक्ति विभाग के अंतर्गत एक भी पानी की योजना ऐसी नहीं है जिसे हमने साइन करके नाबार्ड को न भेजा हो। आप (विपक्ष) एक भी योजना का नाम बता दें कि फलां एम.एल.ए. की योजना मंत्री के पास गई थी और उसने उस योजना को लम्बित रखा हुआ है। जिस किसी की भी योजना जितने भी अमाऊंट की आई है वे सभी हमने नाबार्ड को भेज दी हैं। माननीय सदस्य ने एक रेलिवेंट सवाल किया है और मेरे ध्यान में भी आया है कि डिविजन में ऐसे काम हुए जो नहीं होने चाहिएं थे। उपाध्यक्ष महोदय, विभाग बने हुए हैं। ग्रामीण विकास का काम ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग करेगा। सड़कें बनाना हमारा काम नहीं है। सड़कें बनाना लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग का काम है। हमारे अफसर कहां से बीच में फंस गए कि वे सड़कें बना रहे हैं, डंगे लगा रहे हैं या शमशान घाट बना रहे हैं। मैं इनकी पेमेंट रोकता हूं।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

09.09.2024/1530/केएस/एचके/1

उप-मुख्य मंत्री जारी---

और यह जारी नहीं की जाएगी। जिन ऑफिसरों ने ऐसा काम किया है, उसकी सजा वे भोगेंगे। जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जिन्होंने भी ऐसी सड़कें बनाई हैं, ऐसे डंगे लगाए हैं या शमशान घाट बनाए हैं, जो हमारे एरिया ऑफ ऑप्रेशन में ही नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके वेतन से पैसा काटूंगा। जो लोग ज़रूरत से ज्यादा चाटुकारिता दिखाते हैं, ज़रूरत से ज्यादा लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि हमारा एरिया ऑफ ऑप्रेशन क्या है? हम सड़कें बनाने वाले नहीं हैं। सड़के बनाने वाली और एजेंसिज़ हैं। इसलिए जो भी आपने कहा, एक करोड़ या दो करोड़ रुपये, पेमेंट मैंने रोक दी है, वह रुकी रहेगी जब तक उस मसले की पूर्ण जांच नहीं की जाती।

उपाध्यक्ष महोदय, दो योजनाएं इनके दिल के बहुत करीब है जो कि मुझे भी मालूम है। एक समीरपुर-तियारा और दूसरी दौलतपुर-जलाड़ी। मैं दुर्भाग्य ही कहूंगा कि दोनों योजनाओं को 18-18 करोड़ रुपया खर्च करके भी हम लॉजिकल एंड तक नहीं ले जा पाए हैं। जो इसके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलने चाहिए थे, वह आपको नहीं मिले हैं। उसकी एक वजह तो यह भी है कि जो आपकी दौलतपुर-जलाड़ी, जिसका आपने ज़िक्र भी किया कि उसमें हमारे जुनियर इंजीनियर श्री राजेश जी बह गए थे। आपने उसका जो मसला उठाया, **मैं आपको इस माननीय सदन में आश्वासन देना चाहता हूं कि ऑन डियूटी उनकी डैथ हुई है इसलिए उनके परिवार को सारे नियमों में छूट देते हुए नौकरी दी जाएगी।** क्योंकि फोरैस्ट में भी ऐसे केसिज़ में जिनकी फोरैस्ट फायर में डैथ हो गई थी, जल गए थे, उनको नौकरियां दी गई हैं, ऐसी प्रथा है और उस बात को देखते हुए इन जे.ई. के परिवार को भी हम नौकरी देने के लिए कमिटिड हैं। बाकी जो आपने कहा कि 18-18 करोड़ रुपये लगने के बावजूद भी दौलतपुर-जलाड़ी जो है, यह जल जीवन मिशन में डाल दी गई थी। आपको 24 करोड़ रुपये के आसपास 10 योजनाएं जल जीवन मिशन से मिलीं जिनमें से 8 का काम तो पूर्ण हो गया था। दो योजनाएं, एक दौलतपुर-जलाड़ी और एक पेयजल योजना खोली है। इनमें एक का 98 प्रतिशत कार्य यानी लगभग इसका कार्य पूर्ण ही हो चुका है और यह योजना कमिशन हो चुकी थी लेकिन बरसात आने की वजह से उसके सोर्स वगैरह को नुकसान हो गया। मैं **आपको दोनों योजनाओं के बारे में विश्वास दिलाना चाहता**

09.09.2024/1530/केएस/एचके/2

हूं कि जल्दी ही इन दोनों योजनाओं को हम चला कर दे देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक योजना के बारे में इन्होंने कहा कि वह बनेर खड्ड से चलाई जा रही थी। उसमें भी हम चेंजिज़ कर रहे हैं। उसके सोर्स ठीक करेंगे और मेरे ऑफिसर्ज़ आपसे मिलेंगे और मिलने के बाद दोनों योजनाओं का, सोर्स को ले कर जो भी डिस्प्यूट है, जो पानी ठीक नहीं आ रहा है, वह हम ठीक कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने सीवरेज की बात की। हमने अभी 10 करोड़ रुपये का अगस्त, 2024 में एस.टी.पी.अवार्ड किया। इसमें भी हम आपको डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी दे देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पानी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और खासकर मेरे दोस्त हमारी कार्य प्रणाली से निराश नहीं होने चाहिए। हम चाहेंगे कि जो भी आपके रिलेवेंट प्वाइंट्स हैं, काजल जी, असलियत तो यही है कि शाहपुर और आपका डिविज़न इकट्ठा है और एक सदस्य सरकार में बैठे हैं और एक विपक्ष में बैठे हैं। जब तक यह डिविज़न नहीं होगा, तब तक थोड़ी दिक्कतें रहेंगी लेकिन हम बहुत जल्दी इसका निवारण करेंगे। जो-जो मसले आपने सदन के समक्ष लाएं हैं उनका हम निवारण करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप डिपार्टमैंट और मिनिस्टरी के बारे में धारणा अपनी सही करें। हम बहुत बड़ी आबादी को पानी देते हैं, यह मेरा कहना है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : पवन काजल जी, क्या आप कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं? ...(व्यवधान) इसमें कोई चर्चा नहीं होती।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी...

09.09.2024/1535/av/hk/1

उपाध्यक्ष : अब माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी नियम-62 के तहत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय उप-मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

श्री विपिन सिंह परमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम-62 के तहत बनेर खड्ड पर बनी 18 किलोमीटर की लम्बी सिंचाई योजना के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया हूं। मैंने नियम-62 के तहत न्यूगल खड्ड से निकलने वाली तमाम कूहलें, जिनसे सुलह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तक पानी पहुंचता है, उसका भी ज़िक्र किया था। मैं इन सारे विषयों को आपके सामने रखना चाहता हूं। यह 18 किलोमीटर लम्बी कूहल है जो जिया के नज़दीक बनेर खड्ड से चलती है। यह वर्षों पुरानी कूहल है और दरंग, धोरन, घनेटा, महादेव, बरांकड़, लूधरा इत्यादि ऐसे अलग-अलग गांवों की लगभग 3 हजार कनाल जमीन को सैलाब करती है। हमने वर्ष 2019 में प्रदेश सरकार के समक्ष एक विषय लाया था कि बहुत लम्बी दूरी है। इसलिए नाबार्ड या किसी और केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत इसमें एच0डी0पी0 पाईप डाली जाए। उसका काम शुरू हुआ और मैं स्वयं मौके पर जाता था तथा साथ में अधिकारी भी जाते थे। हमने उस काम को समयबद्ध तरीके से पूरा करवाया। परंतु जब हमने उस बनेर खड्ड के पानी को पाइप्स में डाला तो वह पानी लास्ट गांव बरांकड़ तक पहुंचना था, मगर उन पाइप्स के जगह-जगह पर ज्वाइंट्स ब्रस्ट हो गए। मैंने उस समय भी अधिकारियों से पूछा था कि यह पाइप्स कहां से आई और इस काम को करने वाला ठेकेदार कौन है। मगर उस काम में गंभीरता नज़र नहीं आई और उसके उपरांत पिछली भारी बरसात के बाद उस कूहल में भारी डैमेजिज आ गए। उस कूहल में मिट्टी भर गई। वहां जगह-जगह लैंडस्लाइड के कारण जो डंगे लगे थे वे क्षतिग्रस्त हो गए। वहां के किसान बहुत जागरूक हैं और वे बार-बार अधिकारियों से मिलते हैं परंतु इस बनेर खड्ड का पानी दरंग, धोरन, घनेटा के किसानों के खेतों में नहीं पहुंच पा रहा है। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस पर 4 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि खर्च हुई है। उस पाईप का लगभग 16 ईंच का डाया था। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस बारे में जरूर आश्वासन देंगे ताकि उस इलाके के किसानों को हर मौसम में पानी मिल सके। मैं उप-मुख्य मंत्री जी के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं क्योंकि यह मामला बहुत

पुराना है। हिमाचल प्रदेश में जब माइक्रो हाईडल प्रोजैक्ट की बाढ़ आई थी तो हमारी जो पुरानी कूहलें थीं, उनके बारे में सर्वे किया गया। आज से 17-18 वर्ष पहले उन अधिकतर कूहलों को जहां से पानी आता था वहां पर मिनि माइक्रो हाईडल प्रोजैक्ट्स बना दिए। मैं दूसरे माइक्रो हाईडल प्रोजैक्ट्स की बात नहीं करूंगा मगर जिया के साथ 2 किलोमीटर की दूरी पर एक हाईडल प्रोजैक्ट बना है और वे सारे-का-सारा पानी अपने रैज़र्वायर में ले जाते हैं। वहां पर उनके नाइट वॉचमैन होते हैं। यह कोई हैदराबाद का व्यापारी है जो मनमानी करता है। मैंने इस संदर्भ में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहा।

टी सी द्वारा जारी

09.09.2024/1540/टी0सी0वी0/वाई0के0-1
श्री विपिन सिंह परमार..... जारी

मेरा उप मुख्य मंत्री जी आपसे निवेदन है कि आपकी मध्यस्थता के माध्यम से यह तय हो कि जितना पानी इस कूहल के लिए कथुल्ल कूहल के एग्रीमेंट के अनुसार छोड़ा जाना है, वह छोड़ा जाना चाहिए। इस ध्यानाकर्ष प्रस्ताव में मैंने न्यूगल खड्ड से निकलने वाली कूहलों का भी जिक्र किया है। सुलह विधान सभा क्षेत्र में लगभग 15 कूहलें हैं जो न्यूगल-बंदला से चलती हैं परंतु आज वे सारी-की-सारी कूहलें बंद पड़ी हुईं हैं। इनमें सबसे बड़ी कूहल, मेरे एक साथी कह रहे थे कि श्री शांता कुमार जी भी कभी इस सदन में थे, वे भी कृपाल चन्द कूहल का जिक्र करते थे लेकिन आज नौबत यह आ गई है कि तब उस कूहल में पानी भरकर चलता था, परंतु आज वहां किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। उस कूहल से किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार पानी मिले यह बात हम बार-बार जल शक्ति विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ करते हैं लेकिन उनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। जो कूहल बंदला-पालमपुर से चलती है जिसको हम कृपाल चन्द कूहल कहते हैं, यह लगभग 28 किलोमीटर लम्बी कूहल हैं। कभी इस कूहल का पानी थुरल लगभग 35 किलोमीटर तक पहुंचता था परंतु उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि ये तमाम कूहलें वर्ष 2023 में पालमपुर मण्डल के पास होती थीं। आज वे सारी-की-सारी कूहलें थुरल डिवीजन में बदल दी गईं हैं। मेरा कहना यह है कि रसोई कहीं पर है, पैंठें कहीं पर लगी हुईं हैं यानी इन

कूहलों का नियंत्रण पालमपुर डिवीजन के पास है और जब पैंठें कहीं लगी हुई हैं तो कहां से राशनिंग होंगी, कहां से खाना मिलेगा? इसलिए आज आप नीतिगत फैसला कर लें या तो इन तमाम कूहलों को चाहे वह प्रवाह सिंचाई योजना सिंगार चंद कूहल हैं, चाहे फ्लो इरिगेशन पुटनूल कूहल है उनको भी पालमपुर को दे दीजिए। मियां फतेहचन्द और दाई-दी-कूहल इन सारी-की-सारी कूहलें आप पालमपुर डिवीजन को दे दीजिए क्योंकि यह निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है। मुझे बताया गया कि जब ये कूहलें डिवीजन थुरल को दी गईं तो एक-एक कर्मचारी भेजा गया और ऐसे कर्मचारी भेजे गए जो रिटायरमेंट ऐज पर बैठे हुए हैं। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि इन तमाम कूहलों को चाहे थुरल डिवीजन में दे दीजिए, चाहे पालमपुर में दे दीजिए। यह जो पीने के पानी की योजना है, अब तो सुलह विधान क्षेत्र में जल जीवन मिशन के बाद पानी की समस्या खत्म हो गई है। ये

09.09.2024/1540/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

जो पीने के पानी की स्कीम न्यूगल से चलती है उसका जो रेजरवायर है, उसका जो ट्रीटमेंट प्लांट है वह चौकी में है जो श्री आशीष बुटेल जी का विधान सभा क्षेत्र है। पानी बंदला से आता है और फिर वह पानी वहां पहुंचता है। पानी कितना नीचे भेजना है, अगर पानी ड्रिंकिंग वॉटर सप्लाई के लिए पूरा होगा तब तो ठीक है यदि यह उसके लिए पूरा नहीं होगा तो इसके कारण इरिगेशन स्कीम की एक कूहल मृत हो गई है। एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं कि इन तमाम कूहलों के लिए, क्योंकि कूहलें सुलह में नहीं, ये धौलाधार के नीचे जितने भी विधान सभा क्षेत्र हैं यानी नूरपुर विधान सभा क्षेत्र से लेकर जोगिन्द्रनगर तक खड्डों-नालों से फ्लो इरिगेशन की स्कीमें बनाईं गई हैं।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

09-09-2024/1545/एन0एस0-वाई0के0/1

श्री विपिन सिंह परमार-----जारी

लेकिन अधिकतर की दशा बहुत खराब हो चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप इन कूहलों के रखरखाव के लिए कोई नीति बनाएं। कभी ये कूहलें किसानों के पास हुआ करती थीं। किसान उठते थे और पालमपुर पहुंच जाते थे। आज किसान हैं पर ये सारी सरकारी कूहलें आपके विभाग के पास हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज किसानों की मजबूत कमेटियों का गठन हो और कूहल की रक्षा करने के लिए कूहल रक्षक बनाए जाएं, चाहे कैजुअल लेबर ही हो। जो कूहल 25 किलोमीटर चलती है, कथुल्ल कूहल 18 किलोमीटर चलती है तो यह किसके सहारे चलेगी? हम एक्सिअन और जे0ई को फोन करते हैं तो वे हमें बतियाते हैं। वे हमें इसलिए बतियाते हैं कि हम पानी छोड़ेंगे। आज भी हमारे लोग इस मुहिम में लगे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस इलाके के तमाम किसानों को न्याय मिलना चाहिए। मैं मंत्री जी के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं कि इन तमाम कूहलों में मैंझा, ऊपरला मैंझा, बुहला कटयाड़, फरेड़, सुलह, सालन, रैपर, बटारल, ननाऊं, कंकड़ें, पंतेहड़, गरला देई, रड़ोता, रक्कड़, पुरल, भेड़ी, मण्डप, सुलह कस्बा, गंडोरल, मौरला, फरेड़, समूला, सालन, जसूं, बटारल, रैपर खास, कस्बा लाड़ तड़ाह, मजाकड़ा, नगेड़, बल्लाह, चौकी, पंतेहड़, मनसिंबल, मनसिंबल लोअर, संथेहड़, बोद्धा, हैंजा, ओडर, हार बोद्धा, गंडेसर और भाडल देवी आदि तमाम गांव इन कूहलों से कवर होते हैं। पालमपुर से इन गांवों की दूरी 12-14 किलोमीटर है। इसलिए उप-मुख्य मंत्री महोदय, आप हमें आज आश्वस्त करें। मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या काफी हद तक सॉल्व हो गई है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह विषय इससे संबंधित नहीं है लेकिन जो स्कीमें सैंक्शंड थीं तो चुनावों के बाद वहां पर ठेकेदार छोड़ कर चले गए हैं। आप एस0ई0 साहब से कंप्लीशन रिपोर्ट मंगवाएं। कागजों में नलके लग गए हैं पर नलके दिखते नहीं हैं। उप-मुख्य मंत्री जी, एक इंच की पाइप सुलह डिवीजन से उठा कर कहीं और भेज दी कि यहां पर विपक्ष का विधायक बैठता है। मैं चुप रहा। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे साथ क्यों जयादती हो रही है? आप यहां पर जल जीवन मिशन में सुलह विधान सभा क्षेत्र की तमाम योजनाओं की रिपोर्ट मंगवाएं। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं।

09-09-2024/1545/एन0एस0-वाई0के0/2

उपाध्यक्ष महोदय, कूहलों पर बहुत अतिक्रमण हुआ है। एनक्रोचमेंट हुई है। उप-मुख्य मंत्री जी, आप रिपोर्ट मंगवाएं कि डिपार्टमेंट के पास एनक्रोचमेंट के कितने केसिज आए हैं? यहां पर सेप्टिक टैंकों के कनेक्शन भी इन कूहलों में दे दिए हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मैंने आपके ध्यान में ये विषय लाए हैं तो आप मुझे आश्वस्त करेंगे और इन तमाम कूहलों के बारे में कोई नीतिगत फैसला ले करके इस सदन के सभा पटल पर एश्योरेंस देंगे कि आप इन अलग-अलग कूहलों के लिए डी0पी0आर0 तैयार करवाएंगे। ये कूहलें बारह मासी बनें उसके लिए चाहे आप जल रक्षक के रूप में कूहल रक्षक रखें ताकि यह पानी किसानों के खेतों तक पहुंच सके। यहां पर कहा गया है कि हर विधान सभा क्षेत्र में डिवीजन होना चाहिए, यह अच्छी बात है। पिछली सरकार श्री जय राम ठाकुर जी के समय में मेरे क्षेत्र को भी सर्किल ऑफिस दिया गया था। यह ऑफिस किस लिए दिया गया था? इसलिए दिया गया था कि कंप्रिहेंसिव विकास के लिए हमें धर्मशाला न दौड़ना पड़े। यह बात ठीक है कि धर्मशाला हमारा जिला मुख्यालय है और जिले का केंद्र है। उस समय श्री जय राम ठाकुर जी ने कहा कि जल जीवन मिशन में बहुत-सा पैसा आ रहा है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का बहुत पैसा आ रहा है और आप धर्मशाला क्यों जाएंगे?

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

09.09.2024/1550/rks/AG-1

श्री विपिन सिंह परमार ...जारी

सुलह, पालमपुर, बैजनाथ और नगरोटा के लोगों के लिए हमने जल शक्ति विभाग का सर्किल खोला था लेकिन आपकी सरकार ने उस सर्किल को बंद कर दिया है। मेरा आग्रह है कि आप उस सर्किल को पुनः खोल दें। मैं विपक्ष में बैठा हूं इसलिए थूरल में जितना भी स्टाफ है उसे आप उठाते चलो। जहां नया डिविजन बना है वहां यहां से जे.ई., सुपरवाइजर व फील्ड स्टाफ के कर्मचारियों को ले जाओ। मैं तो कहता हूं कि आप सारे स्टाफ को ही ले जाओ लेकिन मैं चौक में खड़ा होकर कहूंगा कि हमारे साथ धोखा हो रहा

है। आप जहां पर नये कार्यालय खोल रहे हैं वहां पर उसके अनुरूप स्टाफ की व्यवस्था भी होनी चाहिए अन्यथा बड़े दफ्तरों को देखकर लोग खुश नहीं होंगे। लोगों को सुविधा चाहिए और यदि लोगों को सुविधा न मिले तो यह उचित बात नहीं है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि जब आपके पास इस प्रकार के पत्र आएं तो आप थूरल डिविजन का विशेष ध्यान रखें। आपके मन में द्वंद है कि जल शक्ति विभाग का सर्किल भवारना खोलें या पालमपुर परंतु मेरा आग्रह है कि आप इस द्वंद को खत्म कर दें। बादल छंट जाएंगे। श्री जय राम ठाकुर जी ने भवारना में जल शक्ति विभाग का सर्किल दिया है। वह सर्किल कार्यशील हो गया था। वहां पर पूरा स्टाफ बैठ गया था लेकिन हमारे साथ फिर यह जादती क्यों हुई? मेरा आग्रह है कि आप इस जादती को सहूलियत में बदलने की कोशिश करें। हमें आपसे और कोई शिकायत नहीं है। सुलह विधान सभा क्षेत्र में पीने-के-पानी की योजनाएं अच्छी तरह क्रियाशील हैं। सिंचाई योजनाओं के बारे में मुझे जो लगता था उस विषय को मैंने आपके समक्ष रख दिया है। अब आगे आपको आदेश देने हैं। हम इस बारे में सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सड़कों पर लड़ाई लड़ने की नोबत न आएं। दौर एक जैसा नहीं रहता दौर बदल जाता है। आपके कार्यकाल के दो वर्ष पुरे हो चुके हैं। अंतिम वर्ष गिनती का होता है। आप मुझे इस सदन में उन तमाम कूहलों के बारे में आश्वस्त करेंगे कि क्या आप उन सब कूहलों को क्रियाशील करेंगे? इन कूहलों के लिए जो डी.पी.आर. बनेगी उसके लिए आपके अधिकारी आपके आदेशानुसार हमारे साथ बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन आपके अधिकारियों को कई बार डर लगता है कि परमार के साथ बैठकर कोई हमें देख न लें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

09.09.2024/1550/rks/AG-2

उपाध्यक्ष : अब माननीय उप-मुख्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे।

उप-मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, श्री विपिन सिंह परमार जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं इन्होंने इस कुर्सी को भी सुशोभित किया है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं आप मेरी बातों को अन्यथा न लें। आप जिस योजना का जिक्र कर रहे हैं उस योजना को आपने ही बनाया है और आपने ही उसका उद्घाटन किया है लेकिन दोषी

हम हो गए। आप हमारे साथ ऐसा अन्याय मत करें। आप यह कहो कि यह योजना मैंने बनाई थी लेकिन इसमें कुछ खामियां रह गईं। आप कह रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद हमने कुछ नहीं किया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि पैसा आपने ही खर्च किया है। असल में यह 3 निर्वाचन क्षेत्रों का संगम है। माननीय मुख्य संसदीय सचिव, श्री आशीष बुटेल जी यहां बैठे हैं। यह पानी इनके निर्वाचन क्षेत्र से चलता है।

श्री बी.एस. द्वारा ... जारी

09.09.2024/1555/बी.एस./ए.जी-1

उप-मुख्य मंत्री जारी...

और फिर आगे आ करके नगरोटा चुनाव क्षेत्र के माननीय सदस्य भी यहां पर होंगे, वहां पर चला जाता है। उसके बाद यह माननीय सदस्य के हलके में 18 मिलोमीटर के बाद पहुंचता है। जब इस स्कीम को बना रहे थे तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि आपकी तूती बोल रही थी और आपने ऐसा क्यों कर दिया कि टेल एंड पर पानी अपने को लिया? आपने कोई ऐसी योजना प्रस्तावित करनी थी जिससे सबसे पहले आपको पानी आता और फिर कहीं और जाता। अध्यक्ष जी होता क्या है कि पालमपुर से आदरणीय आशीष जी पानी आगे नहीं आने देते। इनके किसानों को पानी चाहिए। उसके बाद आगे नगरोटा-बगवां के किसान फिर से पानी रोग लेते हैं। माननीय पूर्व अध्यक्ष के चुनाव क्षेत्र में जब तक पानी पहुंचा है तब तक बहुत देरी हो जाती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इनको कष्ट हो रहा है। इनके लोगों को कष्ट हो रहा है। यह 18 मिलोमीटर लंबी परियोजना है। इसमें 15 मिलोमीटर तक तो पानी ठीक आ रहा है। पालमपुर का कूहल, कडबू नाला और डंगली नाला है, इसमें साढ़े सात मिलोमीटर तक इनका इलाका आता है और वहां तक पानी ठीक आ रहा है। परंतु इसके बाद नगरोटा का गुजरेहड़ एरिया आ जाता है। उनको भी पानी ठीक आता है। लेकिन पानी की समस्या आखिर के पांच किलोमीटर की है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां बीच में लगभग दो नाले आते हैं और ये ओपन हैं। अब पीछे से पानी आता है यहां आ कारके ओपन छोड़ दिया जाता है। यह एक प्रेक्टिकल समस्या है। दूसरा इन्होंने पॉवर प्रोजैक्ट की बात भी की है। जहां तक पॉवर प्रोजैक्ट की बात है, मैं उपायुक्त, कांगड़ा को डायरेक्शन दूंगा कि वह हमारे अधिकारियों को साथ ले करके इस साइट को

विजिट करें। हमारे मुख्य अभियंता वहां जाएंगे और उपायुक्त भी जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पूंजीपति, कोई भी लाला यह नहीं कर सकता कि हिमाचलियों को पानी से वंचित कर दे और न ही हम यह होने देंगे। आपने यह बात ध्यान में लाई है और जो भी कदम हमें उठाने पड़ेंगे, उन्हें हम उठाएंगे। हमारे अधिकारियों की कमेटी उसे विजिट करके आएगी। दूसरा, कूहलों के बारे में जो कहा गया है, आखिर के जो पांच किलोमीटर्ज हैं, अगर आपको लगता है कि कूहलों की मरम्मत करके ही मसला हल हो सकता है तो 45 लाख रुपये का प्राक्कलन इन्होंने दिया है, उस पैसे को हम देगें। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह पैसा लगा करके

09.09.2024/1555/बी.एस./ए.जी-2

भी मसले का हल नहीं हो सकता। तो आप एक बार हमारे अधिकारियों के साथ बैठ लीजिए। मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि आपके पास जाए और आपके पास बैठ करके व्यूज लेंगे। ऐसा न हो कि हम पैसा लगाएं और आप संतुष्ट न हो। इसलिए पहले बैठ करके जो भी निर्णय होगा उसे में लागू कर दूंगा। यह मैं आपको विश्वासन दिलाना चाहता हूं और जिला कांगड़ा की कूहलों की जो टोटल स्थिति है। उसके बारे में जो भी स्टडी हमें करवानी पड़ेगी हम एक्सपट्र्स को हायर करके कांगड़ा की कूहलों को, ये तो मंत्री रहे हैं और मेरे से बहुत वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। इनका बहुत तजुर्बा रहा है।

(अध्यक्ष महोदय, पदासीन हुए)

इनसे भी हम राय ले लेंगे कि कूहलों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। उसके ऊपर कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट तैयार करके हम कूहलों को बचाने का प्रयास करेंगे । यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

09.09.2024/1600/डी0टी0/ए0एस0-1
उपमुख्य मंत्री जारी...

आपने एस0ई0 ऑफिस की बात कही और ये भी कहा कि वह वहां पर खुला था अब वहां से चला गया है, ये सारे मामले हमारे विचाराधीन हैं। अभी हमनें देहरा में सर्कल खोल दिया है। पालमपुर क्षेत्र में सर्कल खोलना हमारे विचाराधीन है सिर्फ आपने ये कहा कि हम भवारना ले गये थे। हमें सिर्फ यही देखना है कि अगर सर्कल पालमपुर में खुला है तो वह ज्यादा लोगों के लिए वह कंवेनिएंट है या भवारना कंवेनिएंट है। अधीक्षण अभियंता का कार्यालय वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि वह धर्मशाला में है। फिर भी अब हमारे तीन सर्कल नूरपूर धर्मशाल व देहरा में बन गये हैं और पालमपुर ऐरिया के लिए हम निश्चिततौर पर विचार करेगें, यह मैं आपको विसवास दिलवाना चाहता हूं।

09.09.2024/1600/डी0टी0/ए0एस0-2

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी।

श्री विपिन सिंह परमारः अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद। माननीय उपमुख्य मंत्री महोदय से मैंने निवेदन किया था कि हमारी बहुत सी कूहलें जैसे कृपाल चन्द कूहल है, पाटनूल कूहल, मीयां फतेह सिंह कूहल है, यह कूहलें पालमपुर से संचालित होती हैं और इसके सोर्स का कंट्रोल भी पालमपुर डिवीजन के पास है। उसमें पालमपुर डिवीजन के क्षेत्रों के खेतों में भी पानी लगता है और सुलह के क्षेत्र के खेतों में भी पानी लगता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि या तो इसका कंट्रोल पूरी तरह से पालमपुर को ही दे दिया जाए या फिर पूरी तरह से सुलह को इसका कंट्रोल दिया जाए। क्योंकि कंट्रोल उनका है कि कितना पानी छोड़ना है और कितना पानी देना है, माननीय मंत्री महोदय जी से मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि कृपा करके आप इसे एग्जामिन करवां लें ताकि पालमपुर का भी भला हो और सुलह विधान सभा क्षेत्र के 15 कूहलों का लाभ जितने भी किसानों को मिलता है उन्हें भी उसका लाभ मिले। कांगड़ा जिले में तो कूहलें ही कूहलें हैं और ये परम्परागत स्त्रोत हैं, बहुत से उठाऊ सिंचाई योजनाएं सफल नहीं हैं, जैसे माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी द्वारा वन रक्षकों की भर्ती की बात कहीं गई है, सरकार कूहलों के संचालन की व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए जल रक्षक की भर्ती विचार करे। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी द्वारा देहरा में सर्कल ऑफिस खोला गया है,इसके लिए इनको बधाई देता हूं लेकिन

जो सर्कल ऑफिस भवारना में खोला गया था उसे पुनः खोलने की अगर आप घोषणा कर देते हैं, उपमुख्य मंत्री जी ने तो मुझे आश्वस्त किया है लेकिन अगर आप भी अपने मुखारबिंद से घोषणा कर दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि कूहलों का नियंत्रण या तो पूरी तरह से पालमपुर के पास रहे या तो पूर तरह से थुरल के पास हो। मैं इस मामले में रिजिड नहीं हूं। बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्षः माननीय उपमुख्य मंत्री जी।

उपमुख्य मंत्री जीः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने विस्तार से उत्तर माननीय सदस्य को दे चुका हूं। लेकिन जो इन्होंने कूहलों के संबंध में व्यावहारिकता की बात की है, let me examine this issue and after consultation with the officer मैं इसके बारे में बता पाऊंगा कि ये कहां कंवेनिएंट है, जहां भी ये कंवेनिएंट होगा हम उसमें अमल करेंगे।

अध्यक्षः अब विधायी कार्य होगा।

09.09.2024/1600/डी0टी0/ए0एस0-3

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरः स्थापना

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 28) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 28) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 28) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 28) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

09.09.2024/1600/डी0टी0/ए0एस0-4

<u>सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं परण</u>

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 27) पर विचार किया जाए।"

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 27) पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 27) पर विचार किया जाए।"

तो प्रश्न यह है कि "अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 27) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2-10 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2,3,4,5,6,7,8,9 और 10 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

पारणः

09.09.2024/1600/डी0टी0/ए0एस0-5

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे "अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 27) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 27) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 27) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि "अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 27) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

"अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 27) पारित हुआ"

श्री एन0जी0द्वारा जारी

09-09-2024/1605/ए.एस.-एन.जी/1

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-130 के अंतर्गत चर्चा होगी। अब माननीय सदस्य, श्री भवानी सिंह पठानिया नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इसी विषय पर माननीय सदस्य, श्री चन्द्र शेखर व श्री केवल सिंह पठानिया जी से भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वे भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। माननीय सदस्य, श्री भवानी सिंह पठानिया जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव करता हूं कि "प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर यह सदन विचार करे।" इसका कोई भी निर्धारित समय नहीं है। लेकिन जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे तो उन्हें 10 से 12 मिनट का सयम दिया जा सकता है। इस पर कोई भी मतदान नहीं होगा और माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर के पश्चात चर्चा समाप्त हो जाएगी। अब माननीय सदस्य, श्री भवानी सिंह पठानिया जी अपना वक्तव्य इस माननीय सदन में रखेंगे।

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछले 10-12 दिन में वित्तीय स्थिति पर बहुत सारी चर्चाएं आपने भी सुनी होंगी और हम भी सुन रहे हैं। एक प्रकार से यह सनसनी फैलाई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसके पीछे क्या कारण हैं और पता नहीं कि वित्तीय स्थिति ठीक है भी या नहीं। मेरे हिसाब से आज यह माननीय सदन जब प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में चर्चा करेगा तब इसमें हमें वित्तीय स्थिति की पृष्ठ भूमि के पीछे काफी सारी चीजों को देखने की भी जरूरत है। एक सरकार का दायित्व व्यवस्था को ढ़ंग से चलाना होता है। इसके अलावा यह भी दायित्व होता है कि हमारे प्रदेश के जनमानस की अपेक्षाएं व अकांक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करे। मैंने पिछले 25-30 साल की स्कैनिंग की है और पाया कि जो भी सरकार

सत्ता में आई उसने प्रदेश के जनमानस, युवा, बुजुर्ग और हर वर्ग की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश की है।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

09.09.2024/1610/केएस/डीसी/1

श्री भवानी सिंह पठानिया जारी---

प्रत्येक सरकार ने वह सब काम करने की कोशिश की जिससे प्रदेश के लोगों की स्थिति बेहतर हो पाए और उनकी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं पूरी हो पाए। हमने क्या-क्या किया, यह मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। प्रत्येक सरकार ने सुविधाएं देने की कोशिश की। हमने संस्थान खोले, एजुकेशन के लिए स्कूल और कॉलेज खोले, युनिवर्सिटीज़ बनाईं, हॉस्पिटल्ज़, सिविल हॉस्पिटल्ज़ और डिस्पेंसरीज़ खोलीं। पशु-औषधालय बनाएं। विभिन्न दफ्तर खोले। हर सहूलियत को जनता की तरफ ले जाने की कोशिश की। ये सारी सहूलियतें पहुंचाते-पहुंचाते वैल्फेयर स्टेट का जो हमारा एक औचित्य होता है, हमने वह भी करने की कोशिश की। हमने मुफ्त राशन तक दिया। आप सभी जानते हैं कि पिछली सरकार ने जाने से पहले मुफ्त बिजली भी दी, मुफ्त पानी भी दिया और यह सब हमने प्रदेश हित के लिए किया। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि वर्ष 1985 के बाद से यह सब करने के बावजूद कोई भी सरकार वापिस पावर में नहीं आई। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और प्रश्न यह है कि हम जो सोचते हैं कि यह जनता की ज़रूरत है, क्या वह असलियत में जनता की ज़रूरत है या नहीं है? 75 लाख की जो हमारी हिमाचल प्रदेश की आबादी है, वह जनमानस सोचता क्या है, उनकी असली ज़रूरतें क्या हैं या उनकी असली आकांक्षाएं/अपेक्षाएं क्या हैं, वह समझना बहुत ज़रूरी है और मैं उसके ऊपर आज थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि हम सभी ने वह करने की कोशिश की जो हमें लगा कि जनता के लिए यह ठीक है। हमने मुफ्त राशन, बिजली, पानी, शिक्षा और हैल्थ केयर दी। सबकुछ मुफ्त दिया लेकिन उसके बाद भी शायद जनता को ये सारे स्टैप्स रास नहीं आए। इसके पीछे की अवस्था को जानने की आज हमें बहुत ज़रूरत है।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1980 से ले कर अभी तक जो इलैक्शन्ज़ हुए हैं, 1977,1982,1985,1990 और बाद के जो चुनाव हैं, जो बच्चा वर्ष 1980 में पैदा हुआ था या जो व्यक्ति उस समय 20-21 साल का था, उसके पास नेता गए, नेता ने उसको बोला कि देखिए, हमारे पास यहां पर सड़क नहीं है, अध्यक्ष जी, मैं आपको फतेहपुर का उदाहरण देना चाहूंगा, 1977 में फतेहपुर के अंदर केवल 9 किलोमीटर की पक्की सड़क थी। उस समय जब हम जनता को जा कर कहते थे कि हम आपकी सड़क बनाएंगे, उनको लगता था कि यह प्रोग्रेस है। उसके बाद वर्ष 1990 में हमने उनका कहा

09.09.2024/1610/केएस/डीसी/2

कि सड़कें आपकी बन गई हैं, अब हम इनके ऊपर बसें चलाएंगे तो उनको लगता था कि यह प्रोग्रेस है। फिर हम वहां पर बिजली ले कर आए, बिजली को थ्री फेज़ किया। उसके बाद हम पानी ले कर आए और ये सारे हमारे प्रगति के बैंच मार्क बनने शुरू हो गए लेकिन जो बच्चा वर्ष 2000 में पैदा हुआ था, उसको अगर मैं वर्ष 2021-22 में कहूं कि बेटा मैं सड़क ले कर आऊंगा तो वह प्रगति होगी तो वह उसको प्रगति नहीं मानता। क्योंकि जब वर्ष 2000 में वह पैदा हुआ था, उसके घर के सामने उस समय सड़क थी और उस पर बसें भी सुचारू रूप से चल रही थीं। उसके घर के अंदर बिजली और पानी भी था। आज उसकी अपेक्षा बिल्कुल भिन्न है। आज फतेहपुर में मेरे गांव के अंदर दो हिंदुस्तान बस रहे हैं। एक हिंदुस्तान वह है जिसको हम सोचते हैं कि हम जो दे रहे हैं वह उसको भायेगा। जैसे कि हम मुफ्त बिजली, पानी और चिकित्सालय देंगे तो वह बड़ा खुश होगा। उसी के साथ एक दूसरा भारत है, यह वह लड़का है जो युवा है। जो फतेहपुर में बैठकर, नंगल, धमेटा या अन्य छोटे-छोटे गांव में बैठकर रिमोट से यू.एस. की कम्पनी में, ऑस्ट्रेलिया की कम्पनी में या यूरोपियन कम्पनीज़ में काम कर रहा है। उसको वे सारी चीजें नहीं चाहिए जो हमें लगता है कि उसे चाहिए। आप देखिए कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं। उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट 24 घंटे की बिजली है। उससे बड़ी रिक्वायरमेंट उसकी यह है कि थ्री फेज़ इलैक्ट्रिसिटी हो जिससे उसका एयर कंडिशनर चलता रहे क्योंकि जब वह एक ज़ूम कॉल पर होता है तो पीछे पंखे की आवाज से वह ज़ूम कॉल की क्वालिटी नहीं देख सकता। उसको वाईफाई चाहिए, हाई स्पीड इंटरनैट सुविधा चाहिए और उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स उस जमाने की रिक्वायरमेंट्स से टोटली डिफरेंट हैं जिस जमाने के

हिसाब से हम अपनी अर्थव्यवस्था को आज नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। 40 से 50 प्रतिशत हिंदुस्तानी या हिमाचली आज वो हैं और उनकी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं वो हैं जिनके ऊपर शायद हम उस तरीके से गौर नहीं कर पाए। पिछली सरकारें उस तरीके से नहीं देख पाई और हम अगर रियल्टी चैक नहीं लेंगे तो आगे भी हम ये ही गल्तियां करते रहेंगे।अध्यक्ष महोदय, मैं अर्थव्यवस्था के ऊपर आता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे यहां पर टोटल 75 लाख की आबादी है। अब यह 75 लाख की आबादी है कौन? आप देखें कि जिसको हम हिमाचली बोलते हैं, जिसके लिए हम काम करते हैं, यह हिमाचल प्रदेश का वासी कौन है। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

09.09.2024/1615/अव/dc/1

श्री भवानी सिंह पठानिया---- जारी

और हमारा पैसा कहां तथा किस पर खर्च हो रहा है यह समझना भी जरूरी है। हिमाचल प्रदेश की लगभग 75 लाख जनसंख्या है जिसमें हमारा एक वर्ग ऐसा है जिसने प्रदेश को सुचारू रूप से चलाने में मदद की है। ये वे लोग हैं जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले हमारी बिजली की तारों को ठीक करने पहुंचे होते हैं। जब हमारी कोई स्कीम नष्ट होती है तो अपनी जान को जोख़िम में डालकर वहां पर सबसे पहले पहुंचे होते हैं और ये हमारे सरकारी कर्मचारी हैं। इन्हीं सरकारी कर्मचारियों के बेस पर आज हमारा हिमाचल प्रदेश एक समृद्धशाली राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश हर डवलपमेंट एक्टिविटीज में एक टोप की स्टेट इसीलिए बना है क्योंकि यहां हमारे सरकारी कर्मचारी हैं। मगर तथ्य यह भी है कि हिमाचल प्रदेश का इस साल का रैवेन्यू रिसिप्ट 42000 करोड़ रुपये आएगा। इसके अतिरिक्त कैपिटल का मिलाकर 55000 करोड़ रुपये के लगभग रिसिप्ट्स हैं। इसके अंदर 24000 करोड़ रुपये यानी 48 प्रतिशत का खर्चा केवल कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी पर खर्च हो रहा है। यह एक हक़ीक़त है और इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। मगर इस सच्चाई का हमारी अर्थ-व्यवस्था पर क्या फर्क पड़ता है, मैं उसके ऊपर बोलना चाहूंगा। अगर सरकारी कर्मचारियों का डैमोग्राफिक सैटअप देखा जाए तो एक घर में दो-

दो, तीन-तीन कर्मचारी भी होते हैं। किसी घर में एक पेंशनर के साथ-साथ दो-तीन सरकारी कर्मचारी भी होते हैं। अगर तीन का गुणा करके इसका हिसाब किया जाए तो इस पर लगभग 15 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्ज का रहन-सहन चलता है। अब अगर इन 15 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्ज को 75 लाख से माइनस किया जाए तो मेरे पास 60 लाख बचते हैं। अब ये 60 लाख हिमाचली कौन हैं? ये वे लोग हैं जिनके ऊपर पेंशन और सैलरी का व्यय नहीं हो रहा। सरकार के पास जो बाकी पैसा बच रहा है उनके ऊपर वह पैसा खर्च होता है। कर्मचारियों की पेंशन, सैलरी, लोन, ब्याज इत्यादि का पैसा पे करने के बाद जितना बचता है वह बाकी 60 प्रतिशत हिमाचलियों पर व्यय होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि 20 प्रतिशत हिमाचलियों पर लगभग 50 प्रतिशत खर्च हो रहा है और 60 प्रतिशत हिमाचलियों पर केवल 20 प्रतिशत राशि खर्च हो रही है। यह आज की हक़ीक़त है। इन 60 प्रतिशत में हमारे किसान-बागवान, जवान जोकि आर्मी में काम करते हैं और इसके साथ-साथ वे लोग हैं जो मनरेगा

09.09.2024/1615/अव/dc/2

की दिहाड़ी लगाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें वे लोग भी आते हैं जो छोटे दुकानदारों के पास व प्राइवेट सेक्टर में करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके छोटे-मोटे व्यापार हैं। यह 60 लाख की जनसंख्या वह है जोकि आपको 5 वर्षों के बाद बता देती है कि हम आपके काम से खुश है या नहीं। हम यह सोचते हैं कि हमारे लोगों का माइंड सैटअप एक तरीके का है परंतु इनका रिएक्शन बिल्कुल भिन्न होता है।

मैं यहां पर आपको एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं। फतेहपुर के पास एक रियाली मण्डी नामक अनाज मण्डी है जोकि आज से लगभग दो-अढ़ाई वर्ष पहले शुरू हुई थी। मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि पिछले साल यह रियाली मण्डी हिमाचल प्रदेश की व्हीट प्रोक्योर में नम्बर वन साबित हुई है। पूरे हिमाचल प्रदेश की व्हीट प्रोक्योर की रियाली मण्डी फतेहपुर में है। अब हुआ क्या, आप जानते हैं कि पिछली बरसात में बाढ़ आई थी। हमारी एक लाइफलाइन शाहनहर है। मगर यह शाहनहर कुछ पोर्शन्ज से डैमेज हो चुकी है। यह डैमेज क्यों हुई इसके पीछे भी एक अजीब कहानी है। नीति आयोग और

प्लानिंग कमीशन का जब इंटरचेंज हुआ था तो शाहनहर के लिए लगभग पिछले सात वर्षों से मुरम्मत का पैसा आना बंद हो गया। अगर आप किसी चीज़ की मुरम्मत नहीं करेंगे तो वह डैमेज हो ही जाती है। इस डैमेज का खामियाजा यह हुआ कि हमारे किसान वहां पर धान की फसल ठीक से नहीं लगा पाए। दूसरा, इन्द्र देव जी हमारे ऊपर इस बार कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे, उसके कारण भी हमारे काम-काज़ ठीक से नहीं हो पाए। इसके अतिरिक्त बिजली की समस्याएं यानी किसानों की अपनी मोटर्ज नहीं चल पाईं। उनकी मोटर्ज और वहां के ट्रासफॉर्मर्ज जल गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज वहां का ट्रांसफॉर्मर जला हुआ है।

टी सी द्वारा जारी

09.09.2024/1620/टी0सी0वी0/एच0के0-1
श्री भवानी सिंह पठानिया..... जारी

अब जाकर आप उस किसान को बोलोगे कि हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से काम नहीं हो पा रहे हैं तो वह नहीं सुनता और न ही उसको सुनने की जरूरत है क्योंकि उसकी रोजी-रोटी सिंचाई के कारण चलती है और सिंचाई के लिए उसको नहर का पानी चाहिए या बिजली चाहिए। अगर हम उनको यह दोनों चीजें न दें पाएं तो यह हमारे लिए detrimental हो जाता है। उस तबके को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने ओ0पी0एस0 दे दी। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की हम डी0ए0 की किस्त देंगे, उसको तो इससे फर्क पड़ता है कि आप मेरे नहर की रिपेयर करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? इन सब चीजों के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसकी जरूरत इसलिए होती है क्योंकि मेरे पास बेलेंस शीट को बढ़ाने की लिमिडिट उपलब्धता है। श्री विपिन सिंह परमार जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, वे यहां इस समय बैठे नहीं है कि जो राजा होता है उसको अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। इस समय हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है इसका कारण यह भी है कि पिछले दो वर्षों से PDNA (Post-Disaster Needs Assessments) का पैसा नहीं दिया गया। राजा की दिल बड़ा होना चाहिए, मैं उसी पर बात कर रहा हूं अगर राजा बड़ा दिल दिखाए तो यह वही राज्य है जहां पर उनको हर प्रकार के व्यंजन पसंद हैं, यदि वह चाहते तो अपने बजट में

उन्होंने असम, सिक्किम और उत्तराखण्ड तीन राज्यों के लिए जो सहयोग दिया वह हिमाचल प्रदेश के लिए भी दे सकते थे लेकिन यह सहयोग इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि यह कांग्रेस शासित राज्य है। इसलिए यदि राजा बड़ा दिल दिखाएगा तो ही छोटे राज्यों का विकास हो पाएगा। मुझे लगता है कि अगले तीन सालों तक यह केन्द्र सरकार संकीर्ण मानसिकता और संकुचित सोच के साथ चलेगी इसलिए हमें अपने रिसोर्सिज जनरेट करने पड़ेंगे। मैं मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि रिसोर्सिज को जनरेट करने के लिए जो पहल आपने की है, यह एक बहुत बड़ी पहल है। वर्ष 2022 में हम पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आए और हमारे 40 विधायक थे। 68 सदस्यों की इस विधान सभा में हमारी पार्टी के 40 सदस्य जीतकर आए जोकि टोटल जीत का 58 प्रतिशत था। 58 percent of the total House was Congress. उसके बाद कोशिश की गई कि किसी तरीके से षडयंत्र करके इस सरकार को गिरा दिया जाए और उस सिलसिले में हमारे 9 साथी रिजाइन कर गए तथा दोबारा जनता के पास मैनडेट लेने गए। इस बार जो मैनडेट मिला वह सरकार के लिए नहीं

09.09.2024/1620/टी0सी0वी0/एच0के0-2

था, यह मैनडेट ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू की लीडरशीप के लिए था। यह वर्डक्टि इनके ऊपर थी और यदि हम हारते तो यह इनकी हार थी और अगर हम जीते हैं तो यह इनकी जीत है क्योंकि केन्द्र सरकार व आसपास के राज्यों की ओर से पूरी कोशिश की गई कि हम यह चुनाव जीत न पाएं। यह मैनडेट किस चीज के लिए मिला है यह जानना भी बहुत जरूरी है। 9 विधायकों में से 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीत कर आएं हैं और यह मैनडेट 66.6 प्रतिशत है यानी डेढ़ साल में 58 प्रतिशत से 66 पर पहुंचना बहुत बड़ी बात है। यह कोई विरोधी लहर नहीं है इनकी सरकार रिपिट नहीं हुई क्योंकि लोगों को इनकी पॉलिसीज पसंद नहीं आई। आज अगर हमने अपने मैनडेट को 58 से 66 प्रतिशत पर लेकर गए हैं तो इसका मतलब है कि मुख्य मंत्री जी की छवि और वर्किंग स्टाइल के लिए लोगों ने हमें थम्पिंग मेजॉरिटी दी है और कहा कि जो आप काम कर रहे हैं उस पर आप कायम रहें। इसलिए अगर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है इसको ऊपर लेकर आगे जाना है तो हमें कहीं और जगह देखने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जो स्टैप लेने शुरू किए हैं उन पर कायम रहने की जरूरत है। वर्ष 1991 में जब भारत की अर्थव्यवस्था doldrums थी, श्री

चन्द्र शेखर की सरकार ने जो सोना गिरवी रखा हुआ था उसको वापिस लाया था। Liberalization की शुरुआत माननीय श्री पी0वी0 निरसिम्हा राव और माननीय वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने की है। आज जो हिन्दुस्तान आप देख रहे हैं इसकी शुरूआत वर्ष 1991 में इनके द्वारा की गई थी। आज हिमाचल प्रदेश उसी दहलीज पर खड़ा है। आज लोग बार-बार बोल कर हमें रिजैक्ट कर चुके हैं कि

एन0एस0 द्वारा जारी ।

09-09-2024/1625/एन0एस0-एच0के0/1

श्री भवानी सिंह पठानिया-----जारी

लोगों को मुफ्त का पानी नहीं चाहिए। लोगों को मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए और उनको मुफ्त का राशन नहीं चाहिए। उनको डिस्पेंसरियां जगह-जगह पर नहीं चाहिए जहां नर्स तक नहीं होती। वे हमसे क्वालिटी हैल्थ केयर मांग रहे हैं, वे क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी मांग रहे हैं। वे क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ रोड मांग रहे हैं। यह क्वालिटी देने के लिए हमें पूरे-के-पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है जिसको आपने व्यवस्था परिवर्तन के नाम से ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। इसके अंदर अगर हम देखें तो यह एक महायज्ञ है। जब मैं छोटा हुआ करता था तब मैं रामायण सीरियल में देखता था कि जब भी ऋषि-मुनि यज्ञ करने लगते थे तो राक्षस उस यज्ञ में विघ्न डालने आते थे। इसी तरह यह भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है और राक्षस इसमें भी आएंगे लेकिन हमें बिल्कुल नहीं डरना है क्योंकि आपके साथ आपके सारे विधायक कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम यह जो काम करने जा रहे हैं, यह सिर्फ आज का हिमाचल नहीं बल्कि वर्ष 2032 का हिमाचल है और हिमाचल जब सबसे ज्यादा समृद्धशाली बन जाएगा तब हमें याद किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दो-तीन विषयों के ऊपर आकर्षित करना चाहूंगा। अगर हम रिफॉर्म्ज की बात करें तो आप उसमें ऑलरेडी एक शुरुआत कर चुके हैं लेकिन मेरी नजर में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एच0पी0एस0ई0बी0एल है। पॉवर सेक्टर में न केवल पॉवर जेनरेशन जहां पर आज हमारी कोस्ट 7-8 रुपये हाइड्रो पॉवर की आ रही है और इसको अगर हम 2 से 2.50 रुपये तक लेकर जाते हैं तो उसी में लगभग 1600 करोड़ की अपसाइड आ जाती है। दूसरा, हमारा पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन है। हमारे डिस्ट्रिब्यूशन लॉसिज आज 13-14 प्रतिशत पर हैं और

अगर हम इनको रेशनेलाइज करने की कोशिश करें तो काफी हद तक ये रेवेन्यू एनहांसिंग टूल बन जाता है। तीसरा, हमारी जो पॉवर परचेज है और अगर हम पॉवर परचेज पॉलिसी के ऊपर थोड़ी स्ट्रिन्जंसी लिखा दें तो यह भी पैसे का एक टूल बन सकता है। आज हिमाचल में लगभग 6000 करोड़ मेगावाट की डेफिशियेंसी है। हमने जो सोलर पॉवर का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है अगर हम यह डेफिशियेंसी पूरी करते हैं तो 800-900 करोड़ रुपये का और रेवन्यू एनहांसमेंट होता है।

09-09-2024/1625/एन0एस0-एच0के0/2

अध्यक्ष महोदय, अब मैं माइनिंग के ऊपर बोलना चाहता हूं। मेरी माइनिंग वालों से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे अवैध माइनिंग से समस्या है। पंजाब से लोग आते हैं और हमारी खड्डों में माइनिंग करते हैं तथा हमारे मटीरियल को लेकर चले जाते हैं। इसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अगर हम वहां पर राखे लगा दें और उनको छोटे लाइसेंस दे दें क्योंकि खड्ड तो सरकार की है तो उन बेरोजगार युवकों को जिनके पास ट्रैक्टर हैं तथा उनको 25,000 रुपये माइनिंग फीस दें, अगर एक खड्ड पर 4 लीज भी देते हैं तो मैं कह सकता हूं कि पंजाब का कोई आदमी वहां माइनिंग करने आएगा तथा ये सब उसको रात को ही जला डालेंगे। मतलब यह हुआ कि यह एक प्रोटेक्शन टूल, रेवेन्यू टूल और एक रोजगार का टूल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी खड्डों के छोटे लाइसेंस लोकल नौजवानों को दिए जाएं। ये लाइसेंस बड़े उद्योगपतियों, क्रशर मालिकों को नहीं देने हैं बल्कि अपने लोगों को देने हैं जोकि वहां के स्थानीय लोग हैं। एक्साइज पॉलिसी में हर विधान सभा क्षेत्र के अंदर, हर पंचायत के अंदर कम-से-कम दो अड्डे ऐसे होते हैं जो अवैध शराब बेच रहे हैं। अवैध शराब इसलिए है क्योंकि हमने उसको लीगलाइज नहीं किया है। ये वह शराब है जो बिना एक्साइज के निकलती है। जो हमारे आसपास की डिस्टीलरीज हैं वे उसी को निकाल कर बेचती हैं। इसका सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है और इसकी क्वालिटी का हमें कोई पता नहीं है। अगर हम छोटे बार लाइसेंसिज 5000 रुपये से 25,000 रुपये तक लगा देते हैं और उसमें एक कंडीशन हो कि जो भी लाइसेंस लेता है तो उसको ठेके से मैनडेटरी कोटा उठाना पड़ेगा। इससे सरकार को रेवेन्यू आएगा और अवैध शराब की चोरी खत्म होगी। इससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद फोरेस्ट पॉलिसी और पी0एस0यू0 हैं। HRTC should be treated as a profit centre, HPMC

should be treated as a profit centre, इन सबके ऊपर अगर हम अच्छी तरह काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें ब्लैकमेल का सामना नहीं करना पड़ेगा

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

09.09.2024/1630/rks/yk-1

श्री भवानी सिंह पठानिया...जारी

कि हमने आपकी गर्दन पकड़ रखी है और आप हमें नमस्ते नहीं करेंगे या दण्डवत् प्रणाम नहीं करेंगे तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। हम इससे निकल जाएंगे और हमें हर हिमाचली और युवा याद रखेगा कि यह वह सरकार थी जो यह बोलकर नहीं गई कि हम खजाना खाली करके जा रहे हैं। हम खजाना भरकर जाएंगे। अंत में मैं आपको श्री माखन लाल चतुर्वेदी की चार लाइनें पढ़कर सुना रहा हूंः-

चाह नहीं, मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं,
चाह नहीं प्रेमी-माला में बिंध प्यारी को ललचाउं।
मुझे तोड़ लेना वनमाली,
उस पथ में देना फेंक।
हिमाचल की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने,
जिस पग लिए जाएं कदम अनेक।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

09.09.2024/1630/rks/yk-2

अध्यक्ष : इस चर्चा में दो अन्य सदस्य टैग्ड हैं। लेकिन मैं सत्तापक्ष और विपक्ष से एक-एक सदस्य को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। अब श्री जय राम ठाकुर जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, श्री भवानी सिंह पठानिया जी ने नियम-130 के तहत 'प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर यह सदन विचार करे' प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। हमने प्रदेश की वर्तमान आर्थिक

स्थिति पर नियम-67 के तहत भी चर्चा करने के लिए प्रस्ताव दिया था। हमने यह प्रस्ताव इसलिए दिया था क्योंकि पूरा देश जानना चाहता था कि हिमाचल प्रदेश में जो वित्तीय संकट का शोर पड़ा है उसकी वस्तुस्थिति क्या है। जब सदन चला होता है तो सबसे पहले यह जानकारी सदन को होनी चाहिए थी लेकिन इसमें विलम्ब हुआ है। आपने व्यवस्था दी कि हम इस विषय को नियम-130 के तहत ला रहे हैं। आज सदन का अंतिम दिन था लेकिन आपने इस सदन की बैठक एक दिन और बढ़ा दी। अब यह सदन कल तक चलेगा। हम इस विषय में चर्चा कर रहे हैं लेकिन यह हकीकत है कि इससे पहले पूरा देश हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा कर चुका है। हमारे कर्मचारियों व पेंशनर्ज को 1 तारीख को सैलरी व पेंशन नहीं मिल पाई। सैलरी व पेंशन के सिलसिले में मुख्य मंत्री जी ने बयान दिया कि हम 5 तारीख को सैलरी व 10 तारीख को पेंशन देंगे। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हम पहली बार इस प्रकार की वित्तीय स्थिति देख रहे हैं जब समय पर कर्मचारियों व पेंशनर्ज को सैलरी व पेंशन नहीं मिली। स्वाभाविक रूप से पूरे देश में इस विषय पर चर्चा हुई। मैं आज भी इस बात को कह सकता हूं कि आपने सैलरी 5 तारीख को डाली है।

श्री बी.एस. द्वारा ... जारी

09.09.2024/1635/बी.एस./वाई.के-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

अगर आपने सैलरी 05 तारीख को डाली है तो 05 तारीख को सैलरी डालने की वजह यह थी कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की 520 करोड़ रुपये की किस्त केन्द्र सरकार से आनी थी। उससे आपको एक स्पोर्ट मिली है। उसके बाद आपने पेंशनर्ज के लिए अगर बात कही है कि 10 तारीख को पेंशनर्ज को पेंशन मिलेगी। वह इसलिए मिलेगी कि जो हमारे सैंट्रल टैक्सिज में स्टेट का शेयर है वह 10 तारीख को मिलेगा और उससे आप फिर पेंशन देने की स्थिति में हो जाएंगे। वह 7.50 करोड़ रुपये के लगभग शेयर बनता है। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि प्रदेश की स्थिति यह बन गई है कि हम ऐसे हालात में पहुंच गए हैं कि अपने बलबूते प्रदेश के कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाएंगे और अपने बलबूते प्रदेश के पेंशनर्ज हैं उन्हें पेंशन नहीं दे पाएंगे। यह स्थिति आज हमारे सामने खड़ी हो गई है। मुख्य मंत्री जी जिस विषय को बार-बार हर जगह जहां भी मौका मिले, मंच मिले और जहां भी अवसर मिले, एक ही बात कहते हैं कि इसके लिए हम दोषी नहीं हैं। ये तो जय राम ने बहुत लोन

ले रखा है, इस कारण से ये हालात बनें हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि यह स्थिति हमारे सामने स्पष्ट रूप से आनी चाहिए। माननीय सदस्य पठानिया जी ने बहुत कुछ बातों का उल्लेख किया लेकिन वित्तीय स्थिति के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि हमारे बजट का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर जाता है। हिमाचल प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर पॉपुलेशन परपोशन में सबसे ज्यादा संख्या अगर कर्मचारियों और पेंशनर्ज की हैं तो हिमाचल प्रदेश उसमें पहले स्थान पर है। लेकिन उसके बावजूद यह दोष देने की बार-बार कोशिश की जाती है कि पूर्व सरकार जय राम, जय राम ने किया। जब जय राम जी रह जाते हैं तो फिर मोदी जी ने किया। ये दोष देने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि जब हिमाचल प्रदेश में 27 दिसम्बर, 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो क्या उस वक्त प्रदेश में लोन नहीं था? क्या पूर्व सरकार हमें नो ड्यू सर्टिफिकेट दे करके गई थी, कि पैसे का कोई लेन-देन नहीं है? अध्यक्ष महोदय, 48 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण पूर्व की सरकार हमारे ऊपर झोड़ करके गई है। इसे भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। सही मायने में अगर हम थोड़ा और पीछे जा करके देखेंगे, मैंने कोशिश की और मैंने कभी नहीं बोला और न ही मैंने इसे कभी

09.09.2024/1635/बी.एस./वाई.के-2

सार्वजनिक सभाओं में और न ही मीडिया में यह बोला कि पिछली सरकार की वजह से प्रदेश के ऊपर इतना लोन पड़ा है। अगर सही मायने में हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से पटरी से उतरा है तो यह 1993-98 की सरकार रही उस वक्त उतरा है और यह हालात बने थे। हालांकि प्रदेश में उस वक्त कोई आर्थिक संकट नहीं था। लेकिन क्या आवश्यता पड़ी कि उस वक्त बिजली बोर्ड के माध्यम से आपने लोन ले लिया, फोरेस्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से आपने लोन ले लिया? यह क्रम उस वक्त शुरू हुआ और उसके बाद यह थमने का नाम नहीं ले पा रहा है। जरूरत के मुताबिक उस वक्त जितना लोन लेने की आवश्यकता थी, उससे ज्यादा लोन ले लिया गया। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, ये दौर आगे बढ़ते-बढ़ते यहां तक पहुंचा है। आदरणीय पठानिया जी ने यह सही कहा कि विकास के लिए पैसा कहा बचा है? और आने वाले वक्त के लिए प्रदेश के जो हालात बन रहे हैं वह बहुत भयानक बनते जा रहे हैं। विकास के काम के लिए पैसा बचाना बहुत कठिन हो

जाएगा। अगर हम यहां पर बजट पर भी जिक्र करें, जो हमारा मुख्य बजट वर्ष 2022 का था वह 51,365 का था।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

09.09.2024/1640/डी0टी0/ए0जी0-1

श्री जय राम ठाकुर जारी

और उसमें अगर सप्लीमेंट्री बजट को भी मिला दें जो 13,141 करोड़ रुपये था तो कुल मिलाकर 64,506 करोड़ रुपये का वह बजट था। लेकिन जब आपकी सरकार सत्ता में आई तो स्थिति यह बन गई कि जो आपका मूल बजट था वह 53,412 करोड़ रुपये का था और उसके बाद सप्लीमेंट्री बजट 10,300 करोड़ रूपये था यानी कुल 63,712 करोड़ रुपये का बजट बना जोकि भरतीय जनता पार्टी के अंतिम वर्ष के बजट से 1000 करोड़ रुपये कम है। इससे यह मालूम पड़ता है कि प्रदेश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। अगर हम डवलपमेंट की बात करतें हैं कि हमारे पास डवलपमेंट के लिए पहले कितना पैसा था और आज के दौर में कितना है, तो जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी तो हमारा पहला बजट वर्ष 2018-2019 का जो था उसमें डवलपमेंट के लिए अगर मैं उसमें वेतन का जिक्र करूं तो 27.18 प्रतिशत का बजट था, पेंशन के लिए 14.22 प्रतिशत का बजट था , ब्याज की अदायगी के लिए 10.28 प्रतिशत और ऋण की आदयगी के लिए 8.76 प्रतिशत का बजट था और कुल मिलाकर विकास कार्यों के लिए 39.56 प्रतिशत का बजट था। उस समय हमारे पास डवलपमेंट के लिए साइज़बल अमाउंट था। वित्त वर्ष 2019-2020 में भी ये इतना ही था। लेकिन आपके शुरू के वित्त वर्ष 2024-2025 डवलपमेंट के लिए जो बजट रह गया वह 28 प्रतिशत रह गया और अब तो ये 28 प्रतिशत से भी कम हो गया। यह आज चिंता का बहुत बड़ा विषय है कि सरकार आने वाले समय में विकासात्मक कार्य कैसे करेगी। क्योंकि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है। सडकों, हस्पतालों या स्कूलों की मेंटेनेंस के लिए पैसे की बहुत बड़ी कमी होने वाली है। मैं इस सदन में ये भी कहना चाहता हूं कि जैसे वर्तमान सरकार कहती रहती है कि पूर्व सरकार ने बहुत ज्यादा लोन लिया आज इस सदन में सरकार की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के पांच सालों में जो लोन लिया वह 40,672 करोड़ का था और उसमें से 38, 276 करोड़ रुपये हमनें चुकाया जिसमें किस्तें भी वापिस कीं और जो ब्याज

था उसकी भी अदायगी की। इसमें जो अंतर था वह 2396 करोड़ रुपये का था। लेकिन जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आई और वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रदेश में इस प्रकार के हालात बन गये हैं कि जो ऋण प्रदेश सरकार के द्वारा लिया जा रहा उस ऋण से सरकार किस्तों की भी अदायगी करने की स्थिति में नहीं है बहुत कम पैसा किस्तों के रूप में अभी सरकार ने अदा किया है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार ने उस प्रकार का संकट नहीं झेला जो हमारी सरकार द्वारा दो वर्ष तक झेला गया।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

09.09.2024/1640/डी0टी0/ए0जी0-2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जब इनकी सरकार सत्ता में आई थी तो प्रदेश के ऊपर 48000 करोड़ रुपये का लोन था और इन्होंने 40000 करोड़ रुपये लोन लिया जिसमें से 38000 करोड़ रुपये की राशि वापिस भी की गई। मैं यहां ये नहीं समझ पा रहा कि प्रदेश के ऊपर ये लोन 48000 करोड़ से 85000 करोड़ रुपये कैसे हुआ और 10000 करोड़ की लायबिलिटी कैसे हुई? अगर पूर्व सरकार ने 38000 करोड़ रुपये वापिस किया और 2000 करोड़ का लोन ही शेष रहा तो ये अमाउंट 85000 करोड़ रुपये कैसे पहुंचा, मैं नेता प्रतिपक्ष से ये जानना चाहता हूं?

अध्यक्षः माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, अगर मैं ब्याज की अदायगी जो हमने की उसकी बात करूं तो अपने कार्यकाल में जो लोन हमने लिया वह लोन बहुत कम बनता है क्योंकि

एन0जी0 द्वारा जारी...

09-09-2024/1645/ए.जी.-एन.जी/1

श्री जय राम ठाकुर .....जारी

लिमिट से बहुत कम लोन लिया था। हम तो आपको 6000 करोड़ रुपये के लोन की लिमिट छोड़ कर गए थे। जब हमने सत्ता छोड़ी और आप मुख्य मंत्री बने तब हम यह लोन लिमिट

छोड़ कर गए थे। सही मायनों में हमारे 5 साल के समय का नैट लोन लगभग 19600 करोड़ रुपये बनता है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं उनके फैक्ट्स में बहुत बड़ा अंतर है। यह सच्चाई नहीं है क्योंकि जो हकीकत है उसे हम बता रहे हैं। वर्ष 2012 से 2017 तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उस समय लोन में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2017 से 2022 तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और लोन में 48 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अध्यक्ष महोदय, इससे आगे बढ़ कर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस माननीय सदन में दिनांक 30-08-2024 को प्रश्न संख्या-818 लगा था और उसका उत्तर सरकार ने क्या दिया है, यह भी देखने लायक है। प्रश्नों के उत्तर अधिकारी लोग बनाते हैं और वे चालाकी करते हैं। आंकड़ों को घूमाते व छिपाते हैं। वे यही सोचते हैं कि नेताओं को पता नहीं लगता और यह सोच आज भी विद्यमान है। उस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि कुल लोन 21366 करोड़ रुपये लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि 2810 करोड़ रुपये कर्मचारियों की भविष्य निधि के अगेंस्ट भी लोन लिया गया है और इसका जिक्र अलग से किया हुआ है। इन दोनों अमाऊंट को मिलाएं तो सरकार ने अभी तक कुल 24176 करोड़ रुपये लोन ले लिया है। इसके अलावा सरकार ने अभी तक 5864 करोड़ रुपये के लोन की अदायगी की है। यह हैरानी की बात है क्योंकि कोविड के दौरान भी हमने इससे ज्यादा की अदायगी की थी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि आंकड़े घूमाए व छिपाए जा रहे हैं। मैं इन बातों का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि कुछ बातें एकदम स्पष्ट होनी चाहिएं और वे बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज की हकीकत यह है कि हिमाचल प्रदेश पर 90 हज़ार करोड़ रुपये का ऋण चढ़ चुका है। मुख्य मंत्री जी, आप सुख की सरकार व व्यवस्था परिवर्तन की सरकार चला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में इस वर्ष दिसम्बर माह

09-09-2024/1645/ए.जी.-एन.जी/2

से पहले हिमाचल प्रदेश एक लाख करोड़ रुपये के लोन की दिशा में बढ़ता जा रहा है। मुख्य मंत्री जी, हिमाचल प्रदेश पर एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन चढ़ाने का श्रेय आपको जाएगा। यह कीर्तीमान आपके नाम होने जा रहा है और आप इसे रोक भी नहीं पाएंगे। इन हालातों में आपको यह करना ही होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जब हमारी सरकार सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तब हम 6000 करोड़ रुपये की लिमिट छोड़ कर गए थे। उसे हम अपनी सरकार के समय में ले सकते थे लेकिन हमने उसे नहीं लिया। इन्होंने सरकार बनने के बाद, न दायं देखा, न बायं देखा और तुरंत 3 माह के भीतर 6000 करोड़ रुपये की लिमिट को भी एग्सॉस्ट कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति में प्रदेश जिस दिशा में जा रहा है वह हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस सारी चिंता के बारे में मुख्य मंत्री जी ने भी जिक्र किया लेकिन वे हकीकत क्यों नहीं बता रहे हैं? मुख्य मंत्री जी का कभी बयान आता है कि प्रदेश में आर्थिक संकट है। इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में 1000 संस्थानों, चले व खुले हुए संस्थान और लोगों की मांग पर दिए हुए संस्थान, को बंद कर दिया। हमें लगा कि शायद इससे थोड़ी अच्छी स्थिति बन जाएगी लेकिन अच्छी स्थिति नहीं बनी। आप विकास रोक कर हिमाचल प्रदेश को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस विकास को यह नहीं कह सकते कि ये.....(व्यवधान)

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

09.09.2024/1650/केएस/एएस/1

श्री जय राम ठाकुर जारी----

विकास रोक कर आप हिमाचल प्रदेश को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उस विकास को आप यह नहीं कह सकते कि यह बे-वजह का खर्चा है। लोकप्रिय सरकार की लोगों के लिए हमेशा यह प्राथमिकता रहती है कि हम विकास के लिए काम करें, लोगों के कहने के मुताबिक, लोगों के भले के लिए काम करें और इसलिए उनकी सुविधा के लिए अगर कहीं पर संस्थान भी खोलने की ज़रूरत पड़ती है, वहां उन संस्थानों को भी खोलें।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि एक तो जय राम और दूसरे मोदी जी दोषी हैं। केंद्र हिमाचल प्रदेश का शेयर नहीं दे रहा है। आपको केंद्र से चाहिए क्या? जब खुद व्यक्ति दोषी होता है तो वह ज्यादा जोर से बोलता है कि मैं दोषी नहीं हूं, दोषी वह है। हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए क्योंकि अगर कमी है, संकट है तो इस संकट का सामना करने की जिम्मेवारी हमारी है। ...(व्यवधान) हमने कभी नहीं कहा, हमने कहा कि इस संकट का समाधान करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। आप याद करिए कि जब मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्य मंत्री बना था, उसके तीन महीने बाद ही शिमला शहर में जल संकट आ गया। क्या मैं उसके लिए दोषी था? आप लोग तो बाल्टियां और कनस्तर हाथ में ले कर उनको बजाते हुए मालरोड़ पर निकल गए थे। शिमला में थोड़ा सा पानी का संकट आया और आपने इस प्रकार के हालात पैदा कर दिए थे कि जय राम दोषी है लेकिन हमने उसके बावजूद भी आपको दोषी नहीं ठहराया। हमने कहा कि संकट है, इसका समाधान करना हमारी पहली आवश्यकता है। हमने उस संकट का समाधान किया। एक सीज़न में वह पानी का संकट आया जो कि हमारी वजह से नहीं था लेकिन उसके बाद एक साल से पहले-पहले हमने 70 करोड़ रुपये की चाबा की पानी की स्कीम शिमला के लिए शुरू की। उसके बाद दूसरी लगभग 1800 करोड़ रुपये की पानी की स्कीम लाकर शिमला में पानी की समस्या का हमेशा के लिए समाधान किया। दोष दे कर समाधान नहीं हो सकता। अब ये मोदी जी को कह रहे हैं कि उन्होंने रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म कर दी। अध्यक्ष महोदय, जब 15वां वित्तायोग देश के सभी प्रदेशों में गया। सारी जगह जा कर, सारी चीजों को ले कर जो उसने रिकमेंडेशन्ज़ करनी थीं, वह कीं। वह हिमाचल के संदर्भ में नहीं बल्कि पूरे देश के संदर्भ में कीं और हिमाचल भी देश का एक राज्य है।

09.09.2024/1650/केएस/एएस/2

उसके मुताबिक रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट का हिमाचल के लिए जो हिस्सा मिलना था फिर भी वह बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा मिला है। 15वें वित्तायोग के बाद भी बाकी राज्यों की हालत आप देखें, उनको कम मिला है हिमाचल को ज्यादा मिला है। हिमाचल प्रदेश के लिए साल का 6200 करोड़ के लगभग रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा मिलता है जिसके तहत अभी आपको 520 करोड़ रुपये मिले हैं। उसी के तहत जो हर महीने आ रहा

है, उसी का वह हिस्सा मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी चिंता का विषय तो यह है कि अगले साल रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट का यह पैसा और भी कम हो जाएगा क्योंकि फाइनेंस कमीशन ने टेपर डाउन किया है। यह जा कर उससे भी नीचे जाएगा और साल का 3000 से भी कम आएगा । तो सुक्खू भाई गाड़ी कैसे चलेगी? वह बहुत कठिन दौर होगा। रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा हमको पूरे देश में सभी राज्यों की तुलना में बेहतर मिला है लेकिन पूरे देश के लिए टेपर डाउन करने का जो फैसला हुआ, उसके मुताबिक यह कम होता जाएगा। यह हिमाचल के साथ अन्याय का विषय नहीं है। पूरे देश के लिए जो एक फॉर्मुला तय किया है, उसके मुताबिक हुआ है। इसी प्रकार आप कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को जी.एस.टी. कंपनसेशन का पैसा बंद कर दिया। थोड़ा अध्ययन करना चाहिए कि जब जी.एस.टी. शुरू हुआ था, जी.एस.टी. काउंसिल की बैठक में हिमाचल प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर हमारे भी प्रतिनिधि थे। उसमें फैसला लिया गया कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद जी.एस.टी. कंपनसेशन का पैसा सिर्फ पांच साल के लिए दिया जाएगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

09.09.2024/1655/av/as/1

श्री जय राम ठाकुर---- जारी

उस कौंसिल की बैठक में यही फैसला हुआ कि जून, 2022 से जी0एस0टी0 कंपनसेशन का पैसा मिलना बंद हो जाएगा और यह पूरे देश के लिए बंद हुआ था। आप हर बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और जय राम को दोषी ठहराते हैं लेकिन यह उचित नहीं है। केंद्र सरकार के मुताबिक जो शेयर मिल रहा था उस शेयर के अनुसार एक पैसा भी कम नहीं किया गया। मैं तो समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहिए, विशेषकर जो हमारी 50 साल के लिए स्पेशल एसिस्टेंस की बिना ब्याज की ग्रांट होती है, आपने तो उसमें 1500 करोड़ रुपये लिए हैं। हम तो अपने कार्यकाल में शायद 600-700 करोड़ रुपये ले पाए थे। आप 1500 करोड़ रुपये ले चुके हैं परंतु उसके बावजूद आपने उसका ज़िक्र नहीं

किया कि 50 वर्षों के लिए आपने बिना ब्याज के 1500 करोड़ रुपये की राशि ली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वह राशि हमारे प्रदेश के विकास कार्यों के लिए दी है और इस बात के लिए आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए था। परंतु इस बात से बहुत दुःख होता है कि सत्ता पक्ष से कभी भी इस बारे में नहीं कहा गया। हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में पे स्केल भी लागू किया था। उस पे स्केल को लागू करते वक्त हमारे ऊपर बहुत बड़ा वित्तीय संकट आ रहा था लेकिन उसके बावजूद भी हमने लागू किया था। ठीक है, उसकी लायबिलिटीज फ़ेजिज में होंगी, उस बात को लेकर कोई दो राय नहीं है और उस बात को आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। पे स्केल लागू करने का मतलब यह नहीं होता कि सारी-की-सारी लायबिलिटीज हम एक साथ क्लीयर कर पाएंगे। मैं यह कह रहा हूं कि केंद्र आपको मदद कर रहा है और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में पेंशनर्ज को पेंशन इसलिए नहीं मिली क्योंकि मोदी जी ने रोक रखी है। जय राम दिल्ली जाकर प्रदेश का पैसा रोकता है और साथ में यह भी कहता है कि हिमाचल की मदद मत कीजिए। लेकिन मैं वस्तुस्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि जय राम चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, हिमाचल मेरी शीर्ष प्राथमिकता है। मैं विपक्ष में रहूं या पक्ष में, लेकिन अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े मैं उसमें कमी नहीं छोड़ूंगा।

09.09.2024/1655/av/as/2

आपने यहां पर ओ0पी0एस0 का एलान किया। आपको शायद जानकारी नहीं थी और हो सकता है कि आपकी पार्टी ने ओ0पी0एस0 लागू करने का फैसला किया था। यह मंशा हमारी भी थी परंतु हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति से अच्छी तरह से वाक़िफ थे। इसीलिए हमने कहा था कि रुकिए, हम इसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन उससे पहले काँग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में ओ0पी0एस0 लागू करेंगे। हम उसका विरोध थोड़े कर रहे हैं, हमने न तब किया था और न ही आज कर रहे हैं। आपने सत्ता को हासिल करने के लिए ये सारी चीज़ें की थीं। आपने दस गारंटीज केवल सत्ता हासिल करने के लिए दी थी। आपको जिन गारंटीज की वजह से सत्ता हासिल हुई, अब आप एक-एक से मुकरते जा रहे हैं। यहां माननीय मुख्य मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि हमारा 9000 करोड़ रुपया केंद्र के पास पड़ा है। आप मुझे बताइए कि कहां जैसे पड़ा हुआ

है। अगर दिल्ली में कहीं ऐसे ही पड़ा हुआ है तो हम सब उसको लाने के लिए चलते हैं। ...(व्यवधान) वह पैसा सरकार का नहीं है, कर्मचारियों का पैसा है और जो कर्मचारियों का पैसा होता है वह सरकार का नहीं हो सकता है। पी0एफ0आर0डी0ए0 ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि जो पैसा एन0पी0एस0 के अंतर्गत काटा गया है वह हमारी कमिटमेंट है। हमने उसकी अपनी टर्म्ज एण्ड कंडीशन्ज के साथ इंवेस्टमेंट की है।

टी सी द्वारा जारी

09.09.2024/1700/टी0सी0वी0/डी0सी0-1
श्री जय राम ठाकुर.... जारी

उसको सरकार न वापिस ले सकती है और न उसमें इस तरह का कोई क्लॉज है तथा न कोई प्रावधान है। वह पैसा सरकार को देने के लिए नहीं है लेकिन वह पैसा कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट के समय क्लेम करने पर उनके हिस्से के हिसाब से दे दिया जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं कि वह पैसा हमारा है, वह हमारी सरकार का पैसा है, आप कब से उस पैसे के मालिक बन गए? वह कर्मचारियों का पैसा है और इस बात से कौन मना कर रहा है? आज आप पिक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम दोषी नहीं है। अपनी जिम्मेवारी को मर्द की तरह निभाना चाहिए। हमने पांच साल तक सत्ता चलाई, हमने कभी नहीं रोना रोया कि ऋण है, ऋण है। हमने कहा कि है तो कहा है लेकिन इस प्रदेश को चलाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रदेश के लोगों ने हम पर भरोसा किया है, हमें जिम्मेवारी दी है, हमें मुख्य मंत्री बनाया है, हमारी सरकार बनाई है इसलिए हम प्रदेश के विकास के रास्ते में यदि कोई भी बाधा आएगी तो उसका सामना करेंगे। हम पैसों की वजह से भी कोई बाधा नहीं आने देंगे। हमने विकास भी किया और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को समय पर सैलरी और पेंशनरों को पेंशन दीं। आप तो डी0ए0 की किस्तें देने में भी असमर्थ हो गए। आपने जो कुछ कर्मचारी नेता टाइप बना रखें हैं उनको हकीकत मालूम नहीं है और जिस कारण वे बार-बार कहते रहते हैं कि हमारा ये पैसा दिल्ली से आना है। मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वह पैसा आपका है इसमें कोई दो राय नहीं और वह पैसा निश्चित रूप में

आपको ही मिलना है लेकिन वह पैसा नियम और व्यवस्था के मुताबिक मिलेगा। इस पैसे पर प्रदेश सरकार का क्लेम नहीं हो सकता है। हम पांच साल सरकार में रहे और हमने 65, 70 और 75 वर्ष की आयु के पेंशनरों को 5,10 और 15 का जो वित्तीय लाभ देना था, वह 200 करोड़ रुपया हमने दिया। इस तरह से उन कर्मचारियों की मांग को पूरा किया। वर्ष जनवरी, 2016 में जो पंजाब वेतनमान लागू हुआ उसकी 50-50 हजार रुपये की किस्त भी हमने कर्मचारियों और पेंशनरों को जारी की लेकिन अभी भी उसकी लायबिलिटीज हैं, वह निश्चित रूप में हैं और वह आपकी सरकार की जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को समय-समय पर डी0ए0 की किस्त देते रहे हैं। इस तरह से सरकार के ऊपर जो लोड था उसको कम करते रहे हैं। हमने कर्मचारियों और पेंशनरों के मेडिकल रि-इम्बर्समेंट का पैसा भी समय-समय पर दिया लेकिन

09.09.2024/1700/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

आपके समय में एक पैसा भी उन लोगों को नहीं मिला। हमारी सरकार ने जे0सी0सी0 का गठन करके कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी कदम उठाए लेकिन आपने अभी ऐसा कुछ नहीं किया है। अभी भी 12 प्रतिशत डी0ए0 का भुगतान करना शेष है। आपने 10 हजार से ज्यादा कर्मचारी निकाल दिए जो आउटसोर्स पर लगे थे। आज कहते हैं कि हम कर्मचारियों को समय पर सैलरी देते हैं। उप मुख्य मंत्री जी एच0आर0टी0सी0 का जिक्र कर रहे थे, बीच में एक ऐसा दौर आया था लेकिन हमने उसको संभालने की कोशिश की है परंतु आज की तारीख में यह परिस्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको अभी तक भी छह-छह महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है। मुख्य मंत्री जी इस बात का भी संज्ञान लें और उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति संकट में है। प्री-बजट कंसलटेशन की जो मीटिंग होती है उसमें आपका जाना ही नहीं हुआ। जबकि आपको उसमें जाना चाहिए था। शायद उसमें उद्योग मंत्री जी को भेजा गया था। नीति आयोग की बैठक का आप बहिष्कार करते हैं। जब हम फेडरल सट्रेक्चर में रहते हैं तो हमें यह मानकर भी चलना चाहिए कि केन्द्र सरकार भी प्रदेश की ही सरकार है। वहां पर जो महत्वपूर्ण बैठकें होती है उनमें

एन0एस0 द्वारा जारी ।

09-09-2024/1705/एन0एस0-डी0सी0/1

श्री जय राम ठाकुर-----जारी

प्रदेश की बात रखने वाला कोई आदमी वहां पर नहीं पहुंचा तो मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी कमी है। इसको कमी नहीं बल्कि यह कह सकते हैं कि यह गलत काम हुआ है और यह काम वर्तमान सरकार के दौरान हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी हिमाचल प्रदेश के वित्तीय संकट के संदर्भ में केंद्र की वित्त मंत्री के साथ बात की होगी। आपने अभी तक बात नहीं की। अगर हम Post Disaster Needs Assessments(PDNA) की बात करें, आप पैसा तो मांग रहे हैं लेकिन जो पैसा केंद्र सरकार ने दिया है उसको आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। 142 करोड़ रुपये आप खर्च नहीं कर पाए। इसका परिणाम यह होगा कि अगली बार की जो इंस्टॉलमेंट आएगी उस पर इसका असर पड़ेगा और उसमें कमी होगी क्योंकि केंद्र सरकार बोलेगी कि जो पैसा आपको दिया था आपने उसको खर्च नहीं किया। लोगों के घर बह गए, लोगों की जिंदगियां चलीं गईं और जो पैसा आपने उनके लिए केंद्र सरकार से लिया था यानी केंद्र सरकार ने जो पैसा उनकी मदद करने के लिए दिया था और उनका घर बनाने के लिए दिया था, आपकी सरकार ने उस पैसे को खर्च ही नहीं किया। आप इसका दोष नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं, आप दोष भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को दे रहे हैं और आप दोष जय राम ठाकुर को दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों से नुकसान होता है। अध्यक्ष महोदय, डिजास्टर के लिए हिमाचल प्रदेश को लगभग 1800 करोड़ रुपये मिले हैं। आज भी हिमाचल प्रदेश के हजारों लोग जिनके घर बह गए हैं, वे इंतजार कर रहे हैं। जो घोषणा की गई है उसके मुताबिक लोगों को आज दिन तक कोई मदद और पैसा नहीं मिल पाया है। हिमाचल प्रदेश को 18,000 मकान मिले और उसके लिए आप धन्यवाद तक नहीं करते। 2700 करोड़ रुपये प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मिले हालांकि, यह स्कीम है लेकिन मिला तो सही। हिमाचल पूरे देश का पहला राज्य है जिसको पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-॥। का पैसा मिला है जिसका भूमि पूजन आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने विधान सभा के चुनाव से पहले चम्बा के चौगान में किया था। आप फिर भी धन्यवाद नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश को हर जगह मदद हुई है और मैं यह कह सकता हूं। माननीय भवानी पठानिया अपनी बात रख कर बाहर चले

गए और कुछ सुझाव दे रहे थे। वे सुझाव इस तरह से नहीं दे रहे थे कि प्रदेश का संचालन या नेतृत्व आप कर रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश को 9200 मकान और मिल

09-09-2024/1705/एन0एस0-डी0सी0/2

गए और इसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। जब हम गांव में किसी पंचायत में जाते तो लोग कहते हैं कि पंचायत को 15 से 20 मकान मिले। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। मुख्य मंत्री जी, आपने मुख्य संसदीय सचिव 1-2 नहीं बल्कि 6 बना कर रखे हुए हैं। हम भी पांच सालों तक सरकार में रहे लेकिन हमने नहीं बनाए। इसलिए नहीं बनाए कि आर्थिक संकट और बढ़ेगा। बहुत ज्यादा इसकी फाइनैंशियल इंप्लीकेशन्ज होंगी। आपने कैबिनेट दर्जे के साथ बना कर रखे हैं और मामला माननीय उच्च न्यायालय में चला हुआ है। मामला जजमेंट के लिए रिजर्व है। आपने वकीलों को लगभग 6 करोड़ रुपये उनकी कुर्सी बचाने के लिए खर्च कर दिया। आप यहां पर घोषण कर रहे हैं और उस दिन मुझे बड़ा विचित्र लगा जब आपने कहा कि मेरे मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव दो महीने की सैलरी विलंबित लेंगे। पूरे देश भर के टी0वी0 चैनलों में चल पड़ा कि सुक्खु भाई ने गज़ब कर दिया कि दो महीने की सैलरी छोड़ दी। हमने बताया कि छोड़ी नहीं है, वे दो महीने के बाद तीसरे महीने इकट्ठी लेंगे। यह सब नहीं करना चाहिए।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

09.09.2024/1710/rks/hk-1

श्री जय राम ठाकुर....जारी

आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। आपको यह आदत पड़ गई है कि कोई बड़ी खबर बनें लेकिन आपको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। आपने चेयरमैन, ओ.एस.डी. व एडवाइजर को कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया है। प्रदेश के सभी लोग कह रहे हैं कि अगर वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए शुरुआत करनी है तो वह सबसे पहले अपने आप से करें। जो आपने सी.पी.एस. व चेयरमैन बनाएं हैं इससे वित्तीय स्थिति पर बोझ पड़ा है। हमारे समय में चेयरमैन व वाइस चेयरमैन को 30,000 रुपये मिलते थे लेकिन आपने इस

सैलरी को 1.30 लाख रुपये कर दिया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप कैसे आर्थिक संकट से बाहर आ पाएंगे? आपने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में वाटर सैस लगाएंगे। हमने कहा कि आप लगाइए हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि यह ख्याली-पुलाव जमीनी हकीकत नहीं है और यह हो नहीं पाएगा। आप इसकी घोषणा करके चले गए लेकिन अब यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में आपके विरुद्ध फैसला आया है। अब उस फैसले में क्या आप हमको दोषी ठहराएंगे? आप भांग की खेती का जिक्र कर रहे हैं। हम इसका विरोध नहीं करेंगे क्योंकि हमारे समय में भी इस तरह का प्रस्ताव इस सदन में आता रहा है। आप कह रहे हैं कि इससे प्रदेश की आर्थिकी सुधर जाएगी लेकिन दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि आप हिमाचल प्रदेश के लोगों को भांग पिलाना चाह रहे हैं? आपने कहा कि हम कंट्रोल्ड एटमोशफियर में भांग की खेती करना चाह रहे हैं। आप यह काम जरूर करें लेकिन चिंता का विषय यह है कि जो ड्रग्स का प्रचलन पूरी दुनिया में चला है उसमें हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। इसमें क्या हम सारी चीज को रोक पाएंगे? यह एक चिंता का विषय है इसलिए इन बातों पर भी विचार करना जरूरी है। सीमेंट के रेट के बारे में हमारी सरकार के समय विपक्ष के नेता यहां से बड़ा शोर मचाते थे। आप कहते थे कि हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के कारखाने लगे हैं फिर हिमाचल प्रदेश में पंजाब व हरियाणा राज्यों की तुलना में सीमेंट क्यों महंगा है? आज आपकी सरकार सत्तासीन है और यह सरकार क्या कर रही है? जितनी हमारे पूरे कार्यकाल में सीमेंट की कीमतें बढ़ी थी उतनी कीमत तो आपने एक साल में बढ़ा दी है। आपने 100 रुपये प्रति बैग सीमेंट की कीमत बढ़ाई है। यानी 40 प्रतिशत की इंक्रीज एक माह के भीतर हो गई है। इसमें हम किसको दोष दें? ...(व्यवधान) तब आप कहते थे कि जय राम

09.09.2024/1710/rks/hk-2

दोषी है। आज आप उन लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं जिनके नाम सीमेंट की इंडस्ट्री हैं। आप कहते थे कि सरकार सीमेंट के दाम कंट्रोल नहीं करना चाहती। आप कहते थे कि हम गरीब आदमी का घर नहीं बनाना चाहते। लेकिन आज आप क्या बोल रहे हैं? आज आप इस दौर से कैसे निकलेंगे? आज विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। आपने एक साल में एक लाख नौकरियां और पांच सालों में पांच लाख नौकरियां देने का वायदा बेरोजगारों के

साथ किया है। आपके कार्यकाल के दो साल पूरे होने जा रहे हैं लेकिन अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग, हमीरपुर अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है। आपने उस संस्थान को बंद कर दिया था। आपने उस संस्थान को दोबारा से शुरू करने की बात तो की लेकिन यह काम नहीं हो पाया है। आज हिमाचल प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवा नौकरी से महरूम हो गए हैं क्योंकि उनकी नौकरी पाने की उम्र पार हो गई है। आपको इन सारी चीजों के ऊपर जवाब देना होगा। मुख्य मंत्री जी आप इस बात को स्पष्ट करें कि हमारे ऊपर आर्थिक संकट है। आओ, इस संकट का समाधान करने के लिए कुछ बातें करते हैं। अगर आप ऐसा कहेंगे तो बात समझ में आएगी। लेकिन आप बार-बार कह रहे हैं कि इसके लिए जय राम ठाकुर और श्री नरेन्द्र मोदी जी दोषी हैं, आप यह कहना बंद कर दें। जो यह संकट बढ़ता जा रहा है इससे आने वाले समय में और ज्यादा दिक्कत आएगी। जब नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो उसमें साढ़े 6 हजार करोड़ रुपये की लोन लिमिट फिर से शुरू होगी और आप थोड़ा और लोन लेंगे।

श्री बी.एस. द्वारा ... जारी

09.09.2024/1715/बी.एस./एच.के-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

आप उसमें थोड़ा सा समय और निकालेंगे लेकिन बहुत ज्यादा वक्त निकालने की स्थिति में आप नहीं होंगे। यह सैलरी और पेंशन का संकट बना रहेगा। प्रदेश में विकास कार्य को ठप होने का संकट लगातार बना रहेगा। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश जिस दौर में से गुजर रहा है वह हम सब के लिए चिंता का विषय है। मुख्य मंत्री जी जो कहते हैं कि हम वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश देश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे। जब यह कल्पना करते हैं तो हमें आज तक यह समझ नहीं आया और न ही मुख्य मंत्री जी इसे स्पष्ट कर पाएं हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ले करके मुख्य मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। नियम-130 के अन्तर्गत यहां पर जो चर्चा माननीय सदन में करने का आज मौका मिला है, उसके लिए आपने अवसर दिया आपका धन्यवाद। लेकिन

यह विषय सही मायने में प्रदेश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जहां हम सत्र के इस समापन के अवसर पर चर्चा कर रहे हैं। इस विषय पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए थी और मुझे लगता है कि यह एक कमी रही है। अध्यक्ष महोदय आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय, आप क्या कहना चाह रहे हैं।

09.09.2024/1715/बी.एस./एच.के-2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की इस बात के लिए सहमत होगा कि 44.6 मिनट तक माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने बोला और किसी ने इन्हें टोका नहीं। जब टोका नहीं तो मेरा भी पिक्ष के नेता जी से अनुरोध रहेगा कि जब हम बोले तो बहिर्गमन न करें और इस वित्तीय स्थिति का व्याख्यान इन्होंने अच्छी तरह किया है, मैं इसमें और कुछ जोड़ूगा। इन्होंने खुद कहा है कि देखिए इतनी बुरी हालत है और हमने व्यवस्था परिवर्तन के तहत क्या किया है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम आपको दोषी ठहराते हैं, मैंने अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम तो कभी लिया ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि आप दोषी हैं। यह हम कहना चाहते हैं। मैं आज इस दोष वाली बात को जष्टिफाई नहीं करूंगा, मैं कल आंकड़ों के साथ आपको बताऊंगा। इन्होंने भी सहमति जाहिर की है कि हम कहां गलत हैं और कैसे बलत हैं। उस सहमति को भी हम कल आपके सामने रखेंगे। मैं इसलिए खड़ा हुआ कि आपने बीच में गुस्से नहीं होना और आराम से बैठे रहना है, बहिर्गमन करके नहीं जाना है।

अध्यक्ष : माननीय उद्योग मंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे।

09.09.2024/1715/बी.एस./एच.के-3

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने नियम-130 में बोलने के लिए मुझे मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय सदस्य भवानी सिंह पठानिया जी ने नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव रखा है। जिस पर आदरणीय विपक्ष के नेता ने बहुत विस्तृत बात कही है और इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डला है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातों से ये भी सहमत हैं कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति विकट है, प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है।

मगर प्रश्न यह है कि क्या यह वित्तीय स्थिति आज खराब हुई है? यह जो विकट वित्तीय स्थिति हमें मिली है, वह विरासत में मिली है और आपको भी विरासत में मिली थी। आप इस बात से इंकान नहीं कर सकते। जब वर्ष 2017 में आपकी सरकार बनी उस वक्त 48 हजार करोड़ रुपये के करीब प्रदेश के ऊपर कर्ज था। आपने इसे माना और जब आप वर्ष 2022 में इस प्रदेश को छोड़ करके गए तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश के ऊपर 76,500 करोड़ रुपये का कर्ज था और 11 हजार करोड़ रुपये के करीब सरकारी कर्मचारियों की देनदारियां हैं। जिसे आपने भी अपने भाषण में माना है। आपने अपने भाषण में कहा कि हमने जो लोन लिया है वह 44-45 प्रतिशत लोन लिया है। आपके आंकड़े क्या बोलते हैं, आपका जो लोन था, it is more than 60 percent. 76 हजार करोड़ में से अगर 48 हजार करोड़ रुपये निकाल ले तो कितना बनता है? 28 हजार करोड़ बनता है और इसका 50 प्रतिशत कितना हुए, 24 हजार करोड़। It is 28,000/- crore जो इन्होंने लोन लिया है। इनके अपने समय में लगभग 64-65 प्रतिशत लोन था और उसके आधार पर आपने लोन लिया है। अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति कैसे बनी? मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

09.09.2024/1720/DT/YK-1

उद्योग मंत्री जारी...जारी

...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय कुप्रबंधन पर चर्चा हो रही नियम-67 के तहत विपक्ष के सदस्य लाना चाह रहे थे। आज हालत यह है कि जब प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे थे, तो आधी सीटें इनके सदस्यों की खाली पड़ी हुई है, तो किस प्रकार से विपक्ष के सदस्य सीरियस और गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं।

अध्यक्षः माननीय मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022 में जाना चाहूंगा। वर्ष 2022 में चुनावी वर्ष था। चुनावी वर्ष में क्या हुआ इस पर में प्रकाश डालना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की

सरकार और श्री जय राम जी इतने डेसपरेट थे कि किस तरह से वह सत्ता को हासिल करें। उस वक्त इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति की चिंता उस समय के सरकार को नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात यह है कि इनके कार्यकाल के समय एक कार्यक्रम हुआ। स्वर्ण जयंती कार्यक्रम वर्ष 2022 में शुरू किया। हर चुनाव क्षेत्र में एक सरकार द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा और उसका बजट 50 लाख रुपए प्रति चुनाव क्षेत्र रखा। जिसमें जैसे तंबू, रोटी, टैंट और सरकारी बसें सब कुछ रखा। अध्यक्ष महोदय, 34 करोड़ रुपये इनके प्रचार और प्रसार पर सरकार का लगा। हर कार्यक्रम में 100-150 एच0आर0टी0सी0 की बसें लगी हुई थी। जब आपकी सरकार गई, एच0आर0टी0सी0 की 8 करोड़ रुपये की देनदारी उस वक्त सरकार के प्रति थी। जिन बसों को राजनीतिक कार्यक्रमों में आपकी सरकार ने इस्तेमाल किया। अध्यक्ष महोदय, चुनाव नजदीक थे, हिमाचल की जनता को फ्रीबीज कैसे दे दी जाए, महिलाओं को 50 प्रतिशत बस में किराया फ्री कर दिया सरकार के जाते-जाते इन्होंने। उसका एच0आर0टी0सी0 विभाग को कितना लॉस हुआ। यह आपको पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022 में भी मैं इस सदन का सदस्य था। इनकी सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात भी अंतिम वर्ष में की। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, संस्थान खोलने की जो होड़ पिछली सरकार के अंतिम वर्ष में थी उसका जब आंकड़ा देखा तो वह 900 संस्थान थे जो आखरी 6 महीने में खोले गए। अगर इनके आखिरी एक साल को जोड़ दिया जाए तो इनके समय में संस्थान जो खोलने की

09.09.2024/1720/DT/YK-2

होड़ थी वह कम से कम डेढ़ हजार संस्थान 1 साल में पिछली सरकार ने खोले। अध्यक्ष महोदय, हर सरकार संस्थान खोलती है। मुख्य मंत्री जब किसी भी चुनाव क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के लोग मांग करते हैं इन-इन संस्थानों को खोला जाए। माननीय मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी के विधान सभा में उपचुनाव हुआ तो जुबल में भी एस0डी0एम ऑफिस और कोटखाई में भी एसडीएम ऑफिस खोल दिया और चुनाव में जो परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार की जमानत ही जब्त हो गई। एक चुनाव क्षेत्र में एक एस0डी0एम का दफ्तर तो समझ आता है लेकिन हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे चुनाव क्षेत्रों में दो-दो एस0डी0एम के दफ्तर भी खोले गए हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी पूर्व सरकार ने दो

एस0डी0एम ऑफिस खोले। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मगर वह दफ्तर आपने जनता की सुविधा के लिए नहीं खोले थे। वह आपने मुझे हराने के लिए खोले थे कि कैसे हराया जाए। पिछली टर्म में श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, सी0एल0पी0 लीडर होते थे और मैं डिप्टी सी0एल0पी0 लीडर था। आपकी सरकार ने श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को हराने के लिए लिए बल्क ड्रग पार्क लगाओ और मुझे हराने के लिए हाटी लाया।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

09-09-2024/1725/वाई.के.-एन.जी/1

उद्योग मंत्री.....जारी

अध्यक्ष महोदय, इनकी इतनी डेस्पेरेशन थी कि सत्ता को कैसे हासिल किया जाए और कैसे मिशन रिपीट सफल हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत सारे चुनाव क्षेत्रों में देखा कि उस समय मुख्य मंत्री जी को किस प्रकार से चिटें दी जाती थीं कि ये स्कूल, पी.एच.सी., सी.एच.सी. या अस्पतलन खोल दो।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पूर्व सरकार ने जाते-जाते हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड के 34 दफ्तर खोल दिए। जिसमें एस.ई. का सर्कल ऑफिस, एक्स.ई.एन. और सब-डिविजन ऑफिस शामिल थे। पिछले 40 वर्ष में बिजली बोर्ड के केवल 4 दफ्तर खुले और वर्ष 2022 में 34 दफ्तर खुले। इससे आप इनकी डेस्पेरेशन का अंदाजा लगा सकते हो।...(व्यवधान) यह फैक्ट है। मैं बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार ने अपने अंतिम साल में पैट्रोल और डीज़ल के दाम कम कर दिए। इन्होंने डीज़ल पर वैट को 6 रुपये प्रति लीटर कम कर दिया क्योंकि चुनाव सामने था। इन्हें सरकार की वित्तीय स्थिति की चिंता नहीं थी। इन्होंने 6 रुपये प्रति लीटर वैट कम किया और उससे हिमाचल प्रदेश को लगभग 500-600 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ। इन्हें उस समय राजस्व की बिलकुल चिंता नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय, अभी जल शक्ति विभाग का जिक्र हो रहा था। जल शक्ति विभाग द्वारा प्राइवेट कनैक्शन के लिए 50 रुपये लिए जाते थे। इन्होंने चुनाव को नजदीक देखते हुए मई-2022 में उन 50 रुपये को भी लेना बंद कर दिया और उससे इन्होंने हिमाचल प्रदेश व जल शक्ति विभाग को 70-80 करोड़ रुपये का लॉस पहुंचाया।

अध्यक्ष महोदय, श्री जय राम ठाकुर जी यहां पर कर्मचारियों की बात कर रहे थे। छठे वेतन आयोग की सिफ़रिशें वर्ष 2021 में आई और यह सिफारिशें देरी से ही आती हैं।

09-09-2024/1725/वाई.के.-एन.जी/2

लेकिन हमेशा से जो भी सरकार रही है वह अपने कर्मचारियों को समय-समय पर आई.आर. (Interim Relief) देती रही है। लेकिन पूर्व सरकार ने तो कर्मचारियों को आई.आर. दिया ही नहीं था और छठे वेतन आयोग के भार को आगे शिफ्ट करती रही। इन्होंने वर्तमान सरकार पर कर्मचारियों की 11000 करोड़ रुपये की देनदारियां छोड़ दीं। इन्होंने कर्मचारियों को वर्ष 2021 और वर्ष 2022 का डी.ए. भी नहीं दिया।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

उपाध्यक्ष महोदय, श्री जय राम ठाकुर जी ने बहुत सारी सकारात्मक बातें भी कही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हिमाचल प्रदेश के हित में काम करेंगे। माननीय सदन में पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का विषय आया। आपने उसके लिए न 'हां' किया और न ही 'ना' कहा। इस वर्ष भी जब नियम-102 के तहत विषय आया तो माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी से उलझ कर भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल माननीय सदन से बाहर चला गया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल ठीक है कि हिमाचल प्रदेश वित्तीय संकट से गुजर रहा है। इसके लिए न आप (विपक्ष) दोषी हैं और न ही वर्तमान सरकार दोषी है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में राजस्व जनरेट करने के सोर्सिस बहुत कम हैं। हिमाचल प्रदेश को जब राज्य का दर्जा दिया गया था तब केन्द्र सरकार को पता था कि हिमाचल प्रदेश

कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। हिमाचल प्रदेश में आय के सीमित संसाधन हैं और भारत सरकार की ऐड पर भी हिमाचल प्रदेश चलता रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकार बोलती थी कि डबल इंजन की सरकार है। मैं जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को in terms of financial package, in terms of industrial package, in terms of relief package, वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक क्या मिला? मुझे नहीं लगता कि जो हमारा हक था,

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

09.09.2024/1730/केएस/एजी/1

उद्योग मंत्री जारी---

उससे बढ़कर हिमाचल प्रदेश को एक नया पैसा भी मिला हो।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी ये वित्तायोग का ज़िक्र कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत 15वें वित्तायोग की रिकमेंडेशन की वजह से खराब हुई है। मगर 15वें वित्तायोग को तथ्य और आंकड़े कौन सी सरकार ने दिए? यहां पर तो आपकी सरकार थी। आप हिमाचल प्रदेश का पक्ष नहीं रख पाए। मेरी कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी, हिमाचल प्रदेश के हित में सबसे बैस्ट रिकमेंडेशन 14वें वित्तायोग की थी। 13वें वित्तायोग ने हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क किया। 14वें वित्तायोग की रिकमेंडेशन सबसे बैस्ट थी। हमको 14वें वित्तायोग ने 40,624 करोड़ रुपये दिए और वह भी पांच वर्षों में लगभग 8-8 हजार और 7 हजार प्रति वर्ष एक जैसे दिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम तुलना करे, 14वें वित्तायोग में 40 हजार करोड़ रुपये की रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट थी और 15वें वित्तायोग में 38 हजार करोड़ की हमें मिली। वह पहले की तुलना में कम थी। हमारी स्थिति तो खराब ही होगी। अगर हम 13वें और 14वें वित्तायोग की तुलना करें तो 13वें वित्तायोग में हमें 7 हजार रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली जो कि पांच सालों में 7,889 करोड़ रुपये थी। 14वें वित्तायोग ने हमको दी 40,624 करोड़ और 15वें

वित्तायोग ने हमको 37,199 करोड़ दी...(व्यवधान) वह अलग बात है। यहां तो हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है और उस वक्त आप हिमाचल के मुख्य मंत्री थे। हमारी हालत तो खराब होनी ही है। आप हिमाचल की वर्तमान सरकार और मुख्य मंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी को अगर दोष दे रहे हो तो यह दोष नहीं है, यह वित्तीय कुप्रबंधन या और चीजें तो हमें विरासत में मिली हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमको जी.एस.टी. का नुकसान हुआ। मैं तो जी.एस.टी. काउंसिल में हिमाचल प्रदेश को रिप्रेज़ेंट करता हूं। वर्ष 2017 में जब जी.एस.टी. शुरू हुआ, काम्पन्सेट करने की भारत सरकार ने बात की, पांच साल के लिए लॉसिज़ काम्पन्सेट हुए। जून, 2022 में वह बंद हो गया। जो जी.एस.टी. का लॉस है वह हिमाचल प्रदेश को ढाई हज़ार करोड़ रुपये का है। ढाई हजार करोड़ रुपये का लॉस

09.09.2024/1730/केएस/एजी/2

जो आपको काम्पन्सेशन के रूप में मिलता था, इस वर्तमान सरकार को नहीं मिलता। तो वर्तमान सरकार की वित्तीय स्थिति तो ऑटोमेटिकली खराब होगी ही। भारत सरकार ने कहा था कि हर साल जी.एस.टी. की इन्क्रीज़ 14 परसेंट एक्सपैक्टिड थी मगर कुछ राज्यों में 14 परसेंट विशेषकर हिमाचल में वह नहीं आया। भारत सरकार को उन स्टेट्स को काम्पन्सेट करना चाहिए। नॉर्थ इस्ट की स्टेट हैं, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड के सम्बन्ध में जी.एस.टी. लॉसिज़ भारत सरकार को काम्पन्सेट करने चाहिए और हम चाहेंगे कि उसमें आपका भी सहयोग मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहुत सारे इशूज़ हैं। उनका जवाब मुख्य मंत्री जी देंगे। बी.बी.एन.बी. के हमारे एरियर्ज़ आज भी पैंडिंग पड़े हैं। आपके समय में भी पैंडिंग थे। कोर्ट में भी ठीक ढंग से पैरवी नहीं हो पाई। आपकी डबल इंजन की सरकार थी और उससे बेहतरीन मौका हिमाचल प्रदेश को कभी भी नहीं मिल सकता। जो इशूज़ हैं वे रिज़ॉल्व नहीं हुए। अभी आप एन.पी.एस. की बात कर रहे थे। न्यू पैंशन स्कीम में हमारे भारत सरकार के

पास 9,200 करोड़ रुपये हैं। हमने भारत सरकार से निवेदन किया कि वह हमारे पैसे वापिस दे।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जासरी---

09.09.2024/1735/av/ag/1

उद्योग मंत्री ---- जारी

आप कह रहे थे कि क्यों दे। वह इसलिए दे क्योंकि हिमाचल सरकार ने एन0पी0एस0 से ओ0पी0एस0 में स्विचओवर कर लिया है। वह हमारा पैसा है और केंद्र उस पैसे को हिमाचल प्रदेश सरकार को दे मगर केंद्र हमें वह पैसा नहीं दे रहा है। पी0डी0एन0ए0 की 9000 करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार के पास है मगर केंद्र हमें वह पैसा भी नहीं दे रहा है। माननीय श्री जय राम ठाकुर जी, अभी आप कह रहे थे कि भारत सरकार ने हमें पी0एम0जी0एस0वाई0, आपदा या अन्य किसी योजना के अंतर्गत पैसा दिया। लेकिन मैं यहां पर एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को जो दिया है वह हमारा हक़ है। पी0एम0जी0एस0वाई0 फ़ेज-॥ में क्या केवल हिमाचल प्रदेश को ही पैसा मिला दूसरे राज्यों को नहीं मिला? वह पैसा सबको मिला है। अभी आप मकानों का ज़िक्र कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हिन्दुस्तान के सभी 29 राज्यों में मकानों के लिए पैसा मिला है और जो पंचायतों, ब्लॉक्स इत्यादि ने मकान प्रपोज़ किए थे वे भारत सरकार ने हमें भी दिए और यह हमारा सवैंधानिक हक़ भी है। हिन्दुस्तान के 29 राज्यों में हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है। हम तो यह पूछ रहे हैं कि ओवर एण्ड एबव हिमाचल प्रदेश को क्या मिला? अभी केंद्र का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट था जिसको हिमाचल प्रदेश सहित सारा हिन्दुस्तान सुन रहा था। जब आपदा का ज़िक्र आया तो हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि स्पेशल एसिस्टेंस टू आसाम, सिक्किम एण्ड उत्तराखण्ड, उसमें हमारा नाम नहीं आया। उसमें कहा गया कि हिमाचल प्रदेश को मल्टीलेटरल असिस्टेंस दी जाएगी। राजनीति से संबंध रखने वाले लोग तो सारी बात समझ गए क्योंकि तीन राज्यों को डायरेक्ट एड दी गई। इसको भेदभाव नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? भारी बरसात के कारण जितना नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ वह हिन्दुस्तान

के किसी राज्य में नहीं हुआ। आप केंद्र की वकालत कर लो, आपको वह करनी पड़ेगी क्योंकि आप उसी राजनैतिक दल से हैं। मगर लोग जो सुनते और देखते हैं, हर व्यक्ति बात को समझता हैं, हम राजनैतिक लोग जो मर्जी पाठ पढ़ाएं। आपको और हमारे को जो-जो राजनैतिक भाषा सूट करेगी, हम लोग वही बोलेंगे। मगर

09.09.2024/1735/av/ag/2

हिन्दुस्तान की जनता सारी बात समझती है और कहते भी है कि ये पब्लिक है सब जानती है। इसलिए पब्लिक सब जानती है कि क्या हो रहा है।

इसके अतिरिक्त माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप यहां पर वॉटर सैस की बात कर रहे थे। यहां पर जब हमारी सरकार आई और मुख्य मंत्री जी ने वित्तीय स्थिति पर नज़र दौड़ाई तो देखा कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। फिर मुख्य मंत्री जी ने रिसोर्सिज मोबलाईज करने की बात की थी। यहां पर हम सबने विरोध किया। दिल्ली में हिमाचल भवन का किराया पहले विधायक, दूसरे नेता, जजिज और अधिकारी सौ रुपये देते थे जिसको मुख्य मंत्री जी ने बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया। हमारे पूरे विधायक दल ने उसका विरोध किया मगर इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति कैसे सुधरे, उसके लिए मुख्य मंत्री जी ने छोटे-छोटे कदम उठाए हैं। मुख्य मंत्री जी ने वॉटर सैस लगाने का निश्चय किया, ठीक है कोर्ट ने उसको बाद स्ट्रक डाउन कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का वॉटर सैस में क्या स्टेंड था। सब जानते हैं, आपके अनुराग ठाकुर जी ने संसद के अंदर और बाहर इसका विरोध किया। भारत सरकार ने हिमाचल सरकार को पत्र लिखा और कहा कि आप नहीं लगा सकते। मगर जब उत्तराखण्ड और जम्मू-कश्मीर ने लगाया तो केंद्र सरकार ने आंख और कान बंद कर लिए तथा इसके बारे में कुछ नहीं बोला। परंतु जब हिमाचल ने वॉटर सैस लगाया तो आप उसको इलीगल और अनकॉंस्टिच्यूशनल बोल रहे हैं। इस तरह के डबल यार्डस्टिक्स नहीं चलते और ये सबको समझ आते हैं।

आप बोलते हैं कि यह स्कूल बंद कर दिया, वह स्कूल बंद कर दिया लेकिन मैं शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। आप तो माननीय स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के समय में भी विरोध करते थे कि स्कूल रेवड़ियों की तरह बंट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक दौर था जब लोगों के द्वारा स्कूल खोलने की मांग की जाती थी। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में कुछ ऐसे स्कूल थे जिनमें दो-दो सौ बच्चे होते थे। मगर आज उनमें 20-20, 25-25 बच्चे रहे गए हैं।

टी सी द्वारा जारी

09.09.2024/1740/टी0सी0वी0/ए0एस0-1
उद्योग मंत्री .. जारी

आज स्कूलों को रेशनलाइज करने की जरूरत है, आज स्कूलों को बंद करने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री जी समेज स्कूल का जिक्र कर रहे थे, वहां पर 35-40 बच्चे और 9 मास्टर है। क्या हिमाचल प्रदेश सरकार मास्टरों की सुविधा के लिए स्कूल चलाएं या बच्चों की सुविधा के लिए स्कूल चलाएं? आज यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और यह समस्या आपके समय में भी आई थी। यह समस्या वर्तमान सरकार के सामने भी खड़ी है कि हमने जो इंफ्रास्ट्रेक्चर खड़ा किया है, स्वास्थ्य संस्थान, शिक्षा संस्थान और कॉलेजिज खोलकर रखे हैं, वे चाहे ठीक खोलें या गलत खोलें हैं मगर क्या उनको चलाने की हमारी वित्तीय स्थिति है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे बहुत-सारे हार्ड एरिया से हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से हैं। वहां चाहे कांग्रेस की सरकारें रही या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, श्री जय राम ठाकुर जी का विधान सभा क्षेत्र भी एक कठिन क्षेत्र है। स्कूलों में अध्यापक नहीं होते, अस्पतालों में डॉक्टर्ज नहीं होते, ऐसे स्कूल और अस्पताल हम क्या करेंगे जहां पर डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ और टीचर्ज न हों। हमें इस बारे में बैठकर गहराई से विचार करने की जरूरत है। आज हिमाचल प्रदेश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। आज हमें मिल-बैठकर इस विषय पर चिंतन करने की जरूरत है। हमें प्रायोरिटी फिक्स करने की जरूरत है। इस प्रदेश की क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए और वे प्रायोरिटीज चेंज ऑफ गवर्ननमेंट नहीं होनी चाहिए। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि राजनीतिक ओहदें बांटे जाते हैं लेकिन

राजनीतिक ओहदें तो हर सरकारों के समय में बांटें जाते हैं। यह तो पॉलिटिकल कंप्लशन है मगर आज हिमाचल प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, यह सबसे बड़ा प्रश्न है? इस कठिनाई के दौर में हम उम्मीद करेंगे कि श्री जय राम ठाकुर जी जो इस माननीय सदन के सबसे सीनियर विधायक हैं, आपने हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2017-2022 में कोरोना के दौर में भी निकाला है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हिमाचल प्रदेश का सहयोग करेंगे, सरकार को सलाह देंगे। अभी जैसे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र के इश्यूज को हमें मिलकर रिजॉल्व करना चाहिए ताकि केन्द्र से हमें फाइनेंशियल एड मिले। श्री भवानी सिंह पठानिया जी रिसोर्सिज मोबेलाइज करने का जिक्र कर रहे थे। मुख्य मंत्री जी ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को कहा कि इस बात का पता लगाया जाए रिसोर्सिज किस तरह से मोबेलाइज किए जाएं और पैसा कैसे

09.09.2024/1740/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

आएं? आप माइनिंग का जिक्र कर रहे थे, हमने अभी नई माइनिंग पॉलिसी लाई है और हमें उम्मीद हैं कि माइनिंग सेक्टर में डेढ़ से दो सौ करोड़ रुपया और जनरेट करेंगे। हाइड्रल प्रोजैक्ट में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह से पावर सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए? किस तरह से हिमाचल प्रदेश में इंवैस्टमेंट लाई जाए? उपाध्यक्ष महोदय, ये बहुत-सारे मुद्दे हैं जो चिंता का विषय है। हमारी वित्तीय स्थिति खराब नहीं है। हमारी कमिटिडी लायबिलिटीज हैं। महीने में 1200 करोड़ रुपये कर्मचारियों की सैलरी और 800 करोड़ रुपये पेंशनरों की पेंशन के दिए जाते हैं। इसके अलावा लोन के इंट्रस्ट की रि-पेमेंट बाकी है। अगर हम रिसोर्सिज मोबेलाइज नहीं करेंगे और अपने खर्चों में कटौती नहीं करेंगे तो हमारे पास विकास के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। यह एक चिंता का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं चाहूंगा कि विपक्ष की ओर से पॉजिटिव सजैशन्ज आएं। इस सरकार में त्रुटि भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है और कमियां भी हो सकती है। विपक्ष के नाते यह आपकी जिम्मेवारी है कि प्रदेशहित में हमारी गलती, त्रुटि, कमी बताएं। हम उनमें सुधार करने की कोशिश करेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर, सम्पन्न और खुशहाल हों। धन्यवाद। जयहिन्द, जय हिमाचल।

एन0एस0 द्वारा अगला वक्ता ।

09-09-2024/1745/एन0एस0-ए0एस0/1

उपाध्यक्ष : अब इस चर्चा में श्री विपिन सिंह परमार जी भाग लेंगे।

श्री विपिन सिंह परमार : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर बोलूं, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि कारगिल में जो ऑपरेशन विजय चला था उसमें हिमाचल के एक सपूत कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र विजेता शहीद हुए थे और आज उनकी जन्म जयंती है। मैं उनके चरणों में नमन और प्रणाम करता हूं कि ऐसे योद्धा वीर ने अपनी नौजवानी देश के लिए कुर्बान की। उनकी आत्मा को प्रभु के चरणों में स्थान मिले। उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत विस्तार से सारी बातें यहां आई हैं। श्री जय राम ठाकुर जी ने इस विषय पर बड़ी तथ्यात्मक जानकारी दी है। हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में आए हुए 53 वर्ष हो गए हैं। मैं देख सकता हूं कि डॉ0 वाई0एस0 परमार से लेकर बीच में जिन भी मुख्य मंत्रियों का कार्यकाल रहा उन्होंने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने की कोशिश की और उसमें वर्ष 2017 से 2022 के बीच में श्री जय राम ठाकुर जी को भी हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला और इन्होंने भी हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। आप भी कुछ उन नक्शे कदम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है। यहां के पहाड़, नदियां, नालों की सुंदरता यहां के ईमानदार व मेहनतकश लोगों के द्वारा बनती है। परंतु इन 18 महीनों में हिमाचल प्रदेश पर पहाड़ जैसा 94,000 करोड़ रुपये का कर्ज और इसमें लगभग 18 महीनों में 22,000 करोड़ रुपये का लोन लिया गया है। यानी हर हिमाचली के ऊपर 1.17 लाख रुपये का कर्ज है। जो बच्चा पैदा होगा तो उसके ऊपर पैदा होते ही 1.17 लाख रुपये का कर्ज होगा। मैं हिमाचल प्रदेश की आर्थिक प्रति व्यक्ति की आय को देख रहा था। पूरे हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हिमाचल प्रदेश चौथे स्थान पर है। प्रति व्यक्ति ऋण बहुत ज्यादा हो गया है। अब जो व्यक्ति पैदा होगा तो क्या उसका नाम ऋणी राम रखा जाए। कभी तो धनी राम, धनवान, धनंजय हुआ करता था परंतु यह बदलाव कैसे आ गया? प्रदेश में आपकी सरकार बनी और हमने मुख्य मंत्री जी को बहुत बार सुना कि आर्थिक अव्यवस्था हो गई। श्री जय राम ठाकुर जी ने

बिजली मुफ्त दे दी, पानी मुफ्त दे दिया और अनगिनत संस्थान खोल दिए। हम चुप रहे और अपनी आवाज को शालीनता के साथ उठाते रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि 18 महीनों में आपने 900 संस्थान सरकार बनने के बाद रद्द किए,

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

09.09.2024/1750/rks/dc-1

श्री विपिन सिंह परमार...जारी

आपने जो 125 यूनिट फ्री बिजली देने की सुविधा बंद की उससे कितने आर्थिक संसधान जनरेट हुए? जो कमी है क्या आप उस कमी को पूरा कर पाएंगे? अपना कल्याण हो जाए तब तो ठीक है लेकिन जब समाज के कल्याण की बात हो तो यह कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट आ गया है। आपने हिमकेयर योजना बंद कर दी। मुझे वर्ष 2017-22 की याद आ रही है। हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के इलाज के लिए 385 करोड़ रुपये खर्च किए लेकिन जब आपकी सरकार आई तो आपने हिमकेयर योजना बंद कर दी। आप जो आर्थिक कुप्रबंधन के बारे में बार-बार जिक्र कर रहे हैं, शायद इस महत्वकांक्षी जनकल्याणकारी योजना को बंद करके आप अपने खजाने को भरना चाहते हैं। इस सरकार पर मेरा यह इल्जाम है कि आपने इस महत्वकांक्षी योजना को बंद किया है। आज आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि हमने निजी अस्पतालों के कुछ पैसे जारी कर दिए हैं। आपने कहा कि हम सरकारी अस्पतालों के पैसे जारी कर रहे हैं। आप जो कुप्रबंधन के बारे में बार-बार इस सदन के माध्यम से बातों को रखना चाहते हैं यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आपने शगुन योजना बंद कर दी। यह योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। लड़कियों की शादी के लिए जो 31000 रुपये का प्रावधान किया गया था वह आपको भारी लगने लगा। हमने अपने मन को पसोझा कि आप आर्थिक प्रबंधन कर रहे होंगे। मुझे याद है जब हमारी हुकुमत थी तो 45 करोड़ रुपये का बजट शगुन योजना के लिए रखा जाता था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने इस योजना को बंद करके कितने साधन जनरेट किए हैं? हमने गृहणी सुविधा योजना चलाई थी। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जो धुआंमुक्त है। हमने हिमाचल प्रदेश की लगभग तीन लाख से ज्यादा महिलाओं को 175 करोड़ रुपये इस

योजना में जारी किए थे ताकि हमारी बहनें धुआंमुक्त चूल्हा जलाएं। उनको गैस कनैक्शन वितरित किए गए लेकिन आपने इस योजना को भी बंद कर दिया। नारी को नमन योजना पर भी काले बादल मंडराए हुए हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पर हमारी बहनों के साथ धोखा किया जा रहा है। एच.आर.टी.सी. की बसिज में हर दिन 1,25,000 बहनें सफर करती हैं। हमारी सरकार अपने खजाने से 60 हजार करोड़ रुपये एच.आर.टी.सी. को देती थी। आज भी यह चल रहा है लेकिन खबरें यह आ रही है नारी को नमन पसंद नहीं आ रहा है। आप कौन-सी दुनिया में जी रहे हैं?

09.09.2024/1750/rks/dc-2

जो जनहित की योजनाएं थीं आप उन्हें बंद कर रहे हैं। बेटी है अनमोल योजना के तहत जिन परिवारों में दो बेटियां थीं उन्हें 21,000 रुपये देने का प्रावधान श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने किया था। जब बेटियां 18, 19 या 20 साल की होती थी तो यह पैसा उनकी पढ़ाई के लिए दिया जाता था। लेकिन आपने इस योजना को भी बंद कर दिया है। आपने पुनर्विवाह व अंतर्जातीय योजनाएं भी बंद कर दी हैं। आपकी अपनी योजनाएं तो खूब फल-फूल रही हैं। आपके लिए कोई कानून नहीं है।

श्री बी.एस. द्वारा ... जारी

09.09.2024/1755/बी.एस./डी.सी-1

श्री विपिन सिंह परमार जारी...

हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जो जन-जन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उपाध्यक्ष महोदय, ये सहारा योजना बंद हो गई। आठ जो घातक बीमारियां हैं चाहे वह Muscular Dystrophy हैं, चाहे वह chronic renal failure हैं, चाहे वह बोडी पूरी तरह से ineffective हो गई है, चाहे वह केंसर की बीमारी है, Parkinson's की बीमारी है, उनकी जांच कर रहे हैं। जब हम बी.एम.ओ. और सी.एम.ओ. से कहते हैं तो वे कहते हैं कि जांच हो रही है। गरीब जनता के हकों पर डाका मत डालो। जिसका कोई सहारा नहीं था, उसका सहारा वर्ष 2017-22 के बीच में भाजपा और श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार थी। अब अगर आपने तमाम इन योजनाओं को अपने संसाधन जनरेट करने के लिए खड़ा कर दिया तो यह बहुत

दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसे इस रूप में लेता हूं कि अपने खर्चे कुछ कम कर दीजिए और अगर आप खर्चे कम करेंगे तो मुझ यह लगता है कि ये योजनाएं भी चलेंगी। आपने अभी आर.बी.आई. में एक अर्जी लगा दी है, क्योंकि दिसम्बर के बाद सैलरी और पेंशन देने के लिए आपके खजाने में पैसा नहीं है। आपने 700 करोड़ रुपये की अर्जी लगा दी है। जहां आप जी.पी.एफ. के अंगेस्ट लोन ले सकते थे, वह आपने ले लिया है। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि अब तो मंदिरों के सोने और चांदी पर नजर टिक गई है। जिन श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा से देवी के चरणों में मनत पूरी होने पर वह सोना और चांदी चढ़ाया होगा अब तो उसका भी हिसाब-किताब लिया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर जिस प्रकार की अव्यवस्था खराब हुई है, उसके लिए आप लोग जिम्मेवार हैं। मेरा एक प्रश्न लगा था, उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की तमाम पंचायतों से 24 हजार रुपये कौशल विकास निधि में जमा करवाए गए। परंतु हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को भी नहीं बख्शा गया और कोरोना के समय स्वावलम्बन योजना हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए शुरू हुई थी कि 60 लाख रुपये तक आप अपना उद्योग चला सकते हैं, उसे भी बंद कर दिया गया। यानी ये सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कुछ सुख देने के बजाय अपनी सुख की संभावनाओं को तलाश रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह बात यहां पर रखना चाहता हूं और आयुष्मान योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि आपने तो ओवर एंड अबब खर्चा कर दिया है। फिर यहां से मुख्य मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि भारत सरकार पैसा नहीं भेज रही है। अरे, भई जो आपका राइट था उसे तो पूरा करते।

09.09.2024/1755/बी.एस./डी.सी-2

90/10 में जो पैसा आपको भेजना चाहिए था उसे तो भेजते? यहां पर कहा जा रहा है कि हिमकेयर में बहुत धांधली हुई है। जिन निजी अस्पतालों में धांधली हुई है आप छानबीन शुरू करें। आपकी सरकार है आप छानबीन शुरू करवाइए। परंतु आम आदमी इस योजना के लाभ से छूट न जाए, मैं यह निवेदन आपसे करना चाहता हूं। आखिर यह अव्यवस्था बनी कैसे? सत्ता में आने के लिए बड़े-बड़े वायदे हो गए और कल तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि नहीं,

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

09.09.2024/1800/डी0टी0/एच0के0-1

श्री विपिन सिंह परमार जारी

अब परिवार में जितनी भी महिलायें हैं उनको पेंशन नहीं लगेगी अब तो केवल परिवार की एक ही महिला को पेंशन लगेगी। इस पेंशन के लिए सम्मानीय स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के नाम से जो फार्म भरे गये थे अब वे फार्म संबंधित पंचायतों में वापिस आ गये। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पूर्व कहा कि वर्ष में ग्राम सभा की दो बैठके होती हैं और इन ग्राम सभाओं की बैठकों में इन महिलाओं के नाम पारित होंगे और उसके बाद पेंशन लगाई जायेगी। हिमाचल प्रदेश की 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को अगर पेंशन लगानी है तो लगभग 5000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। आपने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा था कि प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अगर आप इस वायदे को धरातल में उतारते हैं तो उसके लिए 2500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। वर्तमान सरकार ने नौजवानों का तो गला ही घोंट दिया है। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अब आउट सोर्स के सहारे चलने वाला है। यहां पर पैट स्कैन की बात हो रही है, यूरोलोजी विभाग की बात हो रही है, यहां पर अन्य सर्जरी की बात भी की जा रही है, गुर्दा प्रत्यारोपण की बात हो रही है, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? जनता के साथ खिलवाड़ मत करो। आप ये धन्धा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आउट सोर्स पर नौकरी देंगे तो उसमें न तो पूरा वेतन देंगे और न ही पूरे लाभ देंगे न रिटायरमेंट की कोई लायबिलिटि होगी, ये सारी बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सत्ता में आने के लिए आपके द्वारा जितने वायदे किए गये थे वो आज आपके गले की फांस बने हुए हैं। हो सकता है कि वर्ष 2022 में जो कांग्रेस पार्टी की मेनिफेस्टों कमेटी के सदस्य होंगे वह इस सदन में नहीं हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी शायद अभियान समिति में होंगे, और मेनिफेस्टो कमेटी के सदस्यों में कहा होगा की जनसभाओं में ये वायदे कर दो। ये भी बोल दो की सरकार गोबर 2 रुपये किलो खरीद लेगी़, ये भी बोल दो कि दूध 100 रुपये खरीदेंगे। एक वर्ष् में 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे ऐसी घोषणा कर दो। अरे भाई वायदा तो कर लो पर आज हिमाचल प्रदेश बहुत बड़े आर्थिक संकट में है। इसके अतिरिक्त ये जो खटाखट की बात इनके राष्ट्रीय नेता करते हैं, ये क्या बिमारी है? इनके राष्ट्रीय नेता यहां आकर कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार ले आओ और जब कांग्रेस की सरकार आयेगी तो हिमाचल और हिंदुस्तान की बहनों के खाते में 8500 रुपया खटाखट आ जायेंगे। खटाखट कैसे आयेंगे क्योंकि यहां तो प्रदेश सरकार

का खजाना ही सफाचट हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की सत्ता की प्राप्ति के लिए जो नेता या जो विचारधारा ऐसी बाते करती हैं, वो ठीक नहीं होता। मैं बैठ-बैठे हिसाब

09.09.2024/1800/डी0टी0/एच0के0-2

कर रह था कि मान लो अगर 100 रुपये का बजट है तो विकास के लिए सिर्फ 28 रुपये ही बच रहे हैं। जो मुफ्त देने के बारे में घोषणायें की गईं हैं उनका क्या होगा क्योंकि विकास के लिए सिर्फ 28 रुपये हैं। आप वायदे जितने बड़े-बड़े कर लो, खुले हुए संस्थान बंद कर दो, उससे कुछ नहीं होगा। 100 रुपये में 25 रुपये सरकार को वेतन में खर्च करने पड़ते हैं, इन्ही 100 रुपये में 17 रुपये पेंशन के रुप में खर्च होते हैं। इसके अतिरिक्त 11 रुपये सरकार को ब्याज के भुगतान के लिए देने पड़ते हैं और 9 रुपये सरकार को कर्ज चुकाने के लिए देने पड़ते हैं और 10 रुपये सरकार को अनुदान के लिए खर्च करने पड़ते हैं। तो इन 100 में 28 रुपये की जो 10 गारंटियां वर्तमान सरकार ने दी है वह गांरटियां कभी पूरी नहीं होंगी। प्रदेश की बात तो मैं नहीं करूंगा पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो विकासात्मक कार्य चले हुए थे वे ठप पड़ गये हैं। उसमें चाहे हमारे स्वास्थ्य संस्थान थे, चाहे वह इंजनीयरिंग कॉलेज था चाहे वह स्कूल के भवनों के कार्य थे। आप लोग कृषि विश्वविद्यालय की भूमि को गैरों के हाथों में बेचना चाहते हैं लेकिन हम उसे नहीं बिकने देंगे। अगर यहां पर उसी प्रकार का कोई नाच-गाने का बहुत बड़ा कुछ बनाना है तो उसे कहीं ओर बनाओ, पर कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश की जमीन पर आपके सपनों को उन विदेशी लोगों के हाथो नहीं बिकने देंगे, ये हमारी सोच है। हमारे कृषि मंत्री महोदय को बहुत अनुभव है। हम इनके बच्चों के समान हैं।

एन0जी0 द्वारा जीर...

09-09-2024/1805/एच.के.-एन.जी/1

श्री विपिन सिंह परमार.....जारी

मंत्री जी ने ठीक कहा और लोगों को अच्छा भी लगा। हम आलोचना के लिए आलोचना नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया वाइंडअप कीजिए। अभी 18 और माननीय सदस्यों ने बोलना है।

श्री विपिन सिंह परमार : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथियों ने 35-40 मिनट बोला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि यह 22000 करोड़ रुपये का लोन कहां पर लगा है? क्या कर्मचारियों के डी.ए. पर लगा, नहीं लगा तो कहां गया? क्या सड़कों पर लगा, नहीं लगा तो कहां गया? क्या यह गारंटियों को पूरा करने पर लगा, नहीं लगा तो कहां गया? क्या विकास कार्यों पर लगा, नहीं लगा तो ये लोन कहां गया? यह हमारे प्रश्न हैं और हम इन्हें इस माननीय सदन में पूछना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा ज्ञान बांटने से पहले अपने से त्याग करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि मुख्य मंत्री जी, उप मुख्य मंत्री जी और मंत्रियों को एस्कोर्ट व पायलट वाहन दिए जाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं बहुत जल्दी पहुंचना होता है। लेकिन कई जगहों पर तो चुने हुए नुमाइंदों ने इसे अपना स्टेटस सिम्बल मान लिया है। पुलिस के भाई कहते हैं कि हम क्या करें क्योंकि सरकार का दबाव है। एक तरफ कहते हैं कि खनन माफिया ने हिमाचल को लूट लिया और एक तरफ कहते हैं कि बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में स्क्रैप के माफिया ने हमें कंगाल कर दिया। यानि कानून व्यवस्था को ठीक करने वाले तो कहीं और लगे हुए हैं। इस माननीय सदन में हम कहते हैं कि वन माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया व चिट्टा माफिया प्रदेश में आ चुका है। थानों में जो स्ट्रैंथ है वह वर्ष 1980 की स्ट्रैंथ है।

09-09-2024/1805/एच.के.-एन.जी/2

पूर्व में स्व0 श्री वीरभद्र सिंह जी ने अस्थाई चौकियां खोली थीं और हमारी पूर्व सरकार में हमने श्री जय राम ठाकुर जी से निवेदन किया कि इन सभी चौकियों को रेगुलर कर दीजिए। मेरे क्षेत्र में भवारना के ठाने से कुछ कॉंस्टेबल साथी धीड़ा व थूरल जाते हैं। आज सरकार इन बातों पर कोई विचार नहीं कर रही है और कह रही है कि दिल्ली वालों की

हम पर नज़र-ए-इनायत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके ऊपर नज़र-ए-इनायत क्यों नहीं है? मैं बताना चाहता हूं कि नज़र-ए-इनायत बहुत ज्यादा हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार हमें बहुत कुछ देती है। यदि माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सितारमण जी ने कुछ घोषणा की है और उनके शब्द कुछ भी हों तो उसके अनुसार अधिकतर राशि भारत सरकार ही देगी। मैं बताना चाहता हूं कि 80 प्रतिशत से ज्यादा राशि भारत सरकार देगी। इसके अलावा बाइलेट्रल का प्रोपोशन आपकी सरकार को देना होगा। मेरा कहना है कि मुख्य मंत्री जी केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से मिलकर आएं और उनसे बातचीत करें। केन्द्र सरकार ने 1727 करोड़ रुपये प्राकृतिक आपदा के समय दिया था और वह पैसा भी पूरा खर्च नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम कि नीति आयोग की बैठक में मुख्य मंत्री जी क्यों नहीं गए। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में एन.एच.ए.आई. के माध्यम से रोड्स बन रहे हैं, क्या वे हिमाचल प्रदेश का हिस्सा नहीं हैं? क्या वे हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट नहीं कर रहे हैं? पठानकोट से मण्डी के लिए फोरलेन का निर्माण हो रहा है और उस पर 10670 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। इसी प्रकार मटौर से शिमला फोरलेन पर 10512 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

09.09.2024/1810/केएस/वाईके/1

श्री विपिन सिंह परमार जारी---

पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ के लिए 1,692 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। परवाणू-सोलन-कैथलीघाट-शिमला के लिए 7,632 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। ये तमाम काम चले हुए हैं और जब प्रधान मंत्री जी कारगिल के शहीदों को नमन करने के लिए, याद करने के लिए लद्दाख गए थे, तो अब तो हिमाचल प्रदेश का लाहौल-स्पिति जिला, लाहौल सीधा लद्दाख

और लेह के साथ जुड़ रहा है। ये बातें क्या हमारे दिमाग से निकल रही हैं? लगभग 15 हजार फीट के ऊपर चार किलोमीटर लम्बी टनल के लिए 1,681 करोड़ रुपया भारत सरकार हिमाचल प्रदेश को दे रही है जिसकी शुरूआत लद्दाख से हो चुकी है। उपाध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश में रेलवे की बहुत सम्भावनाएं हैं। जो शेयर हिमाचल प्रदेश को जमा करवाना होगा, वह आप करवाएं परंतु 2,698 करोड़ रुपये इस बजट में रेलवे एक्सपेंशन के लिए भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिए हैं। हम यह कहें कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश के प्रति उदासीन है तो वह उदासीन नहीं है। देश के प्रधान मंत्री हिमाचल प्रदेश की आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए जहां-जहां ज़रूरत पड़ी है, हमारी मददकी है वह चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट की बात हो, चाहे यहां पर 94 हजार मकान बनाने की बात हो, चाहे यहां पर जल शक्ति विभाग के माध्यम से योजनाओं की बात हो। आपके समर्थकों के घरों में भी प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि से पैसा आता है। वे सभी हमारे ही लोग नहीं हैं। आयुष्मान से अगर 160 करोड़ का इलाज हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वे सभी हमारे ही लोग हैं। हिम केयर से अगर इलाज हुआ है, इस सरकार ने 400 करोड़ रुपये खर्च किए, आपकी देनदारियां हैं। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में स्वैप किया है तो इन्क्वायरी बिठाएं कि किस अस्पताल के कर्मचारियों के नाम से ही पैसे निकाल लिए। लटकाइए उनको, समाज के सामने उनको खड़ा कर दीजिए। पद से बड़ा व्यक्ति नहीं होता परंतु बेईमानी करने वाला व्यक्ति अगर बड़ी जगह पर बैठा है तो उपाध्यक्ष महोदय, उसका निर्णय तो आपको लेना है परंतु गुनहगार सामान्य जनता नहीं होनी चाहिए। सहारा योजना से लोग वंचित क्यों हो जाए? मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हीमोफीलिया जैसी बीमारियों के लिए आप कुछ और सहायता बढ़ाते। तीन से पांच हजार रुपये कर देते। आपने तो सुखाश्रय की बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। सहारा सुखाश्रय योजना उसका नाम रख देते तो हमें अच्छा लगता। हिम केयर के आगे आप सुखाश्रय करके कोई नाम रख लेते।

09.09.2024/1810/केएस/वाईके/2

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री विपिन सिंह परमार : उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें मैं आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं कि थोड़ी सी कटौती करनी पड़ेगी। अपना लाव-लश्कर छोड़ना पड़ेगा और अगर

दफ्तरों के फर्निचर कहीं दूर से आ रहे हैं, तो उसको बंद करना पड़ेगा और चमकने वाले बल्व भी अगर बड़ी दूर से आ रहे हैं तो उन आदेशों को भी रोकना होगा। जनता को ठेंगा, मित्रों का पूरा सेवा पानी, यह तोड़ना पड़ेगा। नए-नए शब्द जैसे विलंबित है, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने रणधीर शर्मा जी से और जय राम जी से पूछा कि यह विलंबित क्या होता है? इन्होंने भी डिक्शनरी खोली, इन्होंने कहा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। बाद में इन्होंने कहा कि विलंबित का मतलब यह है कि कुछ समय के लिए विलम्ब। मैंने पूछा कि उसके बाद टी.ए.,डी.ए. और वेतन सब लेंगे? इन्होंने कहा कि क्यों नहीं लेंगे। आप यह क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

09.09.2024/1815/av/वाईके/1

श्री विपिन सिंह परमार क्रमागत

कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिली और पेंशनर्ज को तो अभी तक भी पेंशन नहीं मिली है। टी0ए0डी0ए0 मिलना तो दूर की बात है, ...(व्यवधान) हम आपके साथ हैं मगर आप अपनी मंशा तो ठीक रखिए। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि जब भी प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो सेपू बड़ी की बात करते हैं। सेपू बड़ी जिला मण्डी की स्पेशल डिश है। अगर वे टारना मंदिर की बात करते हैं तो उससे आपके पेट में मरोड़ क्यों पड़ते हैं? अगर वे यहां के चिन्तपुरनी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, चामुण्डा माता मंदिर, पिताम्बरा माता के मंदिर का ज़िक्र करते हैं या हिमाचल प्रदेश के पुराने-से-पुराने लोगों का ज़िक्र करते हैं या वे यहां के लोगों को नाम के द्वारा जानते हैं, तो अच्छी बात है। इस प्रकार के व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री है। उस कुर्सी पर बैठकर प्रस्ताव पारित करने के माध्यम से आपको राशि मिलेगी, यह तो सम्भव हो सकता है पर संबंध माकूल होने चाहिए। यहां पर कहा गया कि हमारे मुख्य मंत्री जी रात्रि भोज में शामिल हुए, अच्छी बात है। मुख्य मंत्री जी, आप जी-20 के उस कार्यक्रम में गए तो उन्होंने भी आपको अपनी छाती से लगाया, गरमाहट तो आपको भी महसूस हुई होगी। ...(घंटी) मैं तो यह कह रहा हूं कि

प्रधानमंत्री जी की मुख्य मंत्री जी के प्रति सोच क्या है। मैं इनके प्रति उनकी तारीफ कर रहा हूं। ...(घंटी) आप जिस पार्टी से जीतकर आए, अच्छी बात है। परंतु अब जिसकी सरकार बनी है तो सरकारों की पार्टियां नहीं होती, मिलते रहिए और आते रहिए तथा अपनी समस्याओं का इज़हार करते रहिए। लेकिन दिल्ली में चाल कुछ और होती है तथा शिमला पहुंचते-पहुंचते खबर कुछ बन जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि चाल और खबर एक जैसी रहनी चाहिए नहीं तो संदेश तुरंत पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए अपने संसाधनों को और ज्यादा निखारने की जरूरत है। आप शायद इसके लिए लड़ भी रहे होंगे। आप भाखड़ा ब्यास के लाखों-करोड़ों रुपये के एरियर को लेने की बात रख भी रहे होंगे। शानन हाईडल प्रोजैक्ट से मिलने वाला हमारा हक़ और वह प्रोजैक्ट हमें मिले, उसके लिए आप अच्छे वकील भी खड़े कर रहे होंगे। हम केवल आलोचना के लिए आपकी आलोचना नहीं करना चाहते परंतु हिमाचल प्रदेश का चेहरा पूरे देश में कुछ इस प्रकार से चला गया कि हम करज़ाई हो गए। उसके लिए कृपा करके हम ऐसे वक्तव्य न दें, हम आपसे यह निवेदन करना

09.09.2024/1815/av/वाईके/2

चाहते हैं और हम आपके साथ सकारात्मक सुझावों को लेकर चलेंगे। आपने कहा कि जब हमने यह कहा कि हमें एक पैकेज मिलना चाहिए तो विपक्ष वाले वॉकआउट करके चले गए। अभी मंत्री जी यहां पर नहीं बैठे हैं। वे श्री जय राम ठाकुर जी पर इतने आग-बबूला हो गए जबकि इन्होंने (श्री जय राम ठाकुर) तो अपनी बात में कहा है कि हम आपके साथ हैं। इसलिए बड़ा मन रखने की जरूरत आपको है। आज जिस आर्थिक संकट से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, निःसंदेह हमारी छवि बहुत कमजोर हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका आभार।

09.09.2024/1815/av/वाईके/3

उपाध्यक्ष : माननीय उप-मुख्य मंत्री जी, आप बोलिए।

उप-मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात माननीय सदन में पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं और अब मैं उसको दोबारा से स्पष्ट करना चाहता हूं।

ठीक है, हमारे प्रतिपक्ष के साथी धर्म का एजेंडा चलाते रहे हैं। धार्मिक भावनाओं के साथ किस ढंग से प्ले करना है, वह हो सकता है लेकिन हमने जब यह स्पष्ट कर दिया है इस देव भूमि में किसी भी मंदिर का सोना-चांदी न तो गिरवी रखा जा रहा है और न ही बेचा जा रहा है तो कृपया आप इस बारे में प्रदेश में सनसनी फैलाने की कोशिश मत कीजिए। यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने यह मसला उठाया था और हमने उस समय स्पष्ट कर दिया था।

टी सी द्वारा जारी

09.09.2024/1820/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

उप मुख्य मंत्री ..... जारी

यह ठीक है कि हमारे देवी-देवता अमीर हैं और उनके पास माकूल मात्रा में सोना और चांदी है। हमने उसको सुरक्षित रखने के लिए वहां पर बटालियन्ज भी लगा रखी हैं लेकिन विपक्ष की यह सूचना बिल्कुल गलत है कि मंदिरों का सोना बेचा जा रहा है, ऐसा कतई नहीं है।

दूसरा, आपने कहा कि एच0आर0टी0सी0 महिलाओं का मुफ्त सफर बंद किया जा रहा है लेकिन यह विषय किसी भी स्तर पर डिसकस नहीं किया गया है। यहां पर कहा गया कि पहले सरकार एच0आर0टी0सी0 को वेतन और पेंशन के लिए 60 करोड़ रुपये देती थी। वह सरकार अब भी दे रही है, वह कहीं भी बंद नहीं हुआ है। हमने इस महीने कर्मचारियों को सैलरी भी दी है और पेंशन भी दी है, यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

श्री विपिन सिंह परमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्दों में अपनी बात रखना चाहता हूं कि कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के ऊपर बहुत संकट मंडरा रहा है, इसको भी इसमें इन्क्लूड किया जाए क्योंकि वन-टाइम सैटलमेंट जो मार्च में खत्म हो गई थी, नियमों का उल्लंघन करने के बाद आर0सी0एस0 ने फाइलों पर साइन नहीं किए और वहां के जो

अधिकारी हैं उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बाईपास करने के बाद इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। जब से यह योजना शुरू हुई थी, 184 करोड़ रुपया ओ0टी0एस0 से गया है। इससे हमारा एन0पी0 इससे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इस पर आप जरूर गौर करें यानी रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटी ने मंजूरी नहीं दी है और वहां पर तीन अधिकारी यह कह रहे हैं, आप कहेंगे कि राजनीतिक बात कर रहा हूं। कृपा करके आप आदेश दें वरना यह 100 साल पुराना बैंक जिसमें 13 हजारा करोड़ रुपये की जमा पूंजी हैं। 5-6 जिलों का यह बैंक है, इसमें आप भी और हम भी सदस्य हैं। लोक सभा के चुनाव के समय बड़ा मुद्दा उठा था कि करोड़ों रुपये के होटल, साढ़े तीन करोड़ रुपया अगर किसी का ओ0टी0एस0 में माफ हो जाए, इसमें एक नहीं दर्जनों होंगे। मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे बात की थी कि ऐसे लोगों की सूची सार्वजनिक कीजिए जिन्होंने जमीन कहीं पर बताई, यह विभाग मुख्य मंत्री जी के पास है। जहां पर सम्पत्ति प्लज की और करोड़ों रुपया ले लिया और एक रुपये का भी भुगतान नहीं हो रहा है। कृपया करके इस विषय को भी इसमें इंडोरस कर लेना। मैं भूल गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

09.09.2024/1820/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिप्लाई में सारी बातों का जवाब दूंगा लेकिन जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात कही गई है उसके बारे में मैंने पिछले कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं। सदन में बार-बार यह विषय उठाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहां 10 हजार कनाल जगह है जिसमें साढ़े सात हजार जगह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास है। अढ़ाई हजार कनाल जगह हमने टूरिज्म विभाग के नाम से ली है। आपने कहा कि वहां पर डांस करने या नाचने वाले आ रहे हैं लेकिन वहां पर कोई भी डांस करने वाले नहीं आ रहे हैं। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यदि आपने वीडियो चलाना होगा तो चलाते रहना, वह अच्छा चलेगा लेकिन इन बातों को आप रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए।

दूसरा, इन्होंने कहा कि लाइट्स लग रही है, फर्नीचर बाहर से आ रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी कार्य हो रहा है वह सरकार का हो रहा है। यह किसी की निजी सम्पत्ति नहीं है। मुझे नहीं पता कि ऐसी बातें करके क्यों राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। जब किसी का ऑफिस बनता है तो वह सरकारी ऑफिस है, वह

किसी व्यक्ति का ऑफिस नहीं है। उसमें बैठने वाला चाहे मंत्री हो या चाहे कोई और हो वह सरकार का मंत्री है, सरकार का कर्मचारी है। वह उनको घर लेकर नहीं जाते हैं।

एन0एस0 द्वारा जारी ।

09-09-2024/1825/एन0एस0-ए0जी0/1

मुख्य मंत्री -----जारी

आपको पता है जब सरकारें हटती हैं तो कुछ भी सामान घर लेकर नहीं जाते हैं। कोई ऐसी महंगी चीज़ नहीं लगाई जा रही है। यहां कहा जा रहा कि पता नहीं कहां से आ रहा है? ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि पता नहीं कहां से आ रहा है? ऐसा कोई सामान बाहर से नहीं आ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि बार-बार ऐसी बात उठा कर इसका कोई राजनैतिक लाभ नहीं होता लेकिन लोग सोचते हैं कि क्या सच में ऐसा है? जबकि सच में ऐसा होता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसको रिकॉर्ड से निकाला जाए। मैं यही कहना चाहता हूं। आपने कहा कि 18,000 रुपये की लाइट आ रही है। ऐसा अच्छा नहीं लगता लेकिन आपको सच्चाई तो बोलनी चाहिए। आपको सच्चाई बोलनी चाहिए कि 18,000 रुपये की लाइट कहां से आ रही है, फर्नीचर कहां से आ रहा है? आप बोलिए कि मेरे पास 18,000 रुपये के बिल हैं। यह not to be recorded होना चाहिए।

श्री विपिन सिंह परमार : उपाध्यक्ष महोदय, अब अखबारों में आ रहा है कि सरकारी गाड़ियों में कौन घूम रहे हैं, बच्चों को कौन ला रहा है? मैंने कोई अपशब्द नहीं कहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि इन शब्दों को रिकॉर्ड से न निकाला जाए। हम मुख्य मंत्री जी का सम्मान करता हूं। ये हमारे सम्माननीय हैं।

उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइए। आप मुख्य मंत्री जी को बोलने दो फिर आप बोल लेना। आप बैठिए।

मुख्य मंत्री : देखिए, मैं बोल रहा हूं और आप बीच में उठ गए। सत्ता पक्ष के विधायक आपकी बात को कितनी शांति से सुन रहे हैं। अभी तो कल नेगी जी और अन्य विधायकों ने बोलना है। अभी तो हमारे काफी खिलाड़ी बोलने वाले हैं। आपके बाद काफी लोग बोलेंगे और उसके बाद मैंने भी बोलना है। मेरा कहने का मतलब है कि किसी अधिकारी के पास सरकारी गाड़ी है और उसमें किसी को ला रहे हैं तो आपके पास उसके फैक्ट्स होने चाहिए जिनको आप हाउस ऑफ दि टेबल में ले करें। ऐसी बातें कहना कि घूम रहे हैं और

अखबार में खबरें आ रही हैं। मैं आपको अखबार की खबरों के बारे में कहना चाहता हूं कि आजकल अखबार की खबरें भी सत्य पर आधारित नहीं हैं। अगर है, तो उसे आप यहां पर ले करें। हम देखेंगे कि उसमें आगे क्या करना है? ऐसी बातें कहना आपके लिए भी उचित नहीं हैं और हमारे लिए भी उचित नहीं हैं। जो चीज़ हो ही नहीं रही है, उनको कहना नहीं चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

09-09-2024/1825/एन0एस0-ए0जी0/2

उपाध्यक्ष : श्री विपिन सिंह परमार जी आप बोलिए।

श्री विपिन सिंह परमार : उपाध्यक्ष महोदय, आप इतने रिजिड नहीं हैं। मैंने कोई असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया। ये सूचनाएं हमारे लोकतंत्र के मजबूत प्रहरी अखबारों से प्राप्त होती हैं और इन्हीं के कारण हमारी बात पूरी दुनिया में पहुंचती है। हम क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? हम यहां कोई वीडियो बनाने के लिए नहीं आए हैं जिसके लिए आप कह रहे हैं कि आप वीडियो डाल दीजिए। हमारा वीडियो तो लोगों के दिलों में हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन शब्दों को डिलीट नहीं किया जाए और जो खबरों पर आधारित है कि गाड़ियां किनके बच्चों को ढोहती हैं तो मैं अखबार प्रस्तुत कर दूंगा और उपाध्यक्ष महोदय, आप भी उसको पढ़ लेना।

मुख्य मंत्री : परमार जी ने जो शब्द कहे हैं अगर ये उसका प्रमाण हाउस में ले करते हैं तब तो ठीक है अन्यथा उन शब्दों को डिलीट किया जाए। आप जो फर्नीचर के बारे में कह रहे हैं तो उसका बिल लाएं, हवा में बात न करें। मेरा यह मानना है कि इस सदन की अपनी गरिमा है। धन्यवाद।

09-09-2024/1825/एन0एस0-ए0जी0/3

उपाध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर जी भाग लेंगे।

श्री चंद्र शेखर : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री भवानी सिंह पठानिया जी ने 'प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर यह सदन विचार करे।', इस पर चर्चा लाई है। नेता प्रतिपक्ष, उद्योग मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी ने अपनी

बात यहां पर रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के सत्ता में आने के बाद पीड़ादायक करने का माहौल इस प्रदेश में बनाया गया, वह निरंतर जारी है।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

09.09.2024/1830/rks/AS-1

श्री चंद्र शेखर....जारी

हम यह सोचते थे कि आम-आदमी मुख्य मंत्री बनता है, उदाहरण के तौर पर श्री जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री बने और उसी तर्ज पर श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी भी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बने। माननीय मुख्य मंत्री जी और इस सदन में बैठे हुए बहुत से सदस्य छात्र राजनीति से निकले हैं। ...(व्यवधान) परमार जी मैं आपका छोटा भाई हूं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। कृपया बोलने में भी थोड़ा मान-सम्मान बना रहे तो मुझे ठीक लगेगा। पिछले तीन दिनों में जो राष्ट्रीय चैनलों पर माहौल बनाया गया उसमें स्थितियां राजनीतिक पहलू के तौर पर ज्यादा प्रस्तुत हुई। यह कहा गया कि यह प्रदेश दिवालिया होने जा रहा है और विपक्ष के लोग इसी लकीर को खिंचते हुए गवर्नर हाउस पहुंच गए। आर्थिक मुद्दे को चर्चा का केंद्र बिन्दू बनाया गया। प्रतिपक्ष के नेता राष्ट्रीय चैनल पर आए और यह बताया गया कि हमारा प्रदेश फाइनेंशियल इमरजेंसी की ओर बढ़ रहा है। राजनीतिक तौर पर हिमाचल प्रदेश का सफर सन् 1948 से शुरू हुआ है। सन् 1971 के बाद हमारे राज्य को अस्तित्व में आए हुए 53 साल हो चुके हैं। डॉ0 वाई.एस.परमार से लेकर स्वर्गीय श्री राम लाल ठाकुर, श्री शांता कुमार, स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, श्री जय राम ठाकुर और श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू तक यह सफर जारी रहा है। स्थितियां बदली और आज हमारे प्रदेश में एक जुझारू मुख्य मंत्री आए हैं जिन्होंने इस बात को समझ लिया कि जिस ढर्रे पर सरकारें इस प्रदेश को आगे ले जा रही हैं उस ढर्रे पर हम लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। जो कुप्रबंधन का ढर्रा बना उसमें इन्होंने अपने आप माना कि हमने पिछली सरकार के समय 29-30 हजार करोड़ रुपये का लोन लिया है। इंवेस्टर

मीट भी हुई। जब इस विधान सभा का दूसरा सत्र आया तो उप-मुख्य मंत्री जी ने श्वेत-पत्र लाया। वह श्वेत-पत्र आर्थिक तौर पर लाया गया था लेकिन इन्होंने उस श्वेत-पत्र को मानने से भी इनकार कर दिया। प्रदेश मे अभूतपूर्व आपदा आई। इस प्रदेश में 600 व्यक्तियों ने अपनी जान गवाई और करीब 9 हजार लोगों के मकान भी इस आपदा में गिरे। इस प्रदेश में बहुत आर्थिक संकट आया। इन समस्याओं से उबारने के लिए मुख्य मंत्री जी ने अपनी दृढ़ता दिखाते हुए प्रदेश को 45 सौ करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज जारी किया। इस दौरान हमारे विपक्ष को प्रदेश की जनता के साथ खड़े होने का एक मौका था लेकिन ये लोग इस मौके से चूक गए। जब सदन में यह प्रस्ताव लाया कि केंद्र से

09.09.2024/1830/rks/AS-2

आर्थिक पैकेज लाने में आप हमारी मदद कीजिए, आपने उस प्रस्ताव के साथ खड़ा होना उचित नहीं समझा। इस बार जब फिर से यह सदन कह रहा था कि आर्थिक संकट आया और उसके बाद एक और आपदा आई तो सामने वाले लोगों से जो राजनीतिक आपदा पैदा हुई, उस आपदा में विशेष तौर पर अपने माननीय विधायकों को कस्टोडियन की तरह हरियाणा व उत्तरांचल सरकार तथा केंद्रीय एजेंसियों की मदद करने का आरोप है। अभी पता चला है कि. पूर्व में रहे विधायकों के साथ जो सी.आर.पी.एफ लगाई है वह अभी हटी नहीं है। वे चाहते हैं कि सी.आर.पी.एफ. हट जाए क्योंकि इसका खर्चा पड़ रहा है लेकिन वे बराबर उनके पीछे चल रहे हैं।

श्री बी.एस. द्वारा ... जारी

09.09.2024/1835/बी.एस./ए.एस-1

श्री चंद्र शेखर जारी...

इस प्रदेश के अंदर राजनीतिक मंशा ऐसी बनाई गई, पहले राजनीतिक संकट लाया जाए, उसके बाद आर्थिक संकट की तरफ इस प्रदेश को बताया जाए। राष्ट्रीय टी.वी. चैलन किसी अन्य प्रदेश के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। वे चैनल अंबानी जी की भाषा बोलते हैं और अडानी जी की भाषा बोलते हैं। हैरानी इस चीज की हुई कि इस प्रदेश का सेब अडानी

कहां-से-कहां ले गया? सीमेंट को कहां-से-कहां ले गया? उसके ऊपर आज तक कभी भी कोई राजीनतिक वक्तव्य नहीं आया। ये देश आज बड़े पूंजीपतियों का बन चुका है, जिसे भारतीय जनता पार्टी प्रमाणिक तौर पर पूरा साथ भी देती है और उनका पक्ष मजबूती के साथ रखती है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां कुप्रबंधन की बात आई, प्रदेश ऐसा मानता है कि बेरोजगारों के साथ न्याय होना चाहिए, कर्मचारियों के साथ न्याय होना चाहिए और किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। क्या माननीय जय राम ठाकुर जी की सरकार में इनके साथ न्याय हो रहा था? अभी तक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो अब राज्य चयन आयोग में बदला है। वहां के14 मुकदमें दर्ज हा चुके हैं। वे 14 मुकदमें किसी और के लिए नहीं थे वे बेरोजगार जो अपनी कलम पुस्तकालयों में, विश्वविद्यालयों में, स्कूलों और कॉलेजों में चलाना सीखते हैं और नौकरी पाने तक संघर्ष करते हैं, वह संघर्ष कर रहा था और इनके समय में जूझ रहा था। चाहे पुलिस की भर्ती थी, चाहे जे.ओ.आई.टी. की भर्ती थी। चार-चार सालों तक ये नौजवान और बेरोजगार जूझते रहे। हमारे प्रतिपक्ष के नेता उस वक्त में जिस वक्त में ओ.पी.एस. की डिमांड चल रही थी, कर्मचारी मांग कर रहे थे यह पूर्ण हो सकती थी। राष्ट्रीय आका इंकार कर रहे थे, उसी पैट्रन को इन्हें भी फोलो करना था। इसलिए उनके ऊपर घोड़े भी चलते थे और उनके ऊपर पानी की बौछारे भी चलती थीं। ये बराबर रहा और प्रदेश के अंदर यह महौल बना कि माननीय जय राम जी की सरकार को जाना पड़ा। क्या हमारे सामने वाले नेता इस बात का कभी जवाब दे पाएंगे कि जो इन्वेस्टर मीट जो हुई, इस प्रदेश को उस मीट से कितना रेवेन्यू आया, कितना निजी क्षेत्र में बेरोजगारी का आंकड़ा खत्म हुआ और इसमें कितना रोजगार का आंकड़ा जुड़ा? बड़े-बड़े पावर प्रोजैक्ट्स के ऊपर समझौते हुए। जिसके ऊपर परसों भी चर्चा आई थी और उसमें इन बातों को नजर अंदाज किया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी इस वक्त पूरी ताकत के साथ हिमाचली हितों को

केन्द्र बिन्दु बनाते हुए हिमाचल को हिमाचलियत के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। उसका एक बड़ा नतिजा आज हमारे सामने है कि केन्द्र के साथ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर टकराव की स्थिति बनाए बिना बार-बार एक बात कह रहे हैं कि आप दिल्ली चलिए और

हिमाचल प्रदेश की वकालत करिए। ये पहले मुख्य मंत्री नहीं हैं, राजनीतिक तौर पर स्थितियां बदली हैं। मुझे याद है हम बहुत छोटे थे, प्रदेश के अन्दर पंडित शांता कुमार जी की सरकार थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जो आज इनकी है। जिस दिल्ली के वकील बन करके हमारे विपक्ष के साथी पूरी वकालत करते हैं। जिसका राजनीतिक ग्राफ इस बार ऐतिहासिक तौर पर नीचे गिरा है। जिस राजनीति को रेखांकित करने की कोशिश पिछले चुनाव और इस चुनाव के बीच में आया है वह इस बार बड़ा फासला देखने में आ चुका है। दिल्ली की सरकार कमजोर पड़ी है और घुटने टेक रही है, चाहे बिहार के आगे, चाहे आंध्र प्रदेश के आगे और चाहे आसाम के आगे। हमें जो मल्टीलेट्रल सोर्सिज से पैसा लाने की वकाल हो रही है, वह बजट में दिख रहा है कि हमारी मदद करने की मंशा नहीं है। लेकिन इनको सरकार को बचान है और प्रदेश की जनता को दिखा रहे हैं कि नहीं-नहीं हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, यह बात पंडित शांता कुमार जी ने तब कही जब दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी। आज ठीक उलटा हो रहा है। आज हमारे मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली चलो और वहां पैसा लाते हैं। जो हमारा हिमाचल प्रदेश का हक बनता है, पी.डी.एन.ए. का हमारा नौ हजार करोड़ रुपये हक बनता है,

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

09.09.2024/1840/डीटी/डीसी-1

श्री चंद्र शेखर ....जारी

एन.पी.एस. के पैसे के बारे में श्री जय राम ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या है? यह हमारे कर्मचारियों के पुरषार्थ से पैसा इकट्ठा हुआ है अगर यह हिमाचल में आता है तो इसमें बुराई क्या है? आज सैलरी और पेंशन के ऊपर बात हो रही है यह पिछली सरकार के कुप्रबंधन की वजह से हुआ है। यह फोकल प्वाइंट तभी बना है। श्री शांता कुमार जी कहते थे कि कोई दिल्ली गया नहीं और हिमाचल का हक किसने मांगा नहीं, रॉयल्टी मिली नहीं और यह बात आपकी तरफ से पिछले 30 साल पहले बोली है। आज आप अपने पक्ष को रिवर्स करके हिमाचल की जनता को बताना चाहते हैं कि दिल्ली इतनी मेहरबान है। क्या

मेहरबान है? दिल्ली सरकार पूरा बजट सेंट्रलाइज्ड कर चुकी है। राज्यों को घुटनों के बल खड़ा कर दिया गया है। उनकी मर्सी के ऊपर प्रदेश की वित्तीय स्थितियों को छोड़ दिया गया है। हमारा जी.एस.टी. का पैसा ड्यू है। जो 2800 या 3000 करोड़ रुपये है वे हमें मिलने चाहिए लेकिन इसको कहने वाला दोषी है। उत्तरांचल के अंदर जो आपदा आई है वह नाम की है। उनको 800-900 करोड़ रुपये का बड़ा बजट दिया गया है। बिहार के लिए बड़ा पैकेज रिफलैक्ट हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में स्कूल व सड़कें नहीं थीं। ये सामने वाले उन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं, उन्हीं अस्पतालों में इलाज करवाया है जिन्हें पीछे की कांग्रेस सरकारों ने बनवाया है। हिमाचल प्रदेश को हमने इस आधार पर कभी नहीं बांटा कि राजनीतिक चश्मे से देखा जाए। जिन स्कूलों व कॉलेजों से सामने वाले पढ़कर आए हैं वे आज केंद्रीय भूमिका को राजनीतिक भाषा से परिभाषित कर रहे हैं। यह दुःख की बात है। मुख्य मंत्री जी हिमाचलियत के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हिमाचलियत का माइना है। हम अपने सोर्स को मजबूत करें। हम अपने आपको स्वाबलंबी बनाएं। हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएं इसमें गलत क्या है? यहबहुत पहले सोचा जाना चाहिए लेकिन इस पर नहीं सोचा गया। पन बिजली योजना, पर्यटन , आद्योगिक इकाइयां, इन तीनों क्षेत्रों में फूंक-फूंक कर आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे पास बेराजगारी का कोई जवाब नहीं है। गांव-गांव में अनके समस्याएं हैं। कर्मचारियों व पेंशनर्ज की सैलरी व पेंशन के अलावा हमारे पास और भी बहुत सी चुनौतियां हैं। हम सब चुनकर यहां आए हैं। हमारी गांव की सड़क व रास्ते पक्के होने चाहिए, पुलियां बननी चाहिए और सोलर लाइट लगनी चाहिए। सिंचाई व मल निकासी योजनाएं

09.09.2024/1840/डीटी/डीसी-2

बननी चाहिएं। गांव के स्तर पर सभागार होने चाहिए। स्वरोजगार के हेतू सब्सिडी होनी चाहिए। गांव मे बिजली बेहतर होनी चाहिए। लेकिन इसको हमें कैसे सुधार पाएंगे? आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता नहीं है कि जो कुप्रबंधन पहले हुआ उसे हम रोक पाएं। अगर मनरेगा योजना यू.पी.ए. की सरकार नहीं लाती तो क्या हम मनरेगा के बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में सोच सकते हैं। इस पहाड़ी राज्य में अगर मनरेगा जैसी योजनाएं न हो तो लोगों के पास कोई रोजगार का साधन नहीं है। यह हमारी सरकारों के

द्वारा काम हुआ है। मुझे खुशी है कि वर्तमान केंद्रीय सरकार भी इस योजना को गति दे रही है लेकिन यह गति ऐसी नहीं है जो होनी चाहिए थी। हमारे पास आज भी बहुत सी चुनौतियां हैं। जिस हिसाब से सामने से बात आई है, मुख्य मंत्री जी जोखिम उठाने के आदि हैं। वे हर क्षेत्र में जोखिम उठा रहे हैं। उनमें इस बात की हिम्मत है। केंद्र सरकार की मदद के बिना इन्होंने 45 सौ करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने के बारे में सोचा है। विधवाओं के मकान के लिए 3 लाख रुपये देने की बात कोई मुख्य मंत्री नहीं सोच सकता। आज सोलर योजना पर मुख्य मंत्री अग्रेसिवली आगे जाना चाहते हैं।

श्री एन.जी. द्वारा ... जारी

09-09-2024/1845/डी.सी.-एन.जी/1

श्री चंद्र शेखर.....जारी

और उसके ऊपर कोई नहीं सोचता। केन्द्र सरकार भी इन योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहता है। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए टैक्सियों की बात हो रही है। मुझे बहुत लम्बी बात नहीं कहनी है लेकिन कुछ बातों को जरूर अंडर लाइन करना है। पिछली सरकार में जब श्री जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री हुआ करते थे तो सरकार में हर स्तर पर वापिसी करना चाहते थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी पुरजोर कोशिश की गई कि सत्ता में कैसे वापिस आया जाए? मैं बेरोजगारी का हिसाब बताना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिना किसी आरक्षण और बिना साक्षात्कार के, केवल सत्ता में वापिसी करने के लिए 1500-1600 नौजवान, एक ही पार्टी के काडर को रख लिया। हिमाचल प्रदेश के किसी भी विधान सभा क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ है। मेरे जिला के 9 अन्य विधायक मेरे सामने बैठे हैं, कुछ पहले भी रहे हैं तथा कुछ मेरी तरह नए विधायक हैं और किसी के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। पिछली सरकार में कोई एक शब्द भी नहीं बोलता था और न ही कोई आवाज़ उठाता था। दुःख इस बात का है कि वे नौजवान 12 साल के लिए केवल 5500 रुपये मसिक सैलरी पर रख लिए गए हैं। 12 साल के बाद उनमें से केवल 10 प्रतिशत नौजवानों को अनुबंध पर लिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में

इनकी संख्या 35 से 40 हज़ार हो। क्या यह बेरोजगारी से बाहर निकलने का फार्मुला था? क्या भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व इस विषय पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करेगा? हम हिमाचल प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं?

मैं इस माननीय सदन में बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री, श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी ने अपने 20 माह के कार्यकाल में 22000 नौकरियां दी हैं। जिसमें टी.जी.टी., पी.जी.टी. व जे.ओ.ए.(आई.टी.) शामिल हैं। हमारी सरकार ने हर स्तर पर नौकरियों का प्रबंध किया गया है। जल्दी ही राज्य चयन आयोग अपना कार्य करना शुरू कर देगा।

09-09-2024/1845/डी.सी.-एन.जी/2

अभी भी पी.जी.टी., टी.जी.टी. पी.ई.टी., एन.टी.टी. व आई.टी.आई. जिसमें लाइनमैन इत्यादि को भी नौकरियां देने की बहुत सारी सम्भावनाएं हैं। आपने जो विकास का धर्मपुर मॉडल लाया था, क्या वह आपका वित्तीय प्रबंधन है? आज धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपये पुरानी योजनाओं व पुराने भवनों को पूर्ण करने में लग रहा है और अभी 150 करोड़ रुपये और चाहिएं। हम कब अपनी योजनाओं के ऊपर काम करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, यहीं से पूर्व सरकार के वित्तीय कूप्रबंधन का पता चल रहा है। लगभग 300 करोड़ रुपये केवल मात्र पुरानी योजनाओं के भवनों को पूर्ण करने के लिए चाहिएं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि वर्ष 2010 में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक 12 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बनी थी जिसमें प्रदेश का पहला ड्राइविंग स्कूल बनाया गया था। उस स्कूल में आज तक एक भी आदमी ने पांव नहीं रखा। उस भवन के दरवाजे-खिड़कियां भी खराब हो चुके हैं। 12 करोड़ रुपये के भवन का आज तक कोई भी उपयोग नहीं हो पाया। मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारी जनता का पैसा है। प्रदेश का एक-एक पैसा प्रदेश के कर्मचारियों व मजदूरों की मेहनत से निकलता है। आज जितनी फिक्र प्रदेश के

कर्मचारियों को लेकर कर रहे हैं उतनी ही फिक्र निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की भी होनी चाहिए। चाहे वह होटल इंडस्ट्री में काम करता हो और चाहे वह उद्योगों/फैक्ट्रियों में काम करता हो, वह भी इस प्रदेश के लिए उतना ही श्रम कर रहा है जितना एक सरकारी कर्मचारी करता है। हमें यह भी देखना होगा कि उस मजदूर व उस कर्मचारी के ऊपर जो लेबर लॉज़ लागू होने चाहिएं, वे लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

09.09.2024/1850/केएस/एचके/1

श्री चंद्र शेखर जारी---

कहीं इन सब बातों में, प्रबंधन करने के चक्र में जो इकोनॉमी के पीछे मानवीय दृष्टिकोण रहता है, जो एक मानवीय चर्चा, मानवीय संवेदनाएं किसी इकोनॉमी को चलाती बार कल्याणकारी राज्य के अंदर मौजूद रहनी चाहिए, उसका अभाव हो रहा है। पूर्व मुख्य मंत्री जी ने यहां पर लम्बे-लम्बे आंकड़े दिए लेकिन जो आज प्रदेश की स्थितियां बनी हैं, उनसे प्रदेश की जनता आहत हुई है। न केवल प्रदेश बल्कि प्रदेश से बाहर जो हमारे बच्चे, हमारे नौजवान पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर फैले हैं, राष्ट्रीय मिडिया के अंदर एक तस्वीर बनाने की हमारे विपक्ष के साथियों ने बहुत मदद की है। ऐसा लग रहा है जैसे भारी वित्तीय संकट इस प्रदेश के अंदर आ गया है और हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, हम यह कहना चाहते हैं कि जिस मज़बूत रीढ़ के स्वामी हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, मुझे भरोसा है, हम आपदा से बाहर निकल रहे हैं। इस प्रदेश की आम आवाज के तौर पर प्रदेश के मुखिया ने आज इस प्रदेश को आगे ले जाने का बीड़ा उठाया है और मैं विपक्ष के साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि हिमाचलियत को बचाएं। इसको मात्र राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल न करें। हम हिमाचली हैं। जो इस वक्त पूरे देश के अंदर हमारे ऊपर बट्टा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पहले राजनीतिक संकट, उसके बाद वित्तीय संकट, हम तो इन्हीं संकटों में फंसे हुए रह जाएंगे। मैं अपने नेतृत्व के ऊपर पूरा विश्वास करता हूं कि जो आज इस प्रदेश के अंदर परिस्थितियां पैदा हुई हैं, निश्चित तौर पर यह संकट का समय नहीं है लेकिन आगे बढ़ने का समय ज़रूर है और मैं प्रदेश के

अधिकारियों व कर्मचारियों से भी गुज़ारिश करुंगा कि हमें इकठ्ठा मिलकर कदम से कदम बढ़ाना है और मैं सामने वाले सभी माननीयों से भी गुज़ारिश करुंगा कि जिस तरह से ये माननीय मुख्य मंत्री जी से अकेले में आ कर अपने कागज पकड़ा कर जाते हैं और बड़े प्यार से बात करके जाते हैं, अपने काम करवाते हैं, थोड़ा सा मान-सम्मान प्रदेश से बाहर भी दिखना चाहिए। ...(व्यवधान) कोई बात नहीं। हम जनता के लिए हैं लेकिन वह तस्वीर प्रदेश से बाहर भी जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रदेश के मुद्दे पर कहीं न कहीं इकट्ठा हैं। आप और हम दो मुंहें नज़र नहीं आने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

09.09.2024/1850/केएस/एचके/2

श्री जय राम ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जो विधायकों के बारे में बोला गया, रिकॉर्ड में शब्द आए हैं कि विधायक आते हैं, कागज पकड़ाते हैं, अपने काम करवाते हैं। विधायक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और अगर हम मुख्य मंत्री के पास नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? जन-प्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र के मसलों को ले कर अगर सरकार को विपक्ष वालों ने भी लिखकर दिया तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। ये शब्द इस प्रकार से रिकॉर्ड में नहीं आने चाहिए। यह टिप्पणी मुझे ठीक नहीं लगी।

09.09.2024/1850/केएस/एचके/3

उपाध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री आशीष शर्मा जी भाग लेंगे।

श्री आशीष शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर आए प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। इस सम्बन्ध में मुझसे पहले नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य साथियों ने भी अपना पक्ष रखा, उद्योग मंत्री जी ने भी वक्तव्य रखा कि जो विधायक हैं, विपक्ष की भूमिका निभाएं और पॉज़िटिव सजैशन्ज़ भी दें। अगर कोई त्रुटियां हैं तो वे भी सरकार के समक्ष रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी कड़ी में चर्चा में भाग ले रहा हूं ताकि मैं भी सरकार को कुछ सजैशन्ज़ दे सकूं। आदरणीय उद्योग मंत्री जी ने कहा कि मुख्य मंत्री जी छोटी-छोटी चीजों की भी बचत कर रहे हैं जिससे आर्थिक स्थिति ट्रैक पर आए और पैसा ढंग से मैनेज हो पाए। यहां पर माननीय उप-मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं। आपके माध्यम से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूंगा कि पिछली बार भी मैंने विधान सभा में यह प्रश्न लगाया था लेकिन मुझे उसका ठीक ढंग से उत्तर नहीं दिया गया था कि हमारे आई.पी.एच. और पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के जितने भी टेंडर होते हैं, उनकी अर्नेस्ट मनी जो कि सिक्योरिटी डिपोज़िट है और

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

09.09.2024/1855/av/hk/1

श्री आशीष शर्मा---- जारी

वह करोड़ों रुपये में आता है। वह पैसा दो महीने से लेकर छह महीने तक बैंक में पड़ा रहता है जिसके ऊपर न तो ठेकेदार को ब्याज मिलता है और न ही सरकार को ब्याज मिलता है। मैंने उस समय भी यह बात रखी थी कि यह करोड़ों रुपये की राशि केवल आई0सी0आई0सी0 बैंक में जा रही है और वे उस पर ब्याज खा रहे हैं। अगर यही पैसा हमारे कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में भी जाए तो मैं समझता हूं कि उसके एन0पी0ए0 में लाभ मिलेगा और उसकी स्थिति ठीक होगी क्योंकि इस पर बहुत सारा ब्याज मिलता है। सौ करोड़ रुपये, दो सौ करोड़ रुपये यानी जितने भी ऑनलाइन टैण्डर लगते हैं, लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग का वह सारा-का-सारा पैसा जो ठेकेदारों से एफ0डी0आर0 के रूप में जमा होता है वह आई0सी0आई0सी0 बैंक में जाता है। यहां पर आपदा के दौरान प्रदेश की जनता ने दिल खोलकर दान दिया था और सरकार ने अढ़ाई-तीन सौ करोड़ रुपये की राशि का आंकड़ा प्रस्तुत किया था कि इतना पैसा आया है। माननीय मुख्य मंत्री जी लोगों के साथ मिलते रहे और चैक के साथ उनकी फेसबुक पर फोटो भी आती रही। उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने भी अपनी सैलरी आपदा के लिए डोनेट की थी। मैं भी विधायक हूं और उस समय मेरे निर्वाचन क्षेत्र में

जितना भी नुकसान हुआ तो मैंने भी पैसा बांटा था। मैं जब राजनीति में आया था तो मैंने संकल्प लिया था कि जब तक राजनीति में हूं एक भी पैसा नहीं लूंगा। मैं टी0ए0/डी0ए0 का सारा पैसा अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता की सेवा में लगाता हूं। (***)

09.09.2024/1855/av/hk/2

(***) अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

टी सी द्वारा जारी

09.09.2024/1900/टी.सी/वाई.के-1

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन का समय हो गया है। आप बोलने के लिए और कितना समय लेंगे?

श्री आशीष शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पांच मिनट और चाहिए।

उपाध्यक्ष : अगर माननीय सदन की अनुमति हो तो माननीय सदन का समय 10 मिनट और बढ़ाया जाए।

(माननीय सदन का समय 07.10 बजे तक बढ़ाया गया)

श्री आशीष शर्मा : (***)

09.09.2024/1900/टी.सी.वी./वाई.के-2

(***)

(***) अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

09.09.2024/1900/टी.सी/वाई.के-3

आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिमाचल, जय श्री राम।

उपाध्यक्ष :.....एन.एस. शुरू ...

09-09-2024/1905/एन0एस0-वाई0के0/1

उपाध्यक्ष : उप-मुख्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं।

उप-मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पानी की स्कीम की बात की है और कहा है कि सरकारी कोष से पैसा दिया गया। ठीक है, जिस जमीन की इन्होंने बात की है तो उसका कोर्ट केस था। कोर्ट केस में फैसला आया और उसके मुताबिक पैसा दिया गया है। मुख्य मंत्री जी अभी तक उस जमीन को वापिस मांग रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह उनके काम की जमीन थी और डिपार्टमेंट ने हासिल कर ली। जो भी हुआ है तो वह अदालत के फैसले पर हुआ है और श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार के समय में हुआ है। जब कोर्ट केस हुआ और अदालत का फैसला आया तब पैसा तो देना ही है। उन्होंने अदालत में लड़ाई लड़ी और कोई भी हिमाचल का नागरिक अदालत में लड़ाई लड़ता है तो हमें उसके मुताबिक एक्ट तो करना होगा।

उपाध्यक्ष : श्री बिक्रम सिंह जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री बिक्रम सिंह : (***)

(***) अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

उपाध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 10 सितम्बर, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा**
दिनांकः 09 सितम्बर, 2024 **सचिव।**